



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1748]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2010/भाद्र 1, 1932

No. 1748]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2010/BHADRA 1, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

सं. 1 (आर ई 2010)/2009-2014

का.आ. 2065(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुलग्नक में निहित 23 अगस्त, 2010 को अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 को, एतद्वारा अधिसूचित करती है। यह नीति 23 अगस्त, 2010 से प्रभावी होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/विदेश व्यापार नीति/ए एम-11/पीसी-4]

पी. के. चौधरी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

अनुलग्नक

विदेश व्यापार नीति

27 अगस्त, 2009 - 31 मार्च, 2014

(23-8-2010 से प्रभावी)

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णाक्षर
एसीसी	सीमाशुल्क सहायक आयुक्त
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
एईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरओ	अग्रिम रिलीज आर्डर
एसआईडी	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
सीबीईसी	उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएस	स्वतन्त्र राज्यों का कॉमनवैल्थ
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीवीडी	कार्गु टरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीसी	विकास आयुक्त
डीईपीबी	शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र
डीएफआरसी	शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओई	इलेक्ट्रॉनिक विभाग
डीओआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	पर्यटन विभाग

डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडीआई	इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईएच	निर्यात सदन
ईएचटीपी	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद्
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफआईआईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफएमएस	फोकस मार्केट स्कीम
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीएस	फोकस उत्पाद स्कीम
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी वी1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)
एचबीपी वी2	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (तालमेल प्रणाली) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण, 2004-2009
आईटीपीओ	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	अधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल

एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
पीआरसी	नीति छूट समिति
पीटीएच	प्रीमियर व्यापार सदन
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएससीक्यू सी	गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप समिति
एसबी	पोत लदान बिल
एसईएच	स्टार निर्यात सदन
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स कंपाबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	भारत से सेवित स्कीम
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीईई	टाऊनस ऑफ एक्पोर्ट एक्सेलेस
टीएच	व्यापार सदन
टीआरए	टेलिग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	टैरिफ रेट कोटा
वीए	मूल्य संवर्धन
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
डब्ल्यू एचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माण प्रणाली

अध्याय - 1 क

विधिक ढाँचा

- प्रस्तावना** 1.1 प्रस्तावना में वृहत ढाँचे को इंगित किया गया है।
- अवधि** 1.2 यह विदेश व्यापार नीति 2009-2014, जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, 27 अगस्त, 2009 से लागू तथा 31 मार्च, 2014 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए। 26 अगस्त, 2009 तक के निर्यात तथा आयात विदेश व्यापार नीति 2004-2009 द्वारा तदनुसार शासित होंगे।
23 अगस्त, 2010 को अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए विदेश व्यापार नीति, 2009-2014, 23 अगस्त, 2010 को प्रभावी होगी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।
- संशोधन** 1.3 केंद्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इस नीति में अधिसूचना द्वारा संशोधन का अधिकार रखती है।
- अन्तर्वर्ती व्यवस्था** 1.4 इस नीति से पूर्व जारी किए गए प्राधिकार पत्र उस उद्देश्य और अवधि के लिए जिसके लिए ये प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।
- 1.5 यदि इस विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध लगाने की तारीख से पूर्व अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के उपलब्ध बकाया और समय अवधि के संबंध में निर्यात या आयात का पोत लदान मूल वैधता अवधि के भीतर किया गया हो।
तथापि, ऐसे अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के परिचालन के लिए आवेदक को किसी ऐसे प्रतिबन्ध या विनियमन जारी होने के 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास साख पत्र और संविदा का पंजीकरण कराना होगा।

अध्याय - 1 ख

विशेष फोकस पहलें

विशेष फोकस पहल

1ख.1

विश्व व्यापार के हमारे प्रतिशत हिस्से तथा रोजगार अवसरों को सतत रूप से बढ़ाने के दृष्टिकोण से, बाजार विविधता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्तरधारकों को सहायता, कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, चमड़ा, मैरीन, इलैक्ट्रानिक्स और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग, हरित उत्पाद, पूर्वोत्तर से उत्पादों के निर्यात, खेलकूद के सामान और खिलौना क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष फोकस पहलों की पहचान/जारी की गई है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करेगी जिनके लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीति तय करेगी जिसको समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

इसके अलावा, समय-समय पर अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय पहल की घोषणा की जाएगी।

(i) बाजार विविधता

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान परिसंपत्तियों की गिरती हुई कीमतों और बढ़ी हुई आर्थिक अनिश्चितता द्वारा प्रभावित होकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मांग की कमी से विकसित देशों में भारत के निर्यातों की वृद्धि को कम कर दिया है। ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि विकसित देशों में बाजार कब पुनर्जीवित हो पाएगा। विकसित देशों से मांग में आई कमी से भारतीय निर्यातों को उबारने के लिए, इस नीति में अन्य बाजारों में भारतीय निर्यातों के वैविध्यकरण पर फोकस है, विशेष रूप से जो लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओसियाना के हिस्से में स्थित हैं। भारतीय निर्यातों के वैविध्यकरण को प्राप्त करने के लिए, इस नीति के तहत निम्नलिखित पहल की गई है।

(क) फोकस मार्केट स्कीम के परिक्षेत्र में 26 नए देशों को शामिल किया गया है।

(ख) फोकस मार्केट स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन को 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।

(ग) 'बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम' के तहत और

ज्यादा बाजारों और उत्पादों को शामिल करके परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। इससे अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में सभी देशों को किए नें वाले निर्यात और चीन और जापान जैसे प्रमुख एशियाई बाजारों के लिए सहयोग सुनिश्चित होगा।

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन

निर्यात वृद्धि के अगले चरण में जाने हेतु भारत को निर्यात वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस लक्ष्य को हमारे निर्यात क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर ध्यान देने के लिए इस नीति में कई उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) शून्य शुल्क पर ई पी सी जी स्कीम, इंजीनियरिंग उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मूल रसायनों और भेषजों, अपैरेल एवं कपड़ा, प्लास्टिक, हैंडीक्रॉफ्ट्स, रसायनों और सह उत्पादों और चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों जैसे कुछ उत्पादों के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम का विस्तार किया जा रहा है ताकि इसमें और निर्यात उत्पाद समूहों को शामिल किया जा सके। इसमें समुद्री उत्पाद, खेलकूद का सामान, खिलौने, खड़ और खड़ उत्पाद, अतिरिक्त रसायन/सम्बद्ध उत्पाद और अतिरिक्त इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं। स्कीम की अवधि भी 31.3.2012 तक बढ़ाई जा रही है।

(ख) मौजूदा 3% ई पी सी जी स्कीम का निर्यातों द्वारा इसका प्रयोग आसान बनाने के लिए इसे काफी सरल बनाया गया है।

(ग) प्रलेखन एवं कार्रवाई समय को कम करने के लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु ई.पी.सी.जी. स्कीम की सुविधा शुरू की जा रही है।

(घ) मूल्य संवर्धित विनिर्माण निर्यात का बढ़ावा देने के लिए, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित निविष्टियों पर न्यूनतम 15% मूल्य संवर्धन निश्चित किया गया है।

(ङ.) ऑटोमोबाइल्स और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों समेत बहुत से उत्पादों को फोकस उत्पाद और बाजार लिंकड फोकस उत्पाद स्कीमों के तहत प्रोत्साहन के लिए शामिल किया गया है।

(च) प्रोजेक्ट निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

(iii) स्तर धारकों के लिए सहायता

सरकार ने भारत की वस्तुओं के निर्यातों में 'स्तर धारकों' के योगदान को लगभग 60% माना है । स्तरधारकों को प्रोत्साहन देने और प्रोत्साहित करने के लिए तथा निर्यात उत्पादन के प्रौद्योगिकी उन्नयन को भी प्रोत्साहित करने के लिए, पिछले निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 1% की दर से अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप चमड़े तथा इंजीनियरिंग, वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तकरघा और जूट के विशिष्ट उप क्षेत्रों सहित विनिर्दिष्ट उत्पाद समूहों के लिए प्रदान की जाएगी। यह ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इन स्तर धारकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्रयोग की जा सकती है। आयातित पूंजीगत वस्तुएं वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे होंगी । स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप स्कीम का विस्तार कर, समुद्री उत्पाद, खेल-कूद का सामान, खिलौने, विनिर्दिष्ट रसायन तथा संबद्ध उत्पादों और अतिरिक्त इंजीनियरिंग उत्पादों सहित अन्य कई निर्यात उत्पाद समूहों को शामिल कर लिया गया है ।

(iv) कृषि और ग्राम उद्योग

(क) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना ।

(ख) ई पी सी जी के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल ए ई जैड में किसी भी स्थान पर स्थापित करने की अनुमति होगी।

(ग) प्रतिबंधित मदों जैसे कि पैनल, के आयात की विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत अनुमति होगी ।

(घ) कृषि निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत, कीटनाशकों जैसी निर्विष्टियों के आयात की अनुमति होगी ।

(ङ) 150 करोड़ रु० की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात विशिष्टता वाले नये शहरों को अधिसूचित किया जाएगा ।

(च) अन्य स्तरधारकों तथा फूडपार्कों में स्थित ईकाइयों को सीमित हस्तांतरणीयता के जरिए कृषि-इन्फ्रा स्क्रिप के लिए अतिरिक्त नस्यता की अनुमति होगी ।

(v) हथकरघा

(क) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा।

(ख) हथकरघा निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एम.ए.आई./एम डी ए स्कीम के तहत विशिष्ट निधि निर्धारित की जाएगी।

(ग) विशिष्ट कतरनों और अलंकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी। हथकरघा मेडअप्स को भी हकदारी में शामिल किया गया है।

(घ) हाथ से बुनी हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

(ङ) पुनः निर्यात के लिए हाथ से बुने हुए कालीनों के पुराने टुकड़ों का खेप आधार पर शुल्क मुक्त आयात मरम्मत के बाद अनुमत होगा।

(च) 150 करोड़ रु० की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात विशिष्टता वाले नये शहरों को अधिसूचित किया जाएगा।

(छ) एफुलएन्ट शोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण को सीमाशुल्क से छूट गई है।

(vi) हस्तशिल्प

(क) यंत्रों, कटाई और छटाई की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी। हकदारी व्यापक प्राप्त है, और जिसकी सुविधा सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।

(ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जिनके लिए सीधे आयात करना व्यावहारिक नहीं है, वे कतरनों, अलंकरणों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए अधिकृत हैं।

(ग) हस्तशिल्प निर्यातों के प्रोत्साहन हेतु एमएआई और एमडीए स्कीमों के अधीन विशिष्ट निधियाँ निर्धारित की जाएंगी।

(घ) कतरनों, अलंकरणों और उपभोज्यों के शुल्क मुक्त आयात पर सी वी डी में छूट प्राप्त होगी।

(ङ) 150 करोड़ रु० की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात विशिष्टता वाले प्राप्त नये शहरों को अधिसूचित किया जाएगा।

(च) एफुलएन्ट शोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होंगे।

(छ) सभी हस्तशिल्प निर्यातों को विशेष फोकस उत्पादों के रूप में माना जाएगा और उच्चतर प्रोत्साहन के हकदार होंगे।

(ज) उपरोक्त के अतिरिक्त, हस्तशिल्प निर्यातों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के तहत 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा।

(vii) रत्न और आभूषण:

(क) 8 कैरेट और अधिक के स्वर्ण का आयात प्रतिपूर्ति स्कीम के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते कि आयात के साथ शुद्धता, भार और धातु की मात्रा दर्शाता हो और इसके साथ एक 'ऐसे' प्रमाण पत्र संलग्न हो।

(ख) उपभोज्यों, उपकरणों और अतिरिक्त मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आधारित) निम्नलिखित के लिए अनुमत होगी:-

1. निम्नलिखित से बने हुए आभूषण:

क) कीमती धातुएं (सोने और प्लेटिनम के अलावा)-	2%
ख) सोना और प्लेटिनम	1%
ग) रोडियम फिनिश चांदी	3%

2. कटे और पोलिशड हीरे - 1%

(ग) व्यापारिक नमूनों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी 300,000 रुपये होगी।

(घ) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी

निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी।

(ड.) भारत में जेमोलाजिकल इन्स्टीच्यूट ऑफ अमरीका (जी आई ए) और अन्य अनुमोदित एजेंसियों के प्राधिकृत कार्यालयों/ एजेंसियों द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनर्निर्यात के लिए खेप आधार पर हीरों के आयात की अनुमति होगी।

(च) विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए धारिता/भाग लेने के मामले में रत्न एवं आभूषणों के व्यक्तिगत असबाब को बढ़ाकर 5 मिलियन यू एस डालर कर दिया गया है और निर्यात संवर्धन भ्रमण के मामले में 1 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है।

(छ) अमेरिका में प्रदर्शनी के लिए भाग लेने के मामले में अनबिके मर्च के पुनः आयात के लिए दिनों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया है।

(ज) भारत को एक अन्तर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र बनाने के लिए, “हीरा बोर्स (बोर्सज)” स्थापित करने की योजना है।

(viii) चमड़ा और जूते

(क) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत अतिरिक्त 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा।

(ख) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत तैयार चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) विनिर्दिष्ट मर्च की शुल्क मुक्त आयात हकदारी गत वित्तीय वर्ष के दौरान चमड़े के सिले-सिलाए वस्त्र के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत होगी।

(घ) जूतों (चमड़ा और सिंथेटिक दोनों), दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए कतरनों, अलंकरणों और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 3 प्रतिशत होगी। ऐसी हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे छपे हुए और बिना छपे हुए जूतों के डिब्बे, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

(ड.) जलशोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण को मूल सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

(च) अनुपयुक्त आयातित सामग्री जैसे की खालें एवं चमड़ा और नम नीला चमड़ा का पुनर्निर्यात अनुमत है।

(छ) अस्तर और अन्तः अस्तर सामग्री सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01-03-2002 की क्रम सं. 168 के अंतर्गत सी वी डी से छूट प्राप्त है।

(ज) आई टी सी (एचएस) के अध्याय 43 के अधीन आने वाले कच्चा, टैन किए गए और ड्रेस लोम खालों पर सीवीडी से छूट प्राप्त होगी।

(झ) ना बेची गयी खालों, चर्मों और अर्द्ध तैयार चमड़े के पुनर्निर्यात की अनुमति, बिना निर्यात शुल्क के भुगतान के, सार्वजनिक बान्डेड गोदामों से दी जाएगी।

(ix) समुद्री क्षेत्र

(क) मत्स्य क्षेत्र (फिशिंग ट्रालर्स, जहाजों, नौकाओं और अन्य ऐसे ही मदों के अलावा) में ई पी सी जी के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आयात को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट होगी।

(ख) विनिर्दिष्ट खास निविष्टियों/रसायनों और सुगंधित तेलों आदि का शुल्क मुक्त आयात पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा।

(ग) टूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लॉग लाइन तंत्र के आयात को शुल्क की रियायती दरों पर और टूना फिशिंग हेतु बेट फिश के आयात को शून्य शुल्क पर अनुमत होगी।

(घ) विनिर्दिष्ट अपशिष्ट मानदण्डों की शर्तों के साथ समुद्री खाद्य अपशिष्ट की निकासी हेतु स्व-निराकरण प्रक्रिया लागू करना।

(ड.) वी.के.जी.यू.वाई स्कीम के तहत समुद्री उत्पादों को विशेष उच्च दर से प्रोत्साहित किया जाएगा।

(च) शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम और एसएचआईएस स्कीम के तहत लाभों के लिए समुद्री क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(x) इलेक्ट्रॉनिक और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग

(क) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) डी जी एफ टी से अनुमोदनों की त्वरित निकासी को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग निर्यातों को प्रोत्साहन देने हेतु एम ए आई और एम डी ए स्कीमों के उपयोग हेतु निर्यातक/एसोसिएशन पात्र होंगी।

(घ) एस एच आई एस स्कीम के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सैक्टर को भी शामिल किया गया है।

(xi) खेलकूद का सामान और खिलौने

(क) विनिर्दिष्ट विशेष निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3% तक दी जाएगी।

(ख) एम डी ए/एम ए आई स्कीम के तहत खेलकूद के सामान और खिलौनों को प्राथमिकता क्षेत्र माना जाएगा। इस क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु एम ए आई/एम डी ए स्कीम के तहत विशिष्ट निधियाँ निर्धारित की जाएंगी।

(ग) खेल कूद के सामान और खिलौनों से संबंधित आवेदनों को डी जी एफ टी द्वारा त्वरित निकासी हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) खेल कूद के सामान और खिलौनों को विशेष फोकस उत्पाद माना जाएगा और ये उच्चतर प्रोत्साहन के हकदार होंगे।

(ङ) उपरोक्त के अतिरिक्त, फोकस उत्पाद स्कीम के तहत खेल कूद के सामान तथा खिलौने के लिए 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा।

(च) शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम और एसएचआईएस स्कीम के तहत लाभों के लिए खेल कूद के सामान तथा खिलौनों को शामिल किया गया है।

(xii) हरित उत्पाद और प्रौद्योगिकियाँ

भारत का लक्ष्य हरित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और निर्यात हेतु-केन्द्र बनने का है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निर्यात हेतु ऐसे उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। प्रारंभ में, परिवहन, सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन और अन्य उत्पादों जैसा कि अधिसूचित किया जाए जिसे विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 की रिवाइड स्कीम के अधीन प्रोत्साहन दिया जाएगा, से संबंधित मदों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(xiii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निर्यात पर प्रोत्साहन

उत्तर-पूर्वी राज्यों से उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के अधिसूचित उत्पादों पर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 की रिवाइड स्कीम के अधीन प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अध्याय - 1 ग

व्यापार बोर्ड

व्यापार बोर्ड
(बीओटी)

विचारणीय विषय

1.ग.1 विदेश व्यापार से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए व्यापार बोर्ड की स्पष्ट और सक्रिय भूमिका है।

1.ग.2 व्यापार बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :-

I) बदलते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं बनाने तथा इन्हें क्रियान्वित करने में सरकार को सलाह देना;

II) विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, बाधाओं का पता लगाना तथा निर्यात अर्जन को अधिकतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपाय सुझाना ;

III) आयात और निर्यात के मौजूदा संस्थागत ढांचे की जाँच करना तथा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरल और कारगर व्यावहारिक उपाय सुझाना ;

IV) आयात और निर्यात के नीति दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा अधिकतम उपयोग हेतु ऐसी स्कीमों को तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाने हेतु उपाय सुझाना;

V) भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से संबंधित मामलों की जाँच करना तथा भारत के माल व सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाना; और

VI) उपर्युक्त लक्ष्यों को प्रवर्धन देने के लिए अध्ययन करवाना ।

संयोजन

1.ग.3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व्यापार बोर्ड (बीओटी) के अध्यक्ष होंगे। सरकार 25 व्यक्तियों को भी नामित करेगी, जिनमें 10 व्यक्ति व्यापार नीति में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ़ कामर्स के अध्यक्ष अथवा महासचिव पदेन सदस्य होंगे। व्यापार बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

अध्याय - 2

आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान

आयात और निर्यात
मुक्त जब तक कि अन्यथा
विनियमित न हो

2.1

निर्यात और आयात, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वे इस विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों अथवा तत्समये लागू अन्य कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं, मुक्त होंगे। मदवार निर्यात और आयात नीति, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित आई टी सी(एच एस) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

कोट डी आईवरी से अपरिष्कृत हीरों का आयात संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद संकल्प (यू एन एस सी आर) 1643 (2005) के पैराग्राफ 6 के अनुपालन में निषिद्ध होगा।

किम्बर्ले प्रोसेस सर्टीफिकेशन स्कीम (के पी सी एस) से वैनुजुएला के स्वैच्छिक अलगाव को देखते हुए वैनुजुएला को/से अपरिष्कृत हीरों (एच एस कोड-710210, 710221 अथवा 710231) का आयात/निर्यात निषिद्ध होगा। वैनुजुएला को/से अपरिष्कृत हीरों के आयात और निर्यात हेतु किम्बर्ले प्रोसेस प्रमाणपत्र स्वीकृत/पृष्ठांकित/जारी नहीं किया जाएगा।

2.1.1

इराक से/ को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात निषिद्ध होगा।

2.1.2

कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य (डी पी आर के) से/को, निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात चाहे कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो निषिद्ध है:

दस्तावेजों एस/2006/814, एस/2006/815 (एस/2009/205 सहित), एस/2009/364 और एस/2006/853 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दस्तावेज) आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी-9/भाग 1क और आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी-7/भाग 2क (आई ए ई ए दस्तावेज) में सूचीबद्ध सभी मदों, सामग्री उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी, जो डी पी आर के को आणविक संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा अन्य व्यापक जनसंहार के हथियारों संबंधी कार्यक्रमों में योगदान दे सकता है।

2.1.3

सभी मदों, सामग्रियों, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात, जो ईरान के परिशुद्धता-

संबंधी, पुनः संसाधन अथवा हैवी वाटर संबंधी कार्यकलापों में अथवा निम्नलिखित न्यूक्लीयर वीपन डिलिवरी सिस्टम्स के विकास में योगदान दे सकता है, चाहे उसका उद्गम देश ईरान हो या न हो, ईरान से/को, निषिद्ध होगा :-

i) दस्तावेज एस/2006/814 में आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी 8/भाग-1 में खण्ड ख.2 से ख.7 के साथ-साथ क.1 और ख.1 में सूचीबद्ध मदें ख.1 में शामिल उपकरण की आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानान्तरण के अलावा जब ऐसे उपकरण क.1.2 में शामिल लाइट वाटर रिएक्टरों और लो-एनरिच्ड यूरेनियम हेतु, जब रिएक्टरों हेतु असेम्बलड न्यूक्लीयर फ्यूल एलीमेंट्स में शामिल हो;

ii) श्रेणी-2 के 19.क.3 में शामिल मदों की आपूर्ति, बिक्री अथवा स्थानान्तरण को छोड़कर एस/2006/815 में सूचीबद्ध मदें ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उपर्युक्त दस्तावेज विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

कानूनों का अनुपालन

2.2

प्रत्येक निर्यातक या आयातक को, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति तथा उसको दिए गए प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन करना होगा । सभी आयातित माल भी देशी उत्पादित माल पर यथा लागू स्वदेशी कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अधीन होंगे। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किम्बलें प्रोसेस (के पी) प्रमाण-पत्र संलग्न किए बिना, अनगढ़े हीरों का आयात अथवा निर्यात अनुमत नहीं होगा।

नीति की व्याख्या

2.3

आई टी सी(एच एस) अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) अथवा डी ई पी वी दरों की अनुसूची में किसी मद के वर्गीकरण, के संबंध में या विदेश व्यापार नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे (जिसमें विषय वस्तु, कार्य क्षेत्र या प्राधिकार पत्र जारी करना शामिल है) में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा ।

प्रक्रिया

2.4

महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों तथा इस विदेश व्यापार नीति को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी, ऐसी प्रक्रियाओं को, इसी प्रकार, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

नीति/प्रक्रिया से छूट

2.5

व्यापार में आने वाली वास्तविक दिक्कतों और प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने हेतु, महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या समुचित हो, दे सकते हैं।

महानिदेशक, विदेश व्यापार लोकहित में, किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान से या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं और ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे। इस अनुरोध पर केवल निम्नलिखित समितियों की सलाह के बाद ही विचार किया जाएगा :-

क्रमांक	विवरण	समिति
(i)	सभी स्कीमों के तहत उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानदण्ड समिति
(ii)	ई पी सी जी स्कीमों के तहत पूंजीगत माल और लाभों के साथ अन्तः संबंध	ई पी सी जी समिति
(iii)	अन्य सभी मुद्दे	नीति छूट समिति (पीआरसी)

प्रतिबंध के सिद्धान्त

2.6

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता है :-

- (1) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण।
- (2) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।
- (3) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम।
- (4) कैदी श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम।

- (5) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व संबंधी मूल्य की राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण।
- (6) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण।
- (7) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण; और
- (8) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साजो-सामान के व्यापार की रोकथाम।
- प्रतिबंधित माल** 2.7 कोई भी माल, जिसका आई टी सी (एच एस) के अधीन निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित है, उसका इस संबंध में जारी किए गए प्राधिकार पत्र या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।
- लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ अनुमति/ प्राधिकार पत्र की शर्तें** 2.8 प्रत्येक प्राधिकार पत्र विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के लिए वैध होगा तथा उसमें क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तें होंगी, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकती हैं :-
- (क) माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य;
- (ख) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त;
- (ग) निर्यात दायित्व;
- (घ) प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संवर्धन; और
- (ङ.) न्यूनतम निर्यात/आयात मूल्य।
- प्राधिकार पत्र/ लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/ अनुमति पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है** 2.9 कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्राधिकार पत्र देने/नवीकरण करने से इंकार करने का अधिकार होगा।
- जुर्माना** 2.10 यदि प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके विरुद्ध इस विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- राज्य व्यापार** 2.11 कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी(एच एस) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है।

तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है।

राज्य व्यापार उद्यम वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं, ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।

आयातक-निर्यातक कोड संख्या 2.12

जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती, किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जायेगा।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार 2.13

महानिदेशक विदेश व्यापार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी स्कीम बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने, और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

माल लाने-ले-जाने की सुविधा 2.14

भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी।

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार 2.15

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीम बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में निहित, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।

वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 2.16

पूँजीगत माल, कच्चा माल, अन्तर्वर्ती, संघटक, उपभोग्य पदार्थ, अतिरिक्त कलपुर्जे, हिस्से पुर्जे, सहायक सामान, उपकरण और अन्य सामान, जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरूरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है जब तक कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त विशेष रूप से हटा न दी गई हो।

पुरानी वस्तुएं

2.17

पुराने पूंजीगत माल को छोड़कर सभी पुरानी वस्तुएं आयात हेतु प्रतिबंधित होंगी तथा उन्हें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों, आई टी सी(एच एस), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), सार्वजनिक सूचना या इस संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के अनुसार इनका आयात किया जा सकता है।

रिफर्बिश्ड/रि-कंडीशन्ड पुर्जों सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात मुक्त रूप से अनुमत होगा। तथापि पुराने व्यक्तिगत कम्प्यूटर/लैपटॉप, फोटो कॉपी मशीन, एअर-कंडीशनर्स, डीज़ल जनरेटिंग सेट की अनुमति सिर्फ लाइसेंस के मद्दे होगी।

पुनः विनिर्मित वस्तुओं के आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे होगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्क्रेप/अपशिष्ट

2.17क

विशेष आर्थिक क्षेत्र के यूनिट/विकास कर्ता/सह विकास कर्ता के विनिर्माणकारी या प्रोसेसिंग कार्य कलापों के दौरान किसी भी रूप में उत्पन्न हुए धात्विक अपशिष्ट/स्क्रेप सहित अपशिष्ट अथवा स्क्रेप या अवशेष को डी टी ए में मुक्त रूप से बेचने की अनुमति होगी, बशर्ते कि लागू सीमाशुल्क का भुगतान किया जाए।

नमूनों का आयात

2.18

नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) द्वारा शासित होगा।

उपहारों का आयात

2.19

विदेश व्यापार नीति के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों के आयात की अनुमति होगी। अन्य मामलों में सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) महानिदेशक, विदेश व्यापार से प्राप्त करनी होगी।

यात्री असबाब

2.20

वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों की शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है।

ऐसी मर्दों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी प्राधिकार पत्र के बिना वैयक्तिक असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है।

		विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, प्राधिकार पत्र के बिना, अपने वैयक्तिक असबाब के रूप में, निर्यात के लिए आवश्यक ड्राइंग, पैटर्न्स, लैबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ड्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।
निर्यात के आधार पर आयात	2.21	मुक्त रूप से निर्यात योग्य नये अथवा पुराने पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंटेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों तथा जिग्स, फिक्सचर्स, डाईज और माउल्ड्स का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक बचनबद्धता/ बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है।
विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात	2.22	आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, पुर्जे और अनुसंगी, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार या टेक्नोलौजी में सुधार अथवा मानकीकरण के लिए किसी प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है।
विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात	2.23	विदेश में परियोजनाएँ पूरी हो जाने के बाद, परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो।
खुले समुद्र में बिक्री	2.24	भारत में आयात हेतु खुले समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।
पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन आयात	2.25	पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है।
सीमाशुल्क विभाग से माल की निकासी	2.26	जो माल पहले ही आयातित/पोतलदान/पहुँच गया हो लेकिन सीमाशुल्क विभाग से जिसकी निकासी न हुई हो, उस माल की बाद में जारी प्राधिकार पत्र के मद्दे, निकासी की जा सकती है।
बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन	2.27	जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास यथानिर्धारित तरीके से एक विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी/बाँड का निष्पादन करना होगा। स्वदेशी प्राप्ति पत्र के मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में यथानिर्दिष्ट स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद

अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता/बॉण्ड को प्रस्तुत करना होगा।

**आयात के लिए निजी/
सार्वजनिक बांडेड
गोदाम**

2.28

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियारों और गोला-बारुद, खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे बांडेड गोदामों में रख सकता है।

विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो, प्राधिकार-पत्र के मद्दे, घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी की जा सकती है। ऐसे माल पर ऐसी वस्तुओं की, निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।

एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती, तो ऐसी वस्तुओं का आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है।

मुक्त निर्यात

2.29

जब तक ये निर्यात आई.टी.सी.(एच एस) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी वस्तुओं का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है।

तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है।

नमूनों का निर्यात

2.30

नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

**यात्री असबाब
का निर्यात**

2.31

वास्तविक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर निर्यात किया जा सकता है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना जरूरी होगा। तथापि, सरकारी तैनाती पर विदेश जाने वाले भारत सरकार के अधिकारियों को अपने नितान्त व्यक्तिगत उपभोग के लिए अपना व्यक्तिगत असबाब, खाद्य सामग्री(मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध) अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

उपहारों का निर्यात

2.32

किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में, खाद्य मदों सहित, 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा।

तथापि, निर्यात की आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार-पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात

2.33

प्लान्ट के वारंटी स्पेयर्स (देशी अथवा आयातित), इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स या कोई अन्य माल, (आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित मदों को छोड़कर) मुख्य इक्विपमेंट के साथ अथवा बाद में निर्यात किया जा सकता है किन्तु यह ऐसे माल की वारंटी अवधि के भीतर ही हो बशर्ते कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो।

तीसरा पक्ष निर्यात

2.34

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 में यथापरिभाषित तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति होगी।

आयातित वस्तुओं का निर्यात

2.35

विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी रूप में या अंशतः उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि आयात या निर्यात की जाने वाली मद आई टी सी (एच एस) में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित न हो।

मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे आयातित ऐसे माल के निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे दी जाएगी।

2.36

आयात की प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) सहित मदों का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राधिकार-पत्र के बिना किया जा सकता है बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

2.36क

डी टी ए बिक्री के प्रयोजन हेतु पब्लिक बांडेड वेयर हाउस में खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित चमड़े का आयात किया जा सकता है तथा उनकी अनबिकी मदों को 50% लागू निर्यात शुल्क पर ऐसे बांडेड वेयर हाउसेस को पुनः निर्यात किया जा सकता है। तथापि, यह सुविधा निजी बांडेड वेयर हाउस के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं होगी।

प्रतिस्थापन माल का निर्यात

2.37

निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित न हो।

मरम्मत किए गए माल का निर्यात

2.38

निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर, कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये गये तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है।

ऐसे सामान की प्राधिकार-पत्र के बिना और सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।

निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम

2.39

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जा सकती हैं।

ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के हकदार होंगे। ऐसे अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

निर्यात संविदाओं का कोटिकरण

2.40

सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप-से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के वर्ग में रखा जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी।

तथापि, विशेष निर्यातों के मद्दे निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि यह ए सी यू के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रुप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के जरिए हों। तदनुसार वोस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे हो। इस सौदे के कारण खरीददार को अपने गैर-आवासीय बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रुप में गिना जाएगा।

- संविदाओं (जिन के लिए भुगतान एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए किए जाएंगे) उन्हें ए सी यू डॉलर के वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के मद्दे निर्यात ठेकों और बीजकों का भारतीय रुपयों में कोटिकरण किया जा सकता है।
- निर्यात प्राप्तियों की वसूली** 2.41 यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
- निर्यातित वस्तुओं की मुक्त आवाजाही** 2.42 किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु अनुमत मदों की खेप को किसी भी कारण से रोका/बिलम्बित नहीं किया जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित, प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता की मांग कर सकता है।
- स्टॉक को जब्त न करना** 2.42.1 किसी भी अभिकरण द्वारा स्टॉक को जब्त नहीं किया जायेगा ताकि विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों और निर्यात वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख में बाधा न पड़े। कुछ खास मामलों में, संबंधित अधिकरण प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकता है। तथापि, इस प्रकार जब्त किए गए माल को 7 दिन के भीतर छोड़ना होगा।
- निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी)** 2.43 निर्यात संवर्धन परिषदों (ई पी सी) का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है। प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद, परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
- पंजीकरण - सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर सी एम सी)** 2.44 कोई भी व्यक्ति, जो
 (1) आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र (आई टी सी(एच एस) में प्रतिबंधित मदों के रूप में सूचीबद्ध मदों के अतिरिक्त) अथवा
 (2) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन करता है
 तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-

पत्र प्रस्तुत करना होगा बशर्ते कि इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार नीति के तहत विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो।

मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (सी आर ई एस) को इस नीति के तहत प्रयोजनों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर सी एम सी) के रूप में माना जाएगा।

ई डी आई पहल के जरिये 2.45 व्यापार सुविधा

सरकार की यह कोशिश है कि अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अमल में लाते हुए व्यापार दस्तावेजों के अधिकतम सरलीकरण, मानकीकरण और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए काम किया जाए। इस दिशा में, विदेश व्यापार महानिदेशालय दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है जो सीमाशुल्क और बैंकों सहित अन्य सामुदायिक साझेदारों के साथ संदेश के आदान-प्रदान और सहमत प्रोटोकाल पर आधारित है।

डी जी सी आई एण्ड एस 2.45.1 वाणिज्यिक व्यापार डाटा

प्रयोक्ताओं को पेशेवर ढंग से वाणिज्यिक निर्णय लेने के योग्य बनाने हेतु, डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा व्यावसायिक मानदण्ड से संरचना के प्रारूप पर आधारित न्यूनतम समय अन्तराल वाले व्यापार डाटा उपलब्ध कराये जाएंगे।

ई डी आई पहल अनुकूलन 2.45.2 के उन्नयन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ता समुदाय को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आवेदनों अथवा/और ई एफ टी (इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर) के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क में कटौती अनुमत होगी। ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

बंदोबस्त आयोग के जरिए 2.46 निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान

ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए जिन्होंने ऐसे कारण, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और रुग्ण इकाइयों के विलयन, अभिग्रहण और पुनर्वास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में बंदोबस्त आयोग को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

दस्तावेज अपेक्षाओं का 2.47 सरलीकरण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एकल सामान्य दस्तावेज (एस सी डी) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लंबित होने के कारण, निर्यात-आयात से डील करने वाले सरकारी विभाग जहाजरानी बिल,

निर्माण प्रमाण-पत्र

बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र, पैकिंग सूची, लदान बिल आदि जैसे निर्यात दस्तावेजों की जाँच के आधार पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र को स्वीकार करेंगे और इन दस्तावेजों को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं देंगे।

डी टी ए में सेवा कर की वापसी/छूट

2.48

प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के अध्याय-4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी माल और सेवाओं पर, जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों से तथा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निर्यात की गयी है, लगाए गए सेवा कर से छूट की अनुमति दी जाएगी।

एस ई जेड में सेवा कर से छूट

2.48.1

एस ई जेड में यूनिटों को सेवा कर से छूट दी जाएगी।

विदेश में ली गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट

2.48.2

भारत से निर्यातित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, विदेश में दी गई/प्राप्त की गई सेवाओं पर, जहाँ भी संभव है, सेवा कर से छूट होगी।

शिकायत निवारण

निर्यात/आयात के सुविधा प्रदान कर्ता के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय

2.49

विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातों और आयातों के सुविधा प्रदान कर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान बेहतर प्रशासन पर है, जो कि स्पष्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी निकासी प्रणालियों पर निर्भर करता है।

सिटीजन चार्टर

2.49.1

विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सिटीजन चार्टर है, इसमें ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय सारणी दी गई है और विभिन्न स्तरों पर शिकायत समितियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)

2.49.2

व्यापार और उद्योग जगत की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए, सरकारी संकल्प द्वारा शिकायत निवारण समिति के रूप में एक नई शिकायत निवारण प्रणाली गठित की गई है।

सरकार, देरी को माफ करने, वास्तविक मामलों में निर्यातकों द्वारा

उल्लंघन को विनियमित करने, हकदारी पर उठे विवाद को सुलझाने, प्राधिकार-पत्र के प्रयोग हेतु विस्तार की स्वीकृति के लिए, 27.10.2004 को स्थापित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से पिछली नीति की अवधि से सम्बन्धित सभी शेष समस्याओं और विवादों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नाशवान कृषि उत्पादों का निर्यात

2.50

सौदा और प्रबंधन लागतों को कम करने के लिए, नाशवान कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने हेतु एकल खिडकी प्रणाली शुरू की गई है। प्रणाली के तहत मल्टी-फंक्शनल नोडल एजेंसियों की स्थापना की जाएगी जिन्हें कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात

विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-40 पर विस्तृत प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं।

अध्याय - 3

संवर्धनात्मक उपाय

वाणिज्य विभाग में संवर्धनात्मक उपाय

निर्यात की मूलभूत सुविधाओं और संबद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई)

3.1

निर्यात की मूलभूत सुविधाओं और संबद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता देने की स्कीम बनाई गई है ताकि निर्यात प्रयासों में राज्यों को शामिल करने, निर्यातों के विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त मूलभूत सुविधाएँ सृजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा सके। यह स्कीम वाणिज्य विभाग द्वारा प्रशासित है।

इस स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है ताकि इन्हें निर्यात निष्पादन पर आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यात की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं हेतु धनराशि प्रदान की जा सके।

निर्यातों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु कार्यकलापों के लिए इस स्कीम से धनराशि प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि इनके कार्यकलाप सम्पूर्ण रूप से निर्यात से जुड़े हों और निर्यात से इनका जुड़ाव पूर्णतः सिद्ध हो। इस योजना के तहत जिस विशेष योजना के लिए धनराशि का आवंटन और उसका उपयोग किया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं:-

* नये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों (एसईजैड/कृषि व्यापार जोन्स) का सृजन तथा मौजूदा जोनों में सुविधायें बढ़ाना।

* निर्यात कानक्लेव में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य संबंधित मूलभूत सुविधाओं की स्थापना।

* मूलभूत ढाँचे की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी जिसमें एसईजैड की स्थापना भी शामिल है।

* ईपीआईपी/ईपीजैड/एसईजैड के पूँजीगत परिव्यय की आवश्यकता को पूरा करना।

* पूरक मूलभूत सुविधाओं का विकास जैसे कि उत्पादन केन्द्रों को सड़कों द्वारा पत्तनों से जोड़ना, इनलैंड कंटेनर डिपो तथा कंटेनर फ्रंट स्टेशनों की स्थापना।

* विद्युत आपूर्ति को अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों द्वारा स्थायी करना तथा निर्यात उत्पादन केन्द्रों आदि का समूह बनाना ।

* निर्यात प्रयोजन के लिए छोटे (माइनर) पत्तनों और जेटीज़ का विकास करना ।

* कामन एफल्यूएन्ट ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता और

* वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला अन्य कोई कार्यकलाप ।

एसआईडी स्कीम के बारे

<http://www.commerce.nic.in> या

<http://www.commerce.gov.in>

पर उपलब्ध है ।

बाजार पहुँच की पहल (एमआई)

3.2

एम.आई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता फोकस देश, फोकस उत्पाद के आधार पर निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए दी जाती है। निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार संगठनों, राज्य सरकार की एजेंसियों, विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्यिक मिशनों तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/पात्र संगठनों, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है ।

एम.आई स्कीम के अन्तर्गत सभी कार्यकलापों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है । अन्य के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) बाजार का अध्ययन/सर्वेक्षण करना,
- (ii) शो रूम/गोदाम स्थापित करना,
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेना,
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर में माल प्रदर्शित करना।
- (v) प्रचार मुहिम चलाना ।
- (vi) ब्राण्ड को प्रमोट करना ।
- (vii) क्रेता देश में सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भेषजों के लिए पंजीकरण प्रभार और क्लीनिकल परीक्षण आदि करने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति करना ।
- (viii) विदेश में इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार,
- (ix) एन्टी डम्पिंग मुकदमें लड़ने के लिए सहायता देना ।

इनमें से प्रत्येक निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए सरकार से उनकी कुल लागत के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है जो उनकी गतिविधियों और कार्यान्वयन एजेन्सी पर निर्भर करेगा।

दिशा-निर्देशों का पूरा विवरण <http://commerce.nic.in> पर उपलब्ध है।

**बाजार विकास सहायता
(एमडीए)**

3.3

एमडीए स्कीम के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार संवर्धन संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना वाणिज्य विभाग द्वारा प्रशासित है। सहायता में अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं

(i) व्यापार मेलों और विदेशों या भारत में क्रेता और विक्रेता सम्मेलन में भाग लेना।

(ii) व्यापार संवर्धन सेमिनारों में भाग लेना।

(iii) फोकस क्षेत्रों अर्थात् लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, एसईएन देशों, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में से किसी एक में यात्रा करने वाले निर्यातकों को यात्रा अनुदान के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में वित्तीय सहायता यात्रा अनुदान के बिना उपलब्ध है।

विपणन विकास सहायता उन निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी जिनका एमडीए के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित वार्षिक निर्यात कारोबार है। दिशा-निर्देशों का पूरा ब्यौरा <http://commerce.nic.in> पर उपलब्ध है।

**व्यापार से संबंधित मामलों
के लिए क्रेता देश में
सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा
करने पर होने वाले खर्च के
लिए धनराशि देना**

3.4

वाणिज्य विभाग निर्यात संवर्धन परिषदों की सिफारिश पर भेषज, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि रसायन उत्पादों के लिए उत्पाद पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रभारों सहित क्रेता देशों में सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभार/खर्च की प्रतिपूर्ति करता है। भारतीय मूल के विशेष उत्पाद (उत्पादों) पर प्रतिबन्धों/एन्टी डम्पिंग शुल्क आदि के लिए विदेशों में मुकदमा लड़ने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है जो कि वाणिज्य विभाग की बाजार विकास स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध है।

**उत्कृष्ट निर्यात वाले नगर
(टी ई ई)**

3.5

अनेक नगर अच्छे खासे औद्योगिक स्थापना स्थलों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में पर्याप्त योगदान देते हैं। इन औद्योगिक

क्लस्टर स्थलों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ताकि उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके और वैल्यूचेन में उनका दर्जा बढ़ाने में सहायता की जा सके और नये बाजारों की जानकारी प्राप्त की जा सके।

750 करोड़ रु० या उससे अधिक निर्यात करने वाले कुछ चुने हुए शहरों को उनकी निर्यात क्षमता के आधार पर उत्कृष्ट निर्यात के शहर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि व मत्स्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट निर्यात के शहर के लिए यह सीमा 150 करोड़ रु० होगी।

(i) विपणन क्षमता निर्माण और तकनालाजी सेवाओं हेतु निर्यात संवर्धन परियोजनाओं हेतु मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की यूनिटों को एम ए आई स्कीम के तहत प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदायक ई पी सी जी के लिए हकदार होंगे।

(iii) ए एस आई डी ई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु एसएलईपीसी द्वारा टीईई से प्राप्त परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

अधिसूचित नगरों की सूची प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) परिशिष्ट 7 में दी गई है।

ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता 3.6

विदेशी बाजारों में “भारत में निर्मित” लेबल के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से 11 जुलाई 1996 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आईबीईएफ (मूलरूप से इन्डिया ब्रांड इक्विटी फंड कहा गया था और बाद में इसका नाम इन्डिया ब्रांड इक्विटी फाउन्डेशन कर दिया गया था) का गठन किया गया था। आईबीईएफ का उद्देश्य भारत को विश्व में सकारात्मक आर्थिक सत्ता के रूप में सामने लाना और वैश्विक बाजार में भारतीय व्यापार सत्ता और सशक्त व्यापार साझेदार के रूप में कारगर रूप से प्रस्तुत करना है।

वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और निर्यात संवर्धन परिषदों की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए क्षमता निर्मित करने हेतु धनराशि प्रदान करता है ताकि वाणिज्य विभाग बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत गुणवत्ता के उन्नयन के लिए निर्यातकों

की कार्यकुशलता में सुधार करने, अस्वीकृतियों को कम करने, उत्पाद में सुधार आदि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सके।

परीक्षण गृह

- 3.7 केन्द्र सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण में सहायता करेगी ताकि उन्हें अन्तरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाया जा सके।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में संवर्धनात्मक उपाय

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/ विवाद

- 3.8 विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों की क्षेत्रीय उप-समिति (आर एस सी क्यू सी) द्वारा की जाएगी। विशेषतः गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु और सामान्यतः ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, दिशा-निर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-16 में दिए गए हैं।

व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विवाद

- 3.9 यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है, जो

(i) किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो, और/अथवा

(ii) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति गंभीर रूप से हानिकर हो, और/अथवा

(iii) जिससे देश की बदनामी हुई हो,

तो ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

3.10 निर्यात और व्यापार सदन

निर्यात और व्यापार सदन स्तर प्राप्त करने के लिए पात्रता

- 3.10.1 व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातानुसूची एकक (ई ओ यू)/विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) में स्थित एकक और कृषि निर्यात जोन (ए ई जेड) इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बी टी पी) स्तर के लिए पात्र होंगे।

स्तर श्रेणी

3.10.2 आवेदक की श्रेणी का निर्धारण नीचे दी गई सीमा से अधिक होने पर चालू तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन के कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य-मान्य निर्यातों के लिए) निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा। निर्यात सदन स्तर के लिए चार वर्षों (अर्थात् चालू और पिछले तीन वर्षों हेतु) में से कम से कम दो वर्षों में निर्यात निष्पादन आवश्यक है।

स्तर श्रेणी	निर्यात-निष्पादन एफ ओ बी/ एफ ओ आर मूल्य (रुपया करोड़ में)
निर्यात सदन (ई.एच)	20
स्टार निर्यात सदन (एस.ई.एच)	100
व्यापार सदन (टी.एच)	500
स्टार व्यापार सदन (एसटीएच)	2500
प्रीमियर व्यापार सदन (पीटीएच)	7500

स्तर प्रदान करने के लिए
दुगुनी भारिता तथा अन्य
शर्तें

3.10.3

(i) लघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के साथ पंजीकृत यूनिट, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिट/हस्तकरघा/हस्त शिल्प, हाथ से बुना कालीन/रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनिट तथा परिशिष्ट-9 में यथा सूचीबद्ध लेटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारन अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातक, आईएस ओ 9000 (ऋंखला) वाले यूनिट/आईएसओ 14000 (ऋंखला) स्तर वाले/ डब्ल्यूएचओजीएमपी/ एचएसी सीपी/एसईआईसीएमएम स्तर-2 तथा उच्च स्तर प्राप्त एजेंसियां जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 6 में सूचीबद्ध की हैं। सेवा और कृषि उत्पादों के निर्यात, स्टार निर्यात सदन स्तर की स्वीकृति हेतु, निर्यात की दोहरी वरीयता के पात्र होंगे। दोहरी भारिता व्यापारी के साथ-साथ विनिर्माता निर्यातकों को भी उपलब्ध होगी। तथापि, पोत-लदान उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी एक को केवल एक पोत-लदान के लिए दोहरी वरीयता दी जाएगी।

(ii) निर्यात निष्पादन एक से दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अतः निर्यात उत्पादन की गणना के लिए डिसक्लेमर पद्धति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) पुनः निर्यात आधार पर किए गए निर्यात की गणना मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं की जाएगी।

**निर्यात तथा व्यापार सदन
स्तरधारकों के लिए
विशेषाधिकार**

3.10.4

(iv) मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किये गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात निष्पादन में तभी गिना जाएगा जब लिमिटेड कम्पनी के सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर हों ।

एक स्तर धारक निम्नलिखित सुविधाओं का हकदार होगा :-

(i) स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी;

(ii) तरजीह पर 60 दिन के भीतर निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण ;

(iii) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य लेन-देन से छूट। तथापि, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से रुपया भेजना/प्राप्त करना, जारी रहेगा ।

(iv) ई ई एफ सी खाते में विदेशी मुद्रा का 100 प्रतिशत रखना होगा ;

(v) विदेश व्यापार नीति के अधीन स्कीमों में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट होगी ;

(vi) एस ई एच और उपर्युक्त को राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात गोदाम बनाने की अनुमति होगी;

(vii) स्तर धारकों के लिए, ए सी पी स्तर प्रदान करने के बारे में सीमाशुल्क कार्यालय से आवेदन प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निर्णय की सूचना दी जाएगी ।

(viii) विकल्प के रूप में, प्रीमियर व्यापार सदन के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत निर्यात का औसत स्तर 3 वर्षों के बदले पिछले पाँच वर्षों में निर्यात निष्पादन का संख्यात्मक औसत होगा ।

(ix) निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्तरधारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16 के अधीन स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए पात्र होंगे ।

(x) कृषि क्षेत्र के स्तर धारक (अध्याय-1 से 24) वीकेजीयूवाई-विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के तहत कृषि ढांचा प्रोत्साहन स्क्रिप हेतु पात्र होंगे।

3.11

सेवाओं का निर्यात

सेवा निर्यात	3.11.1	सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत आने वाली सभी 161 व्यापार योग्य सेवाएं शामिल हैं जहाँ ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है। सेवाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट - 10 में दी गई हैं।
		इस नीति के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित सेवाओं के निर्यात पर भी लागू होंगे जैसे कि वस्तुओं पर लागू हैं।
सेवा प्रदायकों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र	3.11.2	साफ्टवेयर निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक और साफ्टवेयर ई पी सी के पास पंजीकरण करवाना होगा। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट -2 की क्रम सं0 34 में सूचीबद्ध 15 विशिष्ट सेवाओं के निर्यातकों को सेवा ई पी सी के पास पंजीकृत करवाना होगा। अन्य सेवा निर्यातकों को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन के पास पंजीकृत करवाना होगा।
आम सुविधा केन्द्र	3.11.3	सरकार क्षेत्र विशेष में गृह आधारित सेवा प्रदायकों जैसे इंजिनियरिंग तथा वास्तुविद डिजाइन, नेटवर्क-मीडिया प्रचालनों, साफ्टवेयर के विकासकर्ताओं आदि के उपयोग हेतु आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विकास करेगी तथा राज्य स्तर और जिला स्तर के कस्बों से सेवा निर्यात क्षेत्र के गृह आधारित व्यावसायिकों को भारी संख्या में बुलाया जायेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में पुरस्कार/प्रोत्साहन स्कीमें

	3.12	भारत से सेवित स्कीम (एस एफ आई एस)
उद्देश्य	3.12.1	सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देना उद्देश्य है ताकि सशक्त और विशिष्ट “भारत से सेवित” ब्रांड को तुरंत समस्त विश्व में मान्यता और आदर प्राप्त हो सके।
पात्रता	3.12.2	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -1) के परिशिष्ट-10 में सूचीबद्ध सेवाओं के अखिल भारतीय सेवा प्रदायक जिनका कुल मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जन पिछले/चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपये है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पात्र होंगे।

व्यक्तिगत भारतीय सेवा प्रदायकों के लिए यह न्यूनतम मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जन 5 लाख रुपये होगा।

अपात्र सेवाएं तथा सेवा प्रदायक	3.12.3	सेवाएं और सेवा प्रदायक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 3.6.1 में यथा सूचीबद्ध एस एफ आई एस स्कीम के अन्तर्गत लाभ के हकदार नहीं होंगे।
हकदारी	3.12.4	सभी सेवा प्रदायक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे।
प्रेषण पात्रता	3.12.5	सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य उपकरणों के जरिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के परिकलन के लिए अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा को भी ध्यान में रखा जाएगा।
अनुमत आयात	3.12.6	<p>शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोज्यों सहित किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जो कि अन्यथा आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण के तहत मुक्त रूप से आयात के योग्य हैं और/अथवा प्रतिबंधित हैं। आयात आवेदक के किसी सेवा क्षेत्र व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए।</p> <p>अर्जित शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ उन वाहनों के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी के लिए दी जाएगी, जो सेवा प्रदायक के लिए व्यावसायिक उपस्कर की प्रकृति के होंगे।</p> <p>होटलों, क्लबों जिनमें कम से कम 30 कमरों की आवासीय सुविधा उपलब्ध है, गोल्फ रिजार्ट और विशिष्ट (स्टैंड एलोन) रेस्टोरेंटों के मामले में, जहाँ कैटरिंग सुविधा हो, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का खाद्य वस्तुओं और अल्कोहल युक्त पेयों सहित उपभोज्यों के आयात हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।</p>
गैर-हस्तांतरणीयता	3.12.7	हकदारी/माल (आयातित/प्राप्त) गैर-हस्तांतरणीय होगा (ग्रुप कम्पनी और प्रबन्धित होटलों को छोड़कर) और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।
घरेलू स्रोतों से प्रापण	3.12.8	एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के तहत अनुमत मदों के घरेलू स्रोतों से खरीद हेतु इस संबंध में जारी राजस्व विभाग की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।
	3.13	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई)

उद्देश्य

3.13.1 विशेष कृषि- और ग्राम उद्योग योजना का उद्देश्य निम्नलिखित निर्यात को बढ़ावा देना है -

- (1) कृषि उत्पाद और उनके मूल्य संवर्धित उत्पाद;
- (2) लघु वन्य उत्पाद और उनके मूल्य संवर्धित परिवर्ती;
- (3) ग्राम उद्योग उत्पाद;
- (4) वन आधारित उत्पाद; और
- (5) समय-समय पर यथा अधिसूचित, अन्य उत्पाद।

ऐसे उत्पादों को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 37क में सूचीबद्ध किया गया है।

हकदारी

3.13.2 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ उच्च परिवहन लागत की क्षतिपूर्ति के और अन्य हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान किए जाते हैं।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37 क में अधिसूचित उत्पादों के निर्यातक, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से, किए गए निर्यातों हेतु निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होंगे (मुक्त विदेशी मुद्रा में)।

तथापि, 27.8.2009 से किए गए निर्यातों के लिए, परिशिष्ट 37 क की तालिका 2 में यथा सूचीबद्ध, कुछ फूल, फल, वनस्पतियां और अन्य उत्पाद नीचे पैरा 3.13.3 के अनुसार उपलब्ध 5 प्रतिशत या 3 प्रतिशत वीकेजीयूवाई घटती दर हकदारी के अलावा, निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर एक अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के भी हकदार होंगे।

घटी हुई दर के लिए पात्रता

3.13.3 वी के जी यू वाई स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लाभ केवल उन निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य की तीन प्रतिशत घटी हुई दर पर दिए जाएंगे जिनमें निर्यातक ने निर्यातित उत्पाद के लिए निम्नलिखित लाभों का भी उपयोग किया है :-

- (i) 1% से अधिक दर पर शुल्क वापसी ; और/अथवा
- (ii) विशिष्ट डी ई पी बी दर (अर्थात् विविध वर्ग के अलावा- उत्पाद समूह 90 की क्रम सं०. 22 ग और 22 घ); और/अथवा
- (iii) अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (कैटैलिस्टस, उपभोज्य और पैकिंग सामग्री के अलावा)

जिसके लिए वी के जी यू वाई के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का दावा किया जा रहा है।

कृषि,
अवस्थापना प्रोत्साहन
स्क्रिप

3.13.4 किसी एक वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के लिए, आई टी सी(एच एस) अध्याय 1 से 24 में शामिल उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी स्तर धारकों (जिनके पास चालू वर्ष के लिए स्तर की मान्यता है) को कृषि निर्यातों (वीकेजीयूवाई लाभों सहित जो नीति के पैरा 3.13.2 के अधीन हकदार हैं) के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते कि सभी स्तर धारकों का कुल लाभ 100 करोड़ रुपये से अधिक न हो (अर्थात् प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये) और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.4 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया हो।

सभी स्तर धारकों को लाभ स्वीकृत करने के लिए जोनल कार्यालय, सी एल ए नई दिल्ली लाइसेंसिंग कार्यालय होगा।

निम्नलिखित पूंजीगत माल/उपकरण आयात हेतु अनुमत होंगे :-

(i) कोल्ड स्टोरेज यूनिटें (नियंत्रित वातावरण (सी ए) और संशोधित वातावरण (एम ए) स्टोर्स सहित); प्याज इत्यादि के लिए प्री कूलिंग यूनिटें और मदर स्टोरेज यूनिटें ;

(ii) पैक हाउसेज (हैंडलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग आदि के लिए सुविधाओं सहित) ;

(iii) रीफर वैन/कन्टेनर्स ; और

(iv) परिशिष्ट 37 च में यथा अधिसूचित अन्य पूंजीगत माल/उपस्कर।

आयातित पूंजीगत माल/उपस्कर का उपयोग भंडारण, पैकिंग आदि (उपर्युक्त (ii) में दिए गए अनुसार) और कृषि उत्पादों (कृषि संसाधित खराब होने वाले उत्पादों सहित) के परिवहन के लिए किया जाएगा।

यह अतिरिक्त लाभ वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा और इसलिए अहस्तांतरणीय है।

तथापि, कोल्ड चेन उपस्कर के आयात के लिए यह प्रोत्साहन स्क्रिप स्तरधारकों के साथ-साथ फूड पार्कों में स्थित ईकाइयों ("ईकाई" में विकासकर्ता शामिल नहीं हैं) के मध्य मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा।

3.14 फोकस मार्केट स्कीम(एफ एम एस)

उद्देश्य

3.14.1 इस स्कीम का उद्देश्य, इन देशों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से, चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से उच्च भाड़ा लागत तथा अन्य बाह्य लागतों की क्षतिपूर्ति करना है।

हकदारी

3.14.2 अधिसूचित देश (प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) की परिशिष्ट 37 में दिए अनुसार) सभी उत्पादों के निर्यातक, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से किए गए निर्यातों हेतु निर्यात (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे।

एफ एम एस के लिए अपात्र निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र

3.14.3 एफ एम एस स्कीम के तहत, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए निर्यात उत्पाद/क्षेत्र की निम्नलिखित श्रेणियाँ अपात्र होंगी:

क) एस ई जेड एककों को की गई आपूर्तियाँ;

ख) सेवा निर्यात;

ग) हीरे और अन्य कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थर;

घ) स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम और सादे और जड़ित आभूषणों सहित किसी भी रूप में अन्य कीमती पत्थर;

ड.) सभी रूप में और सभी प्रकार के अयस्क और सांद्रण;

च) सभी प्रकार के अनाज;

छ) सभी प्रकार की और सभी रूपों में, विनी ;

ज) सभी प्रकार के और सभी रूपों में, कच्चे तेल/पेट्रोलियम और कच्चे तेल/पेट्रोलियम आधारित उत्पाद जो आई टी सी(एच एस) कोड 2709 से 2715 में शामिल किए गए हैं।

झ) आई टी सी(एच एस) कोड 0401 से 0406; 19011001, 19011010, 2105 व 3501 के तहत शामिल दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

3.15 फोकस उत्पाद स्कीम (एफ पी एस)**उद्देश्य**

3.15.1 इस स्कीम का उद्देश्य उन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है, जिनकी उच्च निर्यात/रोजगार संभावना है, जिससे मूलभूत सुविधाओं में कमी तथा इन उत्पादों के विपणन में आयी अन्य सम्बद्ध कीमतों की क्षतिपूर्ति की जा सके।

पात्रता

3.15.2 सभी देशों (एस ई जैड यूनिटों सहित) को अधिसूचित उत्पादों (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 की परिशिष्ट-37घ में दिये गए अनुसार) का निर्यात, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से शुरू किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा।

तथापि, परिशिष्ट 37घ की तालिका 2 और तालिका 5 के अन्तर्गत आने वाले विशेष फोकस उत्पाद (उत्पादों)/क्षेत्र (क्षेत्रों) को, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27-8-2009 से किए गए निर्यात के लिए निर्यात से जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किया जाएगा।

इससे अलावा, परिशिष्ट 37घ की तालिका 7 के तहत अधिसूचित फोकस उत्पाद (उत्पादों)/क्षेत्र (क्षेत्रों) को, उत्पाद/क्षेत्र में अधिसूचित करने के लिए जारी सार्वजनिक सूचना में निर्यात/अवधि की अनुमेय तारीख से उत्पाद/क्षेत्र हेतु मौजूदा दर के अलावा निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2 प्रतिशत के बराबर एक अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किया जाएगा।

3.15.3 मार्केट लिंक्ड फोक्स उत्पाद स्क्रिप (एम एल एफ पी एस):

उच्च निर्यात तीव्रता/रोजगार संभावना (जो मौजूदा एफपीएस सूची में शामिल नहीं है) के उत्पादों/क्षेत्रों के निर्यात को एफपीएस के अन्तर्गत (मुक्त विदेशी मुद्रा में) निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि उन्होंने लिंक्ड बाजारों (देशों) को निर्यात किया हो, जो मौजूदा एफ एम एस सूची में शामिल न हो, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 37घ में, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से किए गए निर्यात के संबंध में अधिसूचित किया गया है।

3.16 स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एस एच आई एस)

3.16.1 नीचे पैरा 3.16.4 में यथासूचीबद्ध कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी उन्नयन में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, स्तरधारकों को शुल्क क्रेडिट के रूप में, इन विशिष्ट क्षेत्रों का 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान किए गए निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 1% प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए हकदार होंगे।

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 2009-14 (आर ई-2010) के पैरा 3.10.8 में सूचीबद्ध अतिरिक्त क्षेत्रों के स्तरधारक, 2010-11 और 2011-12 के दौरान किए गए निर्यातों पर स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र होंगे। यह इस अध्याय के तहत दावे/उपयोग किए गए किसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अतिरिक्त होगा।

3.16.2 किसी एक वर्ष में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी यू एफ एस) लाभों का उपयोग करने वाले स्तरधारक (वस्त्र मंत्रालय के अधीन) उस वर्ष के निर्यात के लिए स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र नहीं होंगे।

3.16.3 स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा और नीचे दिए गए पैरा 3.16.4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूँजीगत माल (विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित) के आयात के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।

3.16.4 निम्नलिखित क्षेत्रों के स्तर धारक इस स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र होंगे :-

1. चमड़ा क्षेत्र (तैयार चमड़े के अलावा);
2. वस्त्र व जूट क्षेत्र;
3. हस्तशिल्प;
4. इंजीनियरिंग क्षेत्र (आयरन और स्टील, प्राइमरी या इन्टरमिडिएट फार्म में नान फेरस मेटल, आटोमोबाईल व दुपहिये, न्यूक्लियर रिएक्टर व हिस्से तथा जहाज, बोट व फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स);
5. प्लास्टिक्स; तथा
6. मूल रसायन (फार्मा उत्पाद के अलावा)।

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 2009-14 (आर ई-2010) के पैरा 3.10.8 में सूचीबद्ध अतिरिक्त क्षेत्रों के स्तरधारक, 2010-11 और 2011-12 के दौरान किए गए निर्यातों पर स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र होंगे।

विशेष प्रावधान

3.17 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के सामान्य प्रावधान, विशेष रूप से इंगित किये मामले को छोड़कर

3.17.1 सरकार, लोकहित में, ऐसे देशों को निर्यात, उत्पादों या सेवाओं या निर्यातों को विनिर्दिष्ट करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है, जो हकदारी के परिकलन के पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा सरकार इस अध्याय के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप अधिकतम दर को लगाने/ परिवर्तित करने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है।

इसी प्रकार, सरकार वस्तुओं को अधिसूचित भी कर सकती है (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का परिशिष्ट 37ख में) जिसे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के तहत आयात की अनुमति नहीं होगी।

- अपात्र निर्यात श्रेणियाँ/ क्षेत्र** 3.17.2 निम्नलिखित निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र, वी के जी यू वाई, एफ एम एस, एफ.पी.एस. (एम एल एफ पी एस सहित) तथा स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हकदारी के लिए अपात्र होंगे :-
- (i) ई ओ यू/ई एच टी पी/बी टी पी जो कि प्रत्यक्ष कर/छूट का लाभ ले रहे हैं ;
 - (ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत शामिल आयातित माल का निर्यात ;
 - (iii) ट्रान्सशिपमेंट के जरिये निर्यात, अर्थात् जो निर्यात तीसरे देश से प्रारम्भ हुआ परन्तु ट्रान्सशिपमेंट भारत से हुई हो;
 - (iv) मान्य निर्यात;
 - (v) एस ई जैड यूनिटों द्वारा किया गया निर्यात या एस ई जैड उत्पादों का डी टी ए यूनिटों द्वारा निर्यात; और
 - (vi) आई टी सी (एच एस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध मर्दे।
- निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा) में कमीशन की गणना** 3.17.3 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ की गणना करते समय, निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा) विदेशी एजेन्सी कमीशन का 12.5% तक शामिल होगा।
- मुक्त हस्तान्तरणीयता** 3.17.4 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप तथा इसके तहत आयातित मर्दे मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगी।
तथापि, एस एफ आई एस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (पैरा 3.12) और स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (पैरा 3.16) मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय नहीं होंगे।
- अनुमत आयात** 3.17.5 शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग पूँजीगत माल सहित निविष्टियों या माल के आयात के लिए किया जा सकता है; बशर्ते कि ये मुक्त रूप से आयातित हो और/या आई टी सी(एच एस) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 37ख में सूचीबद्ध मर्दों के आयात को डेबिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात के मर्दे शुल्क के भुगतान के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अधीन शुल्क क्रेडिट स्क्रिप

- का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वह मद स्क्रिप के मद्दे आयात योग्य हो।
- सेनवेट/शुल्क वापसी** 3.17.6 एस एफ आई एस के अन्तर्गत आने वाले को छोड़कर, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद या डेबिट में अदा अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क, को राजस्व विभाग नियमों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा।
- टी आर ए सुविधा** 3.17.7 राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार टेलीग्राफिक रिलीज एंड वाइस (टीआरए) के अन्तर्गत पंजीकरण के पत्तन से भिन्न पत्तन से आयातों के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग अनुमत होगा।
- हकदारी की विशिष्टता** 3.17.8 पोतलदान के लिए, इस अध्याय में शामिल किसी भी स्कीम के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ का दावा केवल निर्यातक के विकल्प पर ही किया जा सकता है।
- पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत आयात** 3.17.9 विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.25 के प्रावधानों में पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।
- निर्यात निष्पादन का अन्तरण** 3.17.10 एक से दूसरे को निर्यात निष्पादन के अन्तरण की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार, पोतलदान बिल जिसमें आवेदक का नाम हो, उसकी निर्यात निष्पादन/कारोबार की गणना तभी की जाएगी जब विदेश से निर्यात आय की बसूली आवेदक के बैंक खाते में हुई हो और यह बी आर सी/ एफ आई आर सी से प्रमाणित होती हो।
- तथापि, वीकेजीयूवाई, एफएमएस तथा एफपीएस (एम एल एफ पी एस सहित) के लिए लाभ, या तो सहायक विनिर्माता (कम्पनी/ फर्म जिसने सीधे विदेश से विदेशी मुद्रा अर्जित की है से, डिसक्लेमर सहित) या कम्पनी/फर्म जिसने विदेश से सीधे विदेशी मुद्रा अर्जित की है, दावा कर सकता है।
- निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान की सुविधा** 3.17.11 इस नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट भी किया जा सकता है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद करना होगा।

अध्याय - 4

शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीम

- शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीम** 4.1 शुल्क विमुक्ति स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। शुल्क विमुक्ति स्कीम के अन्तर्गत (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम और (ख) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए) स्कीम शामिल है। शुल्क छूट स्कीम निर्यात उत्पाद में निर्यात के पश्चात प्रतिपूर्ति/प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क में छूट दी जाती है। शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत (क) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डी ई पी बी) और (ख) शुल्क वापसी स्कीम (डी बी के) हैं।
- शुल्क छूट/विमुक्ति स्कीम के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का पुनः आयात** 4.1.1 अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का उसी या पर्याप्त उसी रूप में पुनः आयात राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जा सकता है।
- मूल्य संवर्धन** 4.1.2 इस अध्याय के (रत्न और आभूषण क्षेत्र को छोड़कर) प्रयोजन हेतु मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगा :-
- ए-बी
- वी.ए. $= \frac{\text{बी}}{\text{ए}} \times 100$, जहाँ
- ए = किए गए निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य।
- बी = प्राधिकार पत्र के तहत आने वाले निवेशों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा कोई अन्य प्रयुक्त आयातित माल, जिसपर शुल्क वापसी के लाभ का दावा किया गया है, का योग।
- अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम**
- अग्रिम प्राधिकार पत्र** 4.1.3 निर्यात उत्पाद में (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) वास्तव में शामिल की गई निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। इसके अलावा, ईंधन, तेल, ऊर्जा, कैटालिस्ट, जिनकी खपत/प्रयोग निर्यात उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, को भी अनुमत

किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशक, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, अग्रिम प्राधिकार पत्र की सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को हटा सकता है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक ऐसे अनिवार्य कलपुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है जिनका परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात/आपूर्ति आवश्यक है। सिआन (एस आई ओ एन) के अधीन निवेशों और निर्यात मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं। ये प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.7 के अनुसार स्वतः घोषित मानदण्डों या तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।

अग्रिम प्राधिकार पत्र सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ जुड़े विनिर्माता निर्यातक, अथवा व्यापारी निर्यातक को निम्नलिखित हेतु जारी किया जा सकता है :-

- i) वास्तविक निर्यात (एस ई जैड को किए निर्यात समेत); और/या
- ii) अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ; और/या
- iii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.2(ख),(ग),(घ),(ङ),(च),(छ),(झ) और (ज) में उल्लिखित श्रेणियों को माल की आपूर्ति;
- iv) विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर "स्टोर्स" की आपूर्ति इस शर्त के मद्दे होगी कि संभरित मद (मदों) के संबंध में विशिष्ट सिऑन है।

इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(घ)(ङ)(च), (छ) और (ज) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के बारे में, उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी परियोजना के अग्रिम प्राधिकार पत्र का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते की उप-ठेकेदार का नाम मुख्य ठेके में उल्लिखित हो।

ऐसा प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संगठनों अथवा संयुक्त राष्ट्र संगठनों के सहायता कार्यक्रम अथवा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को की गयी आपूर्तियों हेतु भी जारी किया जा सकता है, जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

तथापि, कच्ची चीनी के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माता निर्यातक अथवा सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के

साथ जुड़े व्यापारी निर्यातक को जारी किया जा सकता है। निर्यात किसी भी अन्य फैक्टरी (फैक्टरियों) से सफेद चीनी की प्राप्ति द्वारा भी किए जा सकते हैं। यह प्रावधान 17.2.2009 से किए जाने वाले निर्यात के लिए लागू होगा।

- 4.1.4 अग्रिम प्राधिकार पत्रों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। तथापि, पैरा 8.2(ज) और (झ) के तहत शामिल आपूर्तियों हेतु आयातों को लागू एंटी-डम्पिंग और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी।
- 4.1.5 अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा उनके तहत आयातित माल वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी यह हस्तान्तरणीय नहीं होगा। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के बाद शुल्क मुक्त निविष्टियों में से विनिर्मित उत्पाद के निपटान का विकल्प प्राप्त होगा। ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद भी, निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवेट क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित माल उसी फैक्टरी के भीतर अथवा बाहर (सहायक विनिर्माता द्वारा) केवल शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकार पत्र धारक, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ई ओ डी सी के लिए आवेदन भरने के समय, निर्यातक के विकल्प पर, क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक अथवा सनदी लेखापाल से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। तथापि, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत 17.2.2009 से 30.9.2009 तक आयात की जाने वाली खांड के मामले में लागू नहीं होगी।
- इसके अलावा, यथा अनुमत, विनिर्माण अपशिष्ट/स्क्रेप का निर्यात दायित्व की पूर्ति से पहले भी लागू शुल्क के भुगतान पर निपटान किया जा सकता है।
- 4.1.6 प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 के परिशिष्ट-11ख में विनिर्दिष्ट मदों तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र की मदों, जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 के पैराग्राफ 4क 2.1 के अनुसार मूल्य संवर्धन होगा, को छोड़कर अग्रिम प्राधिकार पत्र न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात की अपेक्षा करता है। वसूली की मुद्रा का ध्यान दिए बिना, एसईजेड एककों को निर्यात/विकासक/सह-विकासक को आपूर्तियाँ भी इसमें शामिल होगी।

ऐसा वास्तविक निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है, वह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-11 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

चाय के आयात के लिए प्राधिकार पत्र के मामले में अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत न्यूनतम मूल्य संवर्धन 50 प्रतिशत होगा।

इसी प्रकार मसालों के मामले में (आई टी सी (एच एस) के अध्याय-9 में शामिल) मसालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल मूल्य संवर्धन प्रयोजनों जैसे क्रशिंग/ग्राइन्डिंग/ स्टेरीलाइजेशन या तेलों और ओलियो रेजिन्स के विनिर्माण हेतु होगी और सामान्य क्लीनिंग, ग्रेडिंग, रिपैकिंग आदि के लिए अनुमति नहीं होगी।

4.1.7 प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख को प्रभावी नीति और प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा।

आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति

4.1.8 अग्रिम प्राधिकार पत्र की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ अथवा सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु निःशुल्क निविष्टियों के नॉशनल मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निविष्टियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, यदि सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है तो निर्यातक के पास राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करने का भी विकल्प होगा।

निर्यात दायित्व

4.1.9 अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित अनुसार होगी।

बी आई एफ आर यूनिटों हेतु प्रावधान

4.1.9क बी आई एफ आर के पास पंजीकृत किसी फर्म/कम्पनी अथवा यूनिट का अधिग्रहण करने वाली किसी फर्म/कम्पनी, जो बी आई एफ आर के अन्तर्गत हो, उसे बी आई एफ आर के अनुमोदन अथवा 5 वर्ष यदि विनिर्दिष्ट न हो की शर्त के अधीन, तैयार किए गए पुनर्वास पैकेज के अनुसार संयोजन शुल्क की अदायगी के बिना निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान लघु उद्योग इकाइयों पर संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अनुसार लागू होते हैं।

वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र 4.1.10

अग्रिम प्राधिकार पत्र वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, एन्टि डम्पिंग शुल्क और सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, की अदायगी से छूट प्राप्त है।

स्तर प्रमाणपत्र धारक और निर्यातकों की अन्य सभी श्रेणियां जिनका विगत निर्यात निष्पादन (पिछले दो वर्षों में) हो, वे भी वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु पात्र होंगे।

आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अनुसार हकदारी वास्तविक निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 300 प्रतिशत और/ अथवा पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में मान्य निर्यात के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या एक करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो, तक होगी।

अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ) और अवैधीकरण पत्र 4.1.11

अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र का धारक जो सीधे आयात के बदले स्वदेशी स्रोतों/ राज्य व्यापार अभिकरणों से निविष्टियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेश या अवैधीकरण प्रमाणपत्र के प्रति मुक्त विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा। तथापि, ई. ओ. यू./ई.एच.टी.पी/बी.टी.पी/एस.टी.पी/एस ई जैड युनिटों से ए. आर.ओ या अवैधीकरण पत्र को परिवर्तन किए बिना प्राधिकार पत्र के प्रति आपूर्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।

डी एफ आई ए के हस्तान्तरी ए आर ओ/अवैधीकरण पत्र सुविधा के लिए भी पात्र होगा।

ए. आर. ओ की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित के अनुसार होगी।

बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र 4.1.12

अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, और डीएफआईए अग्रिम रिलीज आदेश या अवैधीकरण पत्र के लिए आवेदन करने के बजाय, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है।

निषिद्ध मर्दे 4.1.13

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए प्रमाण पत्र के तहत आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित आयातों की निषिद्ध मर्दों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मर्दों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए प्रमाणपत्र के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि, ये मर्दे

अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा अवैधीकरण पत्र के मद्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं।

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक को समुद्र में बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों को भी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार उद्यमों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक द्वारा आयात के लिए “अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)” जारी करने की अनुमति है। प्राधिकार पत्र धारक को उन “अनापत्ति प्रमाणपत्र” के मद्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य व्यापार उद्यम को प्रस्तुत करनी होगी और राज्य व्यापार उद्यम, ऐसे आयातों के अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने होंगे। इसकी एक प्रति डी जी एफ टी को भेजी जाए।

इसी प्रकार आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित निर्यातों की निषिद्ध मदों का इस अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए स्कीम के अन्तर्गत निर्यात नहीं किया जाएगा। प्रतिबंधित मदों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता अथवा सभी शर्तों के मद्दे, जैसा भी आवश्यक हो, आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत होगा।

शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

4.1.14

अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, निर्यातित माल में प्रयुक्त, शुल्क भुगतान किए गए माल पर शुल्क वापसी उपलब्ध होगी, चाहे आयातित या स्वदेशी हो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार, शुल्क वापसी उपलब्ध होगी। अनुमत शुल्क वापसी प्राधिकार पत्र में उल्लिखित होगी।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए) स्कीम

स्कीम

4.2.1

निविष्टियों, ईंधन, तेल, ऊर्जा स्रोत, उत्प्रेरक के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी के लिए एक शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) पत्र जारी किया जाता है जिनकी निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए जरूरत होती है। महानिदेशक, विदेश व्यापार, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, डी एफ आई ए की सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को बाहर कर सकते हैं। यह स्कीम 01 मई, 2006 से प्रभावी है।

हकदारी	4.2.2	डी एफ आई ए के मामले में पैराग्राफ 4.1.3 के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, ये प्राधिकार पत्र उन उत्पादों के लिए जारी किए जाएंगे जिनके लिए निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं।
		पश्च निर्यात डी एफ आई ए के मामले में, व्यापारी निर्यातक को केवल निर्यात उत्पाद (उत्पादों) के विनिर्माता (विनिर्माताओं) के नाम और पते का उल्लेख करना होगा। डी एफ आई ए के तहत निर्यात करने से पहले आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
		निर्यात पूर्व प्राधिकार पत्र वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन जारी किए जाएंगे तथा मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, एण्टी डम्पिंग शुल्क और सुरक्षात्मक शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट दी जाएगी।
		वास्तविक प्रयोक्ता डी एफ आई ए के मामले में और जहाँ निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद भी निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवैट क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, ऐसे डी एफ आई ए के मद्दे आयातित माल उस फैक्टरी के भीतर अथवा बाहर (सहायक विनिर्माता द्वारा) शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयोग किया जाएगा।
आयात मद्दे	4.2.3	डी एफ आई ए धारक के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 और 4.1.14 के प्रावधान लागू होंगे।
मूल्य संवर्धन	4.2.4	रत्न और आभूषण क्षेत्र की मर्दों को छेड़कर, जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैराग्राफ 4.2.1 में यथा उल्लिखित मूल्य संवर्धन होगा, ऐसे प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अपेक्षित होगा। अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अन्तर्गत जिन मर्दों के लिए अधिक मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, लागू होंगे।
निर्यात दायित्व	4.2.5	निर्यात दायित्व को पूरा करने से संबंधित प्रक्रिया और इसे पूरा करने के लिए अनुमत समयावधि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के अध्याय 4 में दी गई है।
हस्तान्तरणीयता	4.2.6	निर्यात दायित्व पूर्ण हो जाने के बाद, प्राधिकार पत्र की हस्तान्तरणीयता अथवा इसके मद्दे आयातित निविष्टियों के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकता है।

हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद, प्राधिकार पत्र धारक, डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित ईंधन और अन्य मद (मदों) के अलावा, डी एफ आई ए अथवा शुल्क मुक्त निविष्टियों का हस्तान्तरण कर सकता है। तथापि, ईंधन के लिए, आयात हकदारी केवल उन कम्पनियों को हस्तान्तरित की जाएगी, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार पत्र मंजूर किया गया है।

एक बार हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद, प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात/घरेलू प्रापण अथवा आयातित निविष्टियों/घरेलू स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों के हस्तान्तरण अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान करने की शर्त पर होंगे। हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित करते समय प्राधिकार पत्र में ऐसी अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क की देयता संबंधी टिप्पणी लिखी होगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ सेनवेट सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है, डी एफ आई ए पर हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के बाद भी अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट मिलेगी।

जहाँ कहीं सिसोन वास्तविक प्रयोक्ता शर्त निर्धारित करता है और एसिटिक एनहाइड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्राइन के मामले में, इन निविष्टियों के लिए वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ डी एफ आई ए जारी किए जाएंगे तथा निर्यात दायित्व पूरा करने के बाद भी इन निविष्टियों हेतु कोई हस्तान्तरणीयता अनुमत नहीं होगी।

तथापि, 01.4.2007 से पहले जारी प्राधिकार पत्रों हेतु, अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट विदेश व्यापार नीति (आरई-2006) में यथा उल्लिखित हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के बाद भी रहेगी।

सेनवेट सुविधा

4.2.7

आयातित या घरेलू स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों हेतु सेनवेट क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी।

शुल्क हकदारी पास बुक (डी ई पी बी) स्कीम

शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (डी ई पी बी)

4.3

शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर लागू सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। ईंधन पर सीमा शुल्क का हिस्सा (सिओन में उपभोज्य के रूप में दर्शाया गया) डी ई पी बी दर में भी कारक होगा। सेन्वैट क्रेडिट की अनुपलब्धता के मामले में, विशेष अतिरिक्त शुल्क का हिस्सा डीईपीबी दर (ब्रांड दर के रूप में) में भी अनुमत होगा। निष्प्रभावीकरण निर्यात उत्पाद के मद्दे शुल्क क्रेडिट की मंजूरी से किया जाएगा।

4.3.1

निर्यातक, मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के रूप में, क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। डी टी ए यूनिट से एस ई जैड यूनिट/एस ई जैड विकासक/सह-विकासक को आपूर्ति के मामले में, निर्यातक एस ई जैड यूनिट/एस ई जैड विकासक/सह-विकासक के विदेशी मुद्रा खाते से किए गए भुगतान अथवा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यातों के लिए क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक डी ई पी बी लाभ पाने का भी हकदार होगा, यदि 10.2.2006 से प्राप्त आपूर्तियों के लिए एस ई जैड विकासक/सह विकासक द्वारा भारतीय रुपयों में भुगतान किया गया है।

क्रेडिट, ऐसे निर्यात उत्पादों और ऐसी दरों के मद्दे उपलब्ध होगा जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों। क्रेडिट का इस्तेमाल मुक्त रूप से आयात योग्य मदों और/या प्रतिबन्धित मदों पर सीमाशुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है। ईपीसीजी स्कीम के तहत किए गए आयातों के शुल्क के भुगतान हेतु डीईपीबी स्क्रिप भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा, इस नीति के अध्याय 4 और 5 के अन्तर्गत जारी अनुदेशों में निर्यात दायित्व चूक शुल्क के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान हेतु डी ई पी बी स्क्रिप्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। नामे डाला जा सकता है। तथापि, जुर्माना/ब्याज की रकम का नगद भुगतान करना अपेक्षित होगा।

आईटीसी (एचएस) पुस्तक (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित निर्यातों की निषिद्ध मदें, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 1.5 के अनुसार, जहाँ अनुमत है, अंतरण सुविधा के तहत निर्यातों को छोड़कर डीईपीबी क्रेडिट की हकदार नहीं होंगी।

	4.3.2	डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान नगद भी करने का विकल्प होगा ।
वैधता	4.3.3	आयात के लिए डी ई पी बी की वैधता की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित के अनुसार होगी ।
हस्तांतरणीयता	4.3.4	डी ई पी बी और/अथवा इसके प्रति आयातित मर्दे मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। तथापि, डी ई पी बी का हस्तांतरण आयात के लिए विनिर्दिष्ट उस पत्तन पर होगा, जहाँ से निर्यात किया गया है। निर्यात के पत्तन से अलग पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के तहत अनुमति दी जाएगी ।
शुल्क वापसी की उपयुक्तता	4.3.5	डी ई पी बी के अधीन डेबिट के माध्यम से अथवा नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में भी समायोजित किया जाएगा। रत्न और आभूषण
रत्न और आभूषण के लिए स्कीम	4क	रत्न और आभूषण निर्यातक, विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात कर-सकते हैं/प्राप्त कर सकते हैं ।
प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र	4क.1	निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र (आर ई पी) प्राप्त कर सकते हैं । 4क.1.1 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.28 के अनुसार प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र उपभोज्यों हेतु भी जारी किए जा सकते हैं ।
प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात	4क.2	जैमोलोजिकल इन्स्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जी आई ए) की अथवा इस संबंध में अनुमोदित अन्य कोई एजेन्सी का भारत में, प्राधिकृत कार्यालय /एजेन्सियाँ उनके द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्टों के प्रयोजन, के लिए उनकी प्रयोगशालाओं को हीरे आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसे प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किसी आयात शुल्क के बिना उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्टों के साथ पुनः निर्यातित किया जाएगा ।
स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम के आभूषणों के लिए स्कीम	4क.3	स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, मार्डेंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती

पत्थर, सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।

नामित एजेंसियां

4क.4

नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी), एस टी सी एल लि०, एम एस टी सी लि०, डायमण्ड इण्डिया लि० (डी आई एल), रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी एण्ड जे ई पी सी), स्टार व्यापार सदन (केवल रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.10.2 के तहत प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी। निर्यातक (ई ओ यू और एस ई जेड में ईकाइयों को छोड़कर) नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

इन एजेंसियों (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और ई ओ यू और एस ई जेड स्कीमों के तहत संचालित रत्न एवं आभूषण यूनितों को छोड़कर) द्वारा बहुमूल्य धातुओं के आयात के लिए प्रक्रिया और उनकी निगरानी प्रणाली, इस संबंध में दिए गए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों के अनुसार, शोधन हेतु स्वर्ण छिड़न का निर्यात तथा मानक स्वर्ण छड़ों का आयात कर सकता है।

निर्यात की मदें

4क.5

निम्नलिखित मदों का, यदि निर्यात किया जाता है, तो वे इन सुविधाओं के लिए पात्र होंगी :

(क) 8 कैरेट या अधिक सोने वाले, सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित, जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं, जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं)।

(ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले, चांदी के जेवरात, जिसमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी के स्ट्रिप्स और वस्तुएं, मैडल और सिक्के शामिल हैं (इनमें वैध टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं है।)

(ग) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनम वाले, प्लेटिनम के जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा

वस्तुएँ, जिनमें तमगे एवं सिक्के भी शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं)।

मूल्य परिवर्धन

4क.6

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्य संवर्धन (वी ए) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2.1 में दिए अनुसार होगी। इसका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

ए - बी

$$\text{वी. ए} = \frac{\text{-----}}{\text{बी}} \times 100 \text{ जहाँ}$$

ए. = प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

बी. = निविष्टियों का मूल्य (घरेलू स्रोतों से प्राप्ति सहित), जैसे निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम अंश तथा रत्न आदि जैसी अन्य मदों के मूल्य सहित अनुमत अपशिष्ट का योग। जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी मूल्य में शामिल किया जाएगा।

छीजन मानदंड

4क.7

सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरात के लिए विनिर्माण हानि अथवा छीजन, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी।

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति के मद्दे निर्यात

4क.8

जहाँ निर्यात आदेश, तीन वर्ष के अनुभव वाली नामित एजेंसी/स्तर धारियों/निर्यातकों जिन्होंने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, को दिया जाता है, वहां विदेशी क्रेता विनिर्माण और निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम, एलॉय, चांदी/ स्वर्ण/ प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग का अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप में आपूर्ति कर सकता है।

ऐसी आपूर्तियां अग्रिम तौर पर की जा सकती हैं और इनमें अर्ध परिष्कृत आभूषण जिनमें मरम्मत/ पुनःनिर्माण और निर्यात के लिए फाइंडिंग/माउंटिंग/कम्पोनेन्ट्स शामिल हैं, बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य संवर्धन 10 प्रतिशत हो। तथापि, यदि इस प्रकार के आयातित अर्ध-परिष्कृत सोना/ चांदी/प्लेटिनम आभूषणों का जड़ित आभूषण के रूप में निर्यात किया जा सकता है तो, उनका मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा। निर्यात के ऐसे मामलों में, 2 प्रतिशत के छीजन की अनुमति दी जा सकती है।

नामित अभिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियों या स्तरधारियों/निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा।

**नामित एजेंसियों द्वारा
आपूर्ति के मद्दे निर्यात**

4क.9

निर्यातक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निविष्टि के रूप में अग्रिम अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है।

**अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे
निर्यात**

4क.10

निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र दिया जा सकता है :-

(क) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट और अधिक के माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स।

(ख) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।

(ग) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।

4क.11

ऐसे प्राधिकार पत्रों में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई जायेगी जिसे प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 4क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा। मूल्य संवर्धन प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैराग्राफ 4क 2.1 के अनुसार होगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

**रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार
पत्र**

4क.12

ऊपर पैरा 4क.8, 4क.9 और 4क.10 में रत्न प्रतिपूर्ति (रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति) प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

सादा या जडित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे प्राधिकार पत्र के मूल्य का निर्धारण, विनिर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य संवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में किया जाएगा।

ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।

- रत्न प्रतिपूर्ति दर और मद** 4क.13 प्रतिपूर्ति की दर और आयात की मद, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 12ख के अनुसार निर्धारित होगी ।
- निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात** 4क.14 वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से नामित एजेन्सियों और उनके सहयोगी तथा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की अनुमति से अन्य, विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।
स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने तथा ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात की भी अनुमति है बशर्ते ये प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई शर्तों के अधीन हो ।
- निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना** 4क.15 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा आयात पार्सल को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने- ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- डाक द्वारा निर्यात** 4क.16 विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में (जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा निर्यात भी शामिल है,) आभूषण के पार्सल का मूल्य 75,000 अमरीकी डालर तथा भार के रूप में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- हीरा और जवाहरात डॉलर खाते** 4क.17 अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/अजड़ित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्में तथा कम्पनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्नों से जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों के आयात या निर्यात में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 3 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार हो, नामजद हीरा डॉलर खातों (डी डी ए) के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती हैं ।
ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इसका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा -
(1) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों का आयात/खरीद ;
(2) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,
(3) विदेशी/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर ऋणों का पुनः भुगतान, और

(4) निर्यातक के रुपये खाते में हस्तांतरण । इस हीरा डॉलर खाता(डी डी ए) स्कीम के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिये गये हैं ।

गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की डीडिए धारक को आपूर्ति करने की अनुमति है, भुगतान डॉलर में मिलेगा तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलना होगा। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों और रंगीन रत्नों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई आपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व को पूरा किया गया ही माना जाएगा और/या इसे प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र का हक प्राप्त हो जाएगा।

परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

4क 18.

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमों के अनुसार परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी । पुनः निर्यात के मामले में, निर्यातक नियमानुसार शुल्क वापसी का हकदार होगा ।

अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

4क 19.

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड - 1 के पैरा 4क 32 के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषणों का पुनः आयात की करने अनुमति होगी ।

खेप आधार पर निर्यात

4क 20.

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1 के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषणों के निर्यात की अनुमति होगी।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम

शून्य शुल्क
ई.पी.सी.जी स्कीम

5.1

पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके सी के डी/एस के डी समेत) का शून्य सीमाशुल्क के आधार पर शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 6 वर्षों तक ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए ।

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में यथाउल्लिखित बहिष्करण की शर्त के अधीन इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिक उत्पादों, मूल रसायनों और भेषजों, परिधान और वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायन और संबद्ध उत्पादों तथा चमड़ा और चमड़ा उत्पादों, पेपर एवं पेपरबोर्ड और उसकी वस्तुएँ, सेरामिक उत्पाद, रिफ्रेक्टरीज, ग्लास एवं ग्लासवेयर, रबड़ एवं उसकी वस्तुएँ, प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेलकूद का सामान और खिलौनों के निर्यातकों हेतु यह स्कीम उपलब्ध होगी ।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु वैधता अवधि और निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि का प्रावधान प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में यथा उल्लिखित अलग-अलग होगा । इस अध्याय के अन्तर्गत रियायती 3% शुल्क ई पी सी जी स्कीम से संबंधित सभी अन्य प्रावधान जो शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम के उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं, शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम के लिए भी लागू होंगे । शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम 31.3.2012 तक लागू रहेगी ।

रियायती 3% शुल्क ई पी
सी जी स्कीम

5.2

पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके एस के डी/सी के डी समेत) का 3% सीमाशुल्क पर 3% रियायती शुल्क ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए ।

कृषि यूनिटों, कुटीर अथवा अत्यंत छोटे यूनिटों के मामले में, 3 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात अनुमत होगा

बशर्ते कि प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 12 वर्षों तक आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए।

लघु उद्योग एकको हेतु, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक, पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व पूरा करने के अधीन, 3 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते स्कीम के तहत ऐसे आयातित पूंजीगत माल पहुँचाने का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक न हो तथा ऐसे आयातों के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश लघु उद्योग एककों की निवेश सीमा से अधिक न हो।

तथापि, 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक शुल्क बचाने वाले ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में, निर्यात दायित्व 12 वर्षों की अवधि में पूरा करना अपेक्षित होगा।

यदि ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों पर सी वी डी नकद रूप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इसे सेन्चेट न किया गया हो।

पूंजीगत माल में स्पेयर्स, (रिफर्बिशड/रिकण्डीशन्ड स्पेयर्स सहित) औजार, जिग्स, फिक्चर, डाइज और माउल्ड्स शामिल होंगे।

ई पी सी जी स्कीम के अधीन पुराने पूंजीगत माल का आयात कालावधि संबंधी किसी प्रतिबन्ध के बिना किया जा सकेगा।

तथापि, मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, ट्रैवल एजेंटों, टूर प्रचालकों अथवा टूर परिवहन प्रचालकों और गोल्फ रिजाटर्स का स्वामित्व रखने वाली/संचालन करने वाली कंपनियों को निम्नलिखित शर्त के अधीन दी जायेगी:

(i) होटल, ट्रैवल तथा टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों, जिनका चालू और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रुपये अथवा अधिक हो।

(ii) मोटरकारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात हेतु किसी लाइसेंसिंग वर्ष में जारी सभी ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों पर बचाई गई शुल्क राशि विगत तीन लाइसेंसिंग

वर्षों में होटल, ट्रेवल और टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों से औसत अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) आयातित वाहनों को सिर्फ पर्यटन हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वाहन के आयात की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के पुर्जे जैसे चेसिस आदि, का ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात नहीं किया जा सकेगा।

आई टी सी (एच एस) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रतिबन्धित मदों के आयात की अनुमति मुख्यालय स्थित ई एफ सी से अनुमोदन के बाद ईपीसीजी स्कीम के तहत ही दी जाएगी।

5.2 क मौजूदा संयंत्र और मशीनरी (ई पी सी जी अथवा अन्यथा के तहत पहले से आयातित) के लिए स्पेयर्स (रिफर्बिशड/रिकण्ड्रीड स्पेयर्स सहित), माउलड्स, डाईज, जिग्स, फिक्चर्स, औजार, इनिशियल लाइनिंग हेतु रिफ्रैक्टरीज और उत्प्रेरक के आयात की ई पी सी जी स्कीम के तहत अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 8 वर्षों (शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम के लिए 6 वर्ष) में उपरोक्त पैरा 5.1 और 5.2 (पूँजीगत माल के आयात के लिए) में निर्धारित सामान्य निर्यात दायित्व के 50% के बराबर निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा। यह हालांकि इस शर्त के अधीन होगा कि उपरोक्त स्पेयर्स आदि के आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित प्लांट और मशीनरी के मूल्य के 10 % तक सीमित होगा। ई पी सी जी स्कीम के आयात नहीं किए गए प्लांट और मशीनरी के मामले में स्पेयर्स आदि के आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्लांट और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% तक सीमित होगा।

परियोजनाओं के लिए
ईपीसीजी

5.2 ख स्कीम के तहत पूँजीगत माल के आयात हेतु सीमाशुल्क छूट अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01.03.2002 की क्रम. सं. 441 के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित परियोजना के आयात के लिए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र भी जारी किया जा सकता है।

ऐसे ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क का आठ गुना होगा (शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम हेतु 6 गुना)। बचाया गया शुल्क उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्रभावी शुल्क और ईपीसीजी स्कीम के तहत रियायती शुल्क के बीच का अन्तर होगा।

खुदरा क्षेत्र हेतु ई पी सी जी 5.2ग

खुदरा क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत ढाँचा तैयार करने हेतु खुदरा व्यापारियों को जिनके पास न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, पूंजीगत माल के आयात के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे खुदरा व्यापारी को निर्यात दायित्व अर्थात् 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क का 8 गुना पूरा करना होगा।

वार्षिक आवश्यकता हेतु ईपीसीजी प्राधिकार पत्र

5.2घ

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र स्तर प्रमाणपत्र धारकों को वार्षिक आवश्यकता हेतु और अन्य सभी निर्यातकों की श्रेणियों को जारी किए जा सकते हैं जिनका दोनों शून्य शुल्क और 3 प्रतिशत शुल्क स्कीमों के अधीन विगत में निर्यात निष्पादन (पूर्ववर्ती दो वर्षों में) हो। बचाये गये शुल्क के रूप में वार्षिक हकदारी पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में वास्तविक निर्यात और/या मान्य निर्यात के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक होगा।

पात्रता

5.3

ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता(ओं)/विक्रेता(ओं) और सेवा प्रदायक सहित अथवा उनके बिना विनिर्माता निर्यातक/सहायक विनिर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक और सेवा प्रदायक शामिल हैं।

विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम में एक सेवा प्रदायक भी शामिल है, जो डी-जी एफ टी, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात विशिष्ट शहर में स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेशन द्वारा एक सामान्य सेवा प्रदायक (सी एस पी) के तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नामित/प्रमाणित है:-

(i) सी एस पी को दिए गए ई पी सी जी लाइसेंस में प्रयोक्ता के विवरण और निर्यात दायित्व जो प्रत्येक प्रयोक्ता पूरा करेगा, की मात्रा का स्पष्ट पृष्ठांकन करना होगा।

(ii) ऐसे निर्यातों की गणना अन्य विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु नहीं की जाएगी; और

(iii) सी एस पी के अलावा सी एस पी का प्रत्येक प्रयोक्ता 100% बैंक गारण्टी प्रस्तुत करेगा जो उनके द्वारा निष्पादित निर्यात दायित्व की मात्रा के अनुसार विभाजित छोड़ दिए गए शुल्क के भाग के बराबर होगा और यदि दायित्व पूरा नहीं किया गया है तो बैंक गारण्टी लागू की जाएगी।

पूँजीगत माल के आयात की शर्तें 5.4

पूँजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

निर्यात दायित्व 5.5

निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(i) आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तुओं/दी गई सेवाओं के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।

विस्तार अवधि सहित यदि कोई है, कुल निर्यात दायित्व कालावधि में पिछले 3 वर्षों में उक्त और उसी तरह के उत्पादों के किए गए निर्यातों का औसत, स्कीम के तहत निर्यात दायित्व से अधिक होगा; प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 5.7.6 में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर। यह औसत उक्त और उसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले 3 वर्षों के निर्यात निष्पादन का गणितीय माध्य होगा बशर्ते कि प्रिमियर व्यापार सदन (पी टी एच) को तीन वर्षों के स्थान पर पिछले पाँच वर्षों में निर्यात निष्पादन के गणितीय औसत आधारित निर्यातों के औसत स्तर को निर्धारित करने का विकल्प रहेगा।

50% तक निर्यात दायित्व उस फर्म/कम्पनी अथवा समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा अन्य विनिर्मित माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा पूरा किया जाएगा जिन्हें ई पी सी जी प्राधिकार प्राप्त है। तथापि, 1.4.2008 से पूर्व जारी ई पी सी जी प्राधिकार पत्र पहले के नीति प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

तथापि, ऐसे मामलों में, अतिरिक्त निर्यात दायित्व पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा किए गए औसत निर्यातों से अधिक होगा, यहाँ तक कि मूल और प्रतिस्थापक उत्पाद/सेवा के मामलों में भी जहाँ प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.7.6 में छूट दी गई है।

(ii) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र, डी एफ आर सी, डी एफ आई ए, डी ई पी बी या डॉ बैक योजना के अधीन पोतलदान को ई पी सी जी निर्यात दायित्व को पूरा करने लिए भी गणना की जायेगी।

(iii) निर्यात दायित्व डीटीए को आईटीए-1 मदों की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।

(iv) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे। तथापि नीति के पैराग्राफ 8.2 (क), (ख), (घ), (च) (छ) और (ज) में यथाउल्लिखित, मान्य निर्यात भी विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे।

आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे। विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के संबंध में, पत्तन संबंधी सेवाओं के लिए रुपए के रूप में प्राप्त भुगतान भी, निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए माना जाएगा।

बीआईएफआर यूनिटों के लिए प्रावधान

5.5.1

बी आई एफ आर के साथ पंजीकृत कोई फर्म/कम्पनी या यूनिट खरीदने वाली कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बी आई एफ आर के अधीन है, को बी आई एफ आर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित संचालन एजेंसी द्वारा तैयार पुनर्वास पैकेज के अनुसार निर्यात दायित्व 12 वर्ष तक बढ़ाने, यदि विनिर्दिष्ट न हो, की अनुमति होगी।

उपरोक्त प्रावधान लघु उद्योग इकाइयों पर भी संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अनुसार लागू होंगे।

एग्रो इकाइयों के लिए ईपीसीजी

5.5.2

विधिक वचनबद्धता/बांड पत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी (जो भी लागू हो) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को दिया जा सकता है बशर्ते कि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र परिशिष्ट 8 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (ओं) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया हो।

स्वदेशी रूप से पूंजीगत माल को प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

5.6

ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं घरेलू विनिर्माता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा। ऐसी घरेलू प्राप्ति की ई ओ यू से भी अनुमति दी जाएगी और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.9 (क) में दिए अनुसार उक्त ई ओ यू द्वारा सकारात्मक एन एफ ई को पूरा करने के उद्देश्य से इन आपूर्तियों को गिना जाएगा।

निर्यात दायित्व का निर्धारण

5.7

सीधे आयात के मामले में, निर्यात दायित्व वास्तव में बचाये गये शुल्क के संदर्भ में आंका जाएगा। घरेलू प्राप्ति के मामले में, निर्यात दायित्व रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाये गये नोशनल सीमा शुल्क के संदर्भ में गिना जायेगा।

**मौजूदा ई पी सी जी
मशीनरी का प्रौद्योगिकीय
उन्नयन**

5.8

ई पी सी जी प्राधिकार-पत्र धारक ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के प्रौद्योगिकीय उन्नयन का चुनाव कर सकता है।

मौजूदा पूंजीगत माल के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को शासित करने की शर्त निम्नानुसार है:-

(i) ई पी सी जी के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम समयावधि प्राधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष है।

(ii) पुराने पूंजीगत माल के तहत किया गया न्यूनतम निर्यात पहले ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र पर लगाए गए कुल निर्यात दायित्व का 40 प्रतिशत होना चाहिए।

(iii) निर्यात दायित्व को इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाएगा कि दोनों पूंजीगत माल के लिए निर्धारित कुल निर्यात दायित्व दोनों पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क की कुल राशि का 6 गुना होगा जिसे नए प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 8 वर्ष में पूरा करना होगा।

(iv) प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी और किया जाने वाला न्यूनतम आयात आवेदक फर्म द्वारा संयंत्र और मशीनरी में मौजूदा निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत होगा।

(v) आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल पूर्व पूंजीगत माल से नया व प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत होना चाहिए।

**फास्ट ट्रैक कम्पनियों के
लिए प्रोत्साहन**

5.9

निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से फास्ट ट्रैक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार-पत्र धारक ने अब तक प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक तथा औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा कर लिया हो तो बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र को विमुक्त कर दिया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.12 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

अध्याय - 6

निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क
(ई एच टी पी), साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी)
और बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी)

पात्रता

6.1

अपने सारे माल के उत्पादन और सेवाओं (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) योजना, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना या बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) स्कीम, के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री मेकिंग, री कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में लगी हो सकती है। इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

माल का निर्यात तथा
आयात

6.2

(क) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है, सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा।

निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोचर/साहित्य, पैम्फलेट, होर्डिंग, कैटलोग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्षों के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1:5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की भी अनुमति होगी।

(ख) निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट, डी टी ए अथवा डी टी ए में बाण्डेड गोदामों/भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात और/या खरीद कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हो। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण/लीज पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा।

(ग) निर्यात अभिमुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी। तथापि, क्रोम ओर/क्रोम कंसंट्रेट, के संबंध में इन मदों की निर्यात नीति में यथानिर्धारित राज्य व्यापार व्यवस्था निर्यात अभिमुख इकाईयों के लिए लागू होगी।

(घ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत वस्तुओं का शुल्क मुक्त डीटीए से आयात/खरीद कर सकती है। साफ्टवेयर ई ओ यू/डी टी ए यूनिटें साफ्टवेयर के निर्यात के लिए इस सुविधा का प्रयोग कर सकती हैं।

(ङ.) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियों से भी सोना/चांदी/प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिटों को ऋण अथवा सम्पूर्ण खरीद के आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात रिलीज की तारीख से 90 दिन के अन्दर करना होगा।

(छ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन सेवा यूनिटों के अलावा राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्करो रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रुस संघ को निर्यात कर सकती हैं।

(ज) स्पेयर्स/संघटकों की खरीद और निर्यातों के 5 प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क के बराबर उन्हीं करारकर्ता/खरीददार को निर्यात वस्तुओं के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि एन एफ ई और प्रत्यक्ष कर लाभों के लिए इनका आकलन नहीं किया जाएगा।

(झ) अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभूषण के अलावा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए

अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को शुल्क की अदायगी के बगैर पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू से डीटीए को आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण और ईओयू द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। ऐसे मामले में, खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का मूल्य एनएफई, डीटीए बिक्री हकदारी को माना नहीं जाएगा और ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं से प्राप्त लाभों को आयकर लाभों के योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन बोर्ड किन्हीं अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

पुराना पूंजीगत माल

6.3 पुराने पूंजीगत माल का बिना किसी कालावधि सीमा के शुल्क मुक्त आयात भी किया जा सकता है।

पूंजीगत माल के पट्टे

6.4 (क) पार्टियों के बीच में हुई पक्की संविदा के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूंजीगत माल खरीद सकते हैं। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट शुल्क का भुगतान किए बिना पूंजीगत माल, आयात करने/खरीदने के लिए संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी।

(ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी.टी.पी. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निम्नालिखित शर्तों के मद्दे पूंजीगत वस्तुओं को बेच सकता है और उसे एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पट्टे पर वापस दिया जा सकता है:-

(i) यूनिट को 'परिसंपत्तियों की बिक्री और पट्टे पर वापसी' का लेन-देन करने के लिए क्षेत्राधिकारी सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त से अनुमति लेनी होगी और बेचे जाने वाली या पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुओं का विवरण और एनबीएफसी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) बेचे जाने वाली और पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुएँ यूनिट के परिसर से नहीं हटाई जाएंगी।

(iii) यूनिट की निवल विदेशी मुद्रा सकारात्मक होनी चाहिए जब यह एनबीएफसी के साथ बिक्री एवं पट्टे पर वापसी के लेन देन को शुरू करती है।

(iv) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के साथ पठित अधिसूचना के किसी प्रावधान या व्यतिक्रम जिसके तहत इन वस्तुओं का आयात किया गया है या उन्हें खरीदा गया है, के मामले में इन वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए यूनिट और एन बी एफ सी द्वारा एक संयुक्त वचनबद्धता देनी होगी और इन वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास रहेगा जिनके पास सीमाशुल्क (सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं की संपत्ति को जब्त करना) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (ख) के प्रावधान के तहत यूनिट की सरकार को बकाया देय राशि की वसूली के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर प्रथम अधिकार रहेगा।

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन 6.5 (एन एफ ई)

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 14-1-ग के क्षेत्र विशेष के लिए प्रावधानों को छोड़कर जहाँ उच्च मूल्य संवर्धन की जरूरत होगी, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन होगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचित रूप से गिना जाएगा। जब भी कोई यूनिट परमिट पत्र में शामिल किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध प्रतिबंध के कारण निर्यात करने के लिए अयोग्य हो जाती है, निवल विदेशी मुद्रा आय की गणना के लिए पांच वर्षों का समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जा सकती है। अनुमोदन बोर्ड अगले एक वर्ष के लिए मामला दर मामला आधार पर, निवल विदेशी मुद्रा की गणना के लिए उन यूनिटों के लिए जिन्होंने 30.9.2008 और 30.9.2009 के बीच में पांच वर्षों की अवधि पूरी कर ली है तो केवल आर्थिक मंदी के कारण उस विशेष यूनिट की निर्यातों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए, विस्तार अवधि को बढ़ाने के लिए विचार कर सकता है।

अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और 6.6 विधिक वचनबद्धता: निवेश मानदण्ड

(क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा। एल ओ पी/

एल ओ आई की आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी इस अवधि के भीतर यूनिट को उत्पादन प्रारम्भ कर देना चाहिए। इसकी वैधता अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छः वर्ष से अधिक के विस्तार के प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र/आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.2 में प्रावधानों के अनुसरण में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजन के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की शर्त को अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को न पूरा कर सकने पर वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड की भागी होगी और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा मंसूख हो जाएगा।

पूँजी निवेश प्रक्रिया

(घ) जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश हो उन पर ई.ओ.यू. के रूप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, यह, मौजूदा यूनिटों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी, हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/जलकृषि/पशुपालन/सूचना तकनीकी, सेवाएं, ब्रास हार्डवेयर, हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

आवेदन और अनुमोदन

6.7

(क) सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं अथवा बी ओ ए द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवा गतिविधियों को छोड़कर) की यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को छोड़कर, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ई ओ यू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना के आवेदनों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार 15 दिनों के भीतर मंजूरी अथवा नामंजूरी दी जा सकती है।

(ख) अन्य मामलों में, इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

(घ) संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ या अधिक के निवेश या वार्षिक रूप से 50 करोड़ रु. या अधिक का निर्यात करने वाली मौजूदा डीटीए यूनिटों को ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में बदलने के लिए आवेदन अनुमोदन बोर्ड के सामने निर्णय के लिए रखा जाएगा।

तैयार उत्पाद/ अस्वीकृत 6.8
माल/ अपशिष्ट/ स्कैप/ शेष
और उप-उत्पाद की घरेलू
प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में
बिक्री

निर्यात अभिमुख यूनिटों/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिटों के सारे उत्पादन का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

(क) रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर, यूनिट निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर सकती हैं बशर्ते कि रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की पूर्ति की गई हो। डी टी ए बिक्री हकदारी के अन्दर, इकाइयाँ यूनिटों से निर्यातित या निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं जैसे माल को डी टी ए में बेच सकती है। तथापि, वे यूनिटें जो एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण एवं निर्यात कर रही हैं, विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात के 90 प्रतिशत पोत पर्यात निःशुल्क मूल्य तक इनमें से किसी भी उत्पादों को डीटीए में बेच सकती हैं बशर्ते उपरोक्त निर्धारित यूनिट के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की संपूर्ण हकदारी कुल डीटीए बिक्री के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और चाय (इन्सटैंट टी को छोड़कर) काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों, संगमरमर और समय-समय पर अधिसूचित ऐसी अन्य मदों के रियायती शुल्क पर डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पैकेजिंग/ लेबलिंग/ सेंग्रीगेशन/ रेफ्रीजरेशन/ कम्पैक्टिंग/ माइक्रोनाइजेशन/ पल्वराइजेशन/ ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमत से जुड़ी यूनिटों के मामले में डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड

यूनिट के विदेशी मुद्रा एकाउण्ट से किया गया हो। डी टी ए को की गई बिक्री भी फार्मास्यूटिकल उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए के निष्पादित वस्तुओं के विनिर्माण और संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा।

(ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनिटों सहित, डी टी ए में किसी भी रूप में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत / अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटें डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया हो। सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामित एजेंसियों से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एल ओ पी में विशेष रूप से निषिद्ध न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से उप पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की कुल सीमा के 50 प्रतिशत तक बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी। निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री पर एन.एफ.ई. प्राप्त करने की शर्त नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का यथा लागू रियायती शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार किया जा सकता है जो निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष की ऐसी बिक्री, सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। उन मद्दों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास

आयुक्त छः माह की अवधि और छः माह के भीतर मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित कर सकती है। तदर्थ मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित न कर दे। यूनिटों द्वारा जिन वेस्ट/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री डी टी ए बिक्री की पात्रता या डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री की अनुमति नहीं है उन पर शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को डी टी ए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते की नीति के पैरा 6.8 (क) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान और अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया हो। पैरा 6.8(क) की हकदारी के बाहर उपोत्पाद की बिक्री सम्पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर भी अनुमत होगी।

(ज) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिटों को काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों तथा संगमरमर को छोड़कर तैयार उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है जिनका डी टी ए में विदेश व्यापार नीति के अधीन पूर्ण शुल्क की अदायगी पर मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है बशर्ते इन यूनिटों ने सकारात्मक निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त किया हो। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए के निष्पादित वस्तुओं के विनिर्माण और संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विनिर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी।

(ञ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री के मामले में, जहाँ मूलशुल्क और सी वी डी शून्य है, ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए उत्पाद कर रहित माना जाएगा।

(ट) नये ई ओ यू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क बिक्री की अनुमति होगी जो प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों के 50%

से अधिक नहीं होगी, भेषज यूनिटों में यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी।

(ठ) कपड़ा एवं ग्रेनाइट क्षेत्र की यूनिटों के पास उपरोक्त उप-पैरा 6.8(क), (घ), (ड.), (छ) और (ट) के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में वस्तुओं को बेचने को विकल्प रहेगा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत लगाए गए उत्पाद-शुल्क की कुल की राशि के बराबर भुगतान पर या किसी अन्य कानून जो फिलहाल लागू है के तहत, एक निर्यात अभिमुख इकाई के अलावा भारत में पैदा या विनिर्मित समान वस्तुओं पर लागू होगा बशर्ते उन्होंने पिछले वर्ष में पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3% से अधिक चुकाई गई आयातित आगतों का प्रयोग न किया हो और उन्होंने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली हो। एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लेने पर इकाई को किसी भी उद्देश्य के लिए शुल्क मुक्त आगतों को आयात करने की अनुमति नहीं होगी।

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में अन्य
आपूर्तियाँ 6.9

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी—

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क छूट के तहत डी एफ आई ए/विमुक्ति योजना/ ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियाँ। तथापि, प्रिटिंग क्षेत्र की ईओयू (या अन्य कोई क्षेत्र जिसे प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में अधिसूचित किया जा सके) वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, जहां पर अग्रिम प्राधिकार पत्र के धारक/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार धारक के लिए मूल सीमाशुल्क शुल्क और सीबीडी शून्य है या अन्यथा छूट मुक्त है।

(ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ के मद्दे डीटीए में की गई आपूर्तियाँ।

(ग) अन्य निर्यातमुख इकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बायोटेक्नोलॉजी पार्क/एस ई जेड इकाई को आपूर्ति, बशर्ते ऐसे माल की खरीद के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.2 के अन्तर्गत की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) विदेश व्यापार नीति और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदामों और मुक्त व्यापार तथा गोदाम

क्षेत्रों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ड.) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्तियाँ, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, जैसी प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में व्यवस्था है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रानिक मदों की आपूर्ति।

(छ) निर्यात के लिए डीटीए यूनिट को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हेंगरों की आपूर्तियाँ।

(ज) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-20029/18/2001-पीपी दिनांक 28-01-2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002 (यहाँ पीडीएस स्कीम के रूप में निर्दिष्ट) के तहत सब्सिडाइज्ड मूल्यों पर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू तेल कम्पनियों को ईओयू रिफाइनरी में उत्पादित एलपीजी की सप्लाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी:-

(क) एलपीजी की केवल ऐसी मात्रा की सप्लाई मान्य होगी जिसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्यात की स्वीकृति न दी हो और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एलपीजी की निकासी की जानी हो; और

(ख) वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त पीडीएस स्कीम के तहत सप्लाई के लिए एपीजी के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति दी हो।

अन्यों के माध्यम से निर्यात 6.10

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विनिर्मित माल/विकसित साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा-6.18 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी 6.11

(क) निर्यातोंन्मुख इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों से की गई आपूर्तियों को “मान्य निर्यात” समझा जाएगा और आपूर्तिकर्ता पर डी.टी.ए. आपूर्तिकर्ता निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के अलावा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 के अधीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसक्लेमर प्रस्तुत करने पर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होंगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए, जहाँ भी वापसी की अखिल उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं, विकास आयुक्त द्वारा ब्राण्ड दरें निर्धारित करवाई जाएँगी।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) इसके अलावा, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे :-

(1) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति।

6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सी एस टी के वापसी में देरी पर देय होगा यदि पूरा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर मामले का निपटान नहीं किया जाता है। (जैसा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 9.10.1 में दिया गया है)

(2) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर, डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

(3) समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी दर के अनुसार घरेलू तेल कम्पनियों/घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के डिपो से प्राप्त ईंधन पर अदा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति। वित्त अधिनियम के तहत ईंधन पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति भी लागू होगी।

(4) अदा किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट।

अन्य हकदारियाँ

6.12

ई ओ. यू/ई एच. टी. पी/एस टी. पी/बी टी. पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैं :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अनुसार आयकर से छूट ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

(ग) निर्यात आय की वसूली 12 महीनों के भीतर करनी होगी ।

(घ) ईईएफ सी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन को रखने की अनुमति होगी ।

(ङ) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जाब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का

(1) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है ;

(2) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है; और

(3) यूनिट ने ।

(क) सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा/निर्यात दायित्व जहाँ भी लागू है, प्राप्त कर लिया है ।

(ख) धोखा/साठगांठ/जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को छुपाना या उनके किसी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम के दांडिक प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, वित्त अधिनियम 1994 सेवाकर या सहयोगी अधिनियम या उनके तहत बनाए गए नियमों को शामिल करते हुए के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस या पुष्टिकृत मांग जारी नहीं किया गया है ।

(च) एस ई जेड यूनिटों की तरह आटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी ।

(छ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों में निर्धारित तरीके के अनुसार मासिक आधार पर यूनिटें उत्पादित या विनिर्मित और डी टी ए में निष्पादित वस्तुओं पर शुल्क चुकाएंगी ।

अन्तर यूनिट हस्तांतरण

6.13

(क) निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के इन-बॉर्ड-मूवमेंट की प्रक्रिया को अपनाने वाले संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी। ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से ए ई जैड विकासक अथवा यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति भी एस ई जैड अधिनियम, 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(ख) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी तथा विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड यूनिटों को हस्तांतरित या ऋण पर दिया जा सकता है।

(ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएँ मानी जाएंगी।

उप-ठेके

6.14

(क) (1) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर जॉब वर्क के जरिये डी टी ए को उत्पादन प्रक्रिया का उप-ठेका दे सकती हैं जिनमें डी टी ए में यूनिटों द्वारा जॉब वर्क के जरिये माल के रूप या स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है।

(ii) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक भी उप ठेके पर दे सकती हैं।

(ख) (i) ई ओ यू यूनिटों को डीटीए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए गए

शुल्क को वापिस लेने के लिए डीटीए यूनिट हकदार होगी।

(ii) जब के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए ।

(iii) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू कर सकते हैं।

(iv) 'ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी एकक विदेशों में उत्पादन प्रक्रिया के अंश का उप ठेका दे सकते हैं और एलओपी में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती उत्पादों को विदेश भेज सकते हैं। विदेशी उप ठेकेदार परिसर से माल का निर्यात करते समय किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब माल को देश में वापस लाया जाएगा, सम्बंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जायेगी।'

(ग) जब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्कैप/वेस्ट/रेमनन्ट को या तो जॉब वर्कर के कार्य स्थल से सौदा मूल्य पर लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाइयों द्वारा अन्य ई ओ यू या एस ई जैड या डीटीए में इकाइयों में उपठेका/ विनिमय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

प्रयोग न किए गए माल की बिक्री 6.15

क) यदि कोई निर्यातानुमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से खरीदे गए माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो

- (i) इन्हें अन्य ई ओ यू/एसइजैड/ ई एच टी पी / एस टी पी/बी टी पी इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है; या
 - (ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात प्राधिकार सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या निर्यात कर सकती है; या
 - (iii) ई ओ यू/ई एचटीपी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मदों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा ।
- (ख) पूंजीगत माल और स्पेयर्स जो पुराने हो गए/अतिरिक्त हैं का निर्यात किया जा सकता है या अन्य ई ओ यू / ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड इकाइयों को हस्तांतरण या लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यहास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य कलपुर्जे, विनिर्मित माल, संसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रेप/बेस्ट/रैमनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।
- (ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।
- (घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी ।

रिकंडिशनिंग/
मरम्मत और पुनः
इंजीनियरिंग करना

6.16

निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को रिकंडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है । प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1

के पैरा 6.28 और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

**आयातित/स्वदेशी वस्तुओं
का प्रतिस्थापन/मरम्मत**

6.17

(क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात/आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई और किसी भी कारण से स्वीकार न की गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/बदलने के लिए लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके का हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामले में वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है। यूनिट विदेशी संभरकों के भारत में अधिकृत एजेंटों से मुफ्त प्रतिस्थापन (प्रदत्त शुल्क ले सकती है बशर्ते की खराब हिस्से का पुनः निर्यात किया गया या नष्ट किया गया है)। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

ईओयू योजना से बहिर्गमन

6.18

(क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती है। ऐसा बहिर्गमन उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के भुगतान करने पर और लागू औद्योगिक नीति के तहत होगा।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन के समय उसे जुर्माना देना होगा।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य

धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित ऐजसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर इस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) 'ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी' यूनिट को भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों के लिए अनुमेष, मौजूदा 'ई पी सी जी' स्कीम के तहत पूँजीगत माल पर शुल्क का भुगतान करके विकास आयुक्तों द्वारा किसी भी समय स्कीम को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। यह 'ई ओ यू' स्कीम के तहत सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा मानदण्ड की पूर्ति, 'ई पी सी जी' स्कीम के तहत पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

(ङ) 'ई ओ यू' योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा। यूनिट डिबांडिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टि करेंगे। शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात यूनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी "बेबाकी प्रमाण-पत्र" के आधार पर यूनिट अन्तिम रूप से डिबांडिंग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा।

यदि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम डिबांडिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र और विकास आयुक्त द्वारा जारी किया गया अन्तिम डिबांडिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूँजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा। तथापि वे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी ई पी बी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं यदि गणना और देय राशि विवादास्पद है और उसमें लम्बा समय लगेगा तो विकास प्रक्रिया को तेज़ करने

के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/किस्त प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाएगी।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबान्डिंग के पश्चात् डी टी ए में ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ ले जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार ई पी सी जी योजना के तहत यहाँ डी टी ए यूनिटों के रूप में पूँजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात् और स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूँजीगत वस्तुओं को ले जाते समय पूँजीगत वस्तुओं से सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

(छ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार के तहत एक बार के विकल्प के रूप में निकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है। यह सकारात्मक एन एफ ई मानदण्ड की पूर्ति के अधीन होगा।

परिवर्तन

6.19

(क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं और पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10(क) और 10(ख) के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।

(ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

एन एफ ई की निगरानी

6.20

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन
यात्राओं/ विदेश में शो
रूमों/शुल्क मुक्त दुकानों के
जरिये निर्यात

6.21

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को निम्नलिखित की अनुमति है:

- (i) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना ।
- (ii) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य को व्यक्तिगत रूप से लाना/ले जाने ।
- (iii) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए माल का निर्यात करने ।
- (iv) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/बिक्री हेतु निर्यात करने ।
- (v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना करने ।

आयात/ निर्यात पार्सलों को
व्यक्तिगत रूप से लाना ले
जाना जिसमें विदेश जाने
वाले यात्रियों के जरिए
सामान ले जाना शामिल है

6.22

रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाईयों के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हों। भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रत्न एवं आभूषण ई ओ यू का प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत ढुलाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 किग्रा. तक प्रारंभिक रूप में सोने का आयात कर सकता है ।

डाक/कोरियर द्वारा निर्यात/
आयात

6.23

निःशुल्क नमूनों सहित माल का सीमा शुल्क के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाने या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

ई ओ यू यूनिटों का
प्रशासन/विकास आयुक्त
की शक्तियाँ

6.24

ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त की शक्तियों का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान

6.25

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है।

ई एच टी पी/एस टी पी के
लिए अनुमोदन

6.26

ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनितों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति विकास आयुक्त के बजाए संचार व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अन्तरमंत्रालयीय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी।

बी टी पी का अनुमोदन

6.27

जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बी टी पी) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। बी टी पी में यूनितों के मामले में इस अध्याय के संबद्ध उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

अध्याय - 7

विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

अध्याय - 7क

मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र

मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र संबंधित नीति विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

अध्याय - 8

मान्य निर्यात

मान्य निर्यात

- 8.1 “मान्य निर्यात” का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।

संभरण की श्रेणियाँ

- 8.2 विदेश व्यापार नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल की मुख्य/उप ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को “मान्य निर्यात” के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित हुआ हो :-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के मद्दे माल का संभरण;

(ख) निर्यातानुमुख यूनिटों (ईओयू) / साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एसटीपी) / इलेक्ट्रॉनिक हार्ड वेयर टेक्नालोजी पार्क (ई एच टी पी) / बायोटेक्नालोजी पार्क (बी टी पी) को माल की आपूर्ति।

(ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) प्राधिकार पत्र धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/ निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्था हो।

इन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जिनके लिए बोली आमंत्रित की गई है और विदेश में विनिर्मित वस्तुओं के लिए डी डी पी मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित है, माल और उपकरणों की आपूर्ति और अधिष्ठापन (टर्नकी ठेकों का एकल उत्तरदायित्व);

(ड.) पूंजीगत माल, अनअसैम्बल्ड/ डिसअसैम्बल्ड तथा संयंत्र,

मशीनरी, अनुषंगी, औजार, डाई तथा वाणिज्य उत्पादन तक स्थापना हेतु प्रयुक्त होने वाले, माल सहित और उर्वरक संयंत्रों के एफ ओ आर मूल्य के 10 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों की आपूर्ति;

(च) शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देने वाली वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए माल की आपूर्ति;

(छ) ऊपर (च) में शामिल न किए गए पावर प्रोजेक्टों और रिफाइनरी को माल की आपूर्ति;

(ज) 100 प्रतिशत ई-ओ यू (घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो;

(झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति; और

(ञ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को माल की आपूर्ति ।

पैराग्राफ (घ), (ड.), (च) और (छ) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे यदि आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

तथापि, मेगा पावर प्राजेक्ट के संबंध में आई सी बी की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी, यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा को प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली के जरिये समझौते द्वारा प्राप्त किया गया हो या प्रोजेक्ट को प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली द्वारा दिया गया हो ।

मान्य निर्यातों के लिए लाभ 8.3

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार मान्य निर्यात के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित में से कोई/सभी लाभ दिए जाएंगे

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए

(ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।

(ग) जहाँ आपूर्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के मद्दे की गई हैं वहाँ अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट होगी। अन्य मामलों में अन्तिम उत्पाद शुल्क वापिस किया जाएगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा दूसरे अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता को की गई आपूर्तियों के लिए अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सकती है, जहाँ ऐसा विनिर्माता, बदले में, अन्तिम निर्यातक को उत्पाद (उत्पादों) की आपूर्ति करता है।

आपूर्तिकर्ता को लाभ

8.4.1

(i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(क) के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डी एफ आई ए के मद्दे की गई आपूर्तियों के संबंध में आपूर्तिकर्ता, अन्तर्वर्ती आपूर्ति हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए का हकदार होगा।

(ii) यदि आपूर्तिकर्ता ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.11 और 4.1.12 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के मद्दे जारी अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) या बैंक टू बैंक साख-पत्र के अनुसार आपूर्ति की है तो वह विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग), जो भी लागू हो, में सूचीबद्ध लाभों का हकदार होगा।

8.4.2

विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ख) के अनुसार ईओयू/ईएच टी पी/एस टी पी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग), जो भी लागू हो, में सूचीबद्ध लाभों का हकदार होगा।

8.4.3

विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ग) के अधीन आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3 (क) (ख) और (ग), जो भी लागू हो, में सूचीबद्ध लाभों के हकदार होंगे।

8.4.4

(i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (घ), (च) और (छ) के तहत आपूर्तियों के मामले में, आपूर्तिकर्ता पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का हकदार होगा।

(ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(घ) में उल्लिखित आपूर्तियों के संबंध में केवल ऐसे अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति, जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित की जाए, मान्य निर्यात लाभों की हकदार होगी। ऐसे अभिकरणों/निधियों की सूची प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 13 में दी गई है।

(iii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(च) के तहत मान्य निर्यात के लाभ उन मदों पर लागू होंगे, जिनका आयात शून्य सीमाशुल्क पर राजस्व विभाग द्वारा अनुमत होगा, बशर्ते कि वह समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।

(iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा-8.2(छ) के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को की गई पूंजीगत माल और पूंजीगत माल के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक पुर्जों की आपूर्ति, मान्य निर्यात लाभों के लिए हकदार होगी बशर्ते कि वह स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई पी पी)/इंजीनियरिंग एण्ड, प्रोक्योरमेंट कान्ट्रैक्ट (ई पी सी) स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद की गई हो। तथापि, मेगा पावर प्राजेक्ट के संबंध में आई सी बी की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी, यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा को प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली के जरिये समझौते द्वारा प्राप्त किया गया हो या प्राजेक्ट को प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली द्वारा दिया गया हो। मान्य निर्यात के लाभ पावर संयंत्रों के नवीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु भी उपलब्ध होंगे। आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में दिए गए लाभों जो भी लागू हों, के लिए पात्र होंगे। तथापि, यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 की क्रम सं० 400 में यथा निर्दिष्ट कोई बड़ी पावर परियोजना स्थापित करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.3 (क), (ख) और (ग) में, जो भी लागू हो, यथा उल्लिखित मान्य निर्यात के लाभ पाने की पात्र होगी, यदि ऐसी बड़ी योजना, सीमाशुल्क अधिसूचना में, विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्पादन क्षमता के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 की क्रम संख्या 400 में यथा विनिर्दिष्ट मौजूदा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए अपेक्षित माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात लाभों, जो भी लागू हो, को पाने की पात्र होगी।

(v) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.2छ के अन्तर्गत उन नई रिफाइनरियों को जो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित

की गई हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक चलेगी, को आपूर्ति, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 की क्रम संख्या 228 में विनिर्दिष्ट सूची संख्या 17 में उल्लिखित माल के लिए मान्य निर्यात के लाभों की हकदार होंगी। आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, के लिए पात्र होगा।

8.4.5 विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(ड.) के तहत की गई आपूर्तियों के मामले में, आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, के लिए पात्र होगा। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों के पूंजीगत माल और पुर्जों लिए भी उपलब्ध होंगे जिन्हें नौवीं योजना के दौरान स्थापित अथवा विस्तारित/रीवेम्पड/रिट्रोफिटिड/आधुनीकीकरण किया गया है। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों को की जाने वाली उन आपूर्तियों के लिए भी उपलब्ध होंगे, जो आठवीं/नौवीं योजना में शुरू हुई हैं और दसवीं योजना तक चलेगी।

8.4.6 विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(झ) के अन्तर्गत आने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित परियोजना को माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, के लिए पात्र होंगी।

8.4.7 विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ज) के तहत न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को की गई आपूर्तियों के सम्बन्ध में, आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) जो भी लागू हों, में विनिर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क की क्रम सं० 401 की सूची 43 में विनिर्दिष्ट किसी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने हेतु अपेक्षित केवल उस माल की आपूर्ति, जिनकी क्षमता 440 मैगावाट या अधिक हो जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी ने प्रमाणित किया हो, की गई आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ की हकदार होंगी, बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोली (न कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली) प्रक्रिया के अधीन हुई हो।

**अंतिम उत्पाद शुल्क
वापसी/शुल्क वापसी
के लिए पात्रता**

8.5 माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(ग) के अनुसार में अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/छूट प्राप्त न की हो। इसी प्रकार आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि आवेदक द्वारा सेनवेट क्रेडिट सुविधा/छूट प्राप्त न की गई हो। तथापि ऐसी आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए सीमाशुल्क पर मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी।

8.5.1 मान्य निर्यात स्कीम के तहत ड्यूटी ड्रा बैंक और अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी में देरी होने पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा; यदि पूर्ण आवेदक की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मामले का निपटान नहीं किया गया हो (प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 के पैरा 9.10.1 में यथा निर्धारित)।

मुख्य/उप ठेकेदार द्वारा की जाने वाली आपूर्तियाँ

8.6.1 मान्य निर्यात के सभी मामलों में, आपूर्तियाँ प्रत्यक्षतः नामित प्रोजेक्ट/एजेन्सियाँ/यूनिटें/अग्रिम प्राधिकार पत्र/ई पी सी जी प्राधिकार-पत्र धारक को की जाएंगी। तथापि, उप ठेकेदार नामित प्रोजेक्ट/ एजेन्सियों को सीधे आपूर्ति करने के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्ति करेगा। ऐसी आपूर्तियाँ प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 8.4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्य निर्यात के लाभ पाने के पात्र होंगी।

8.6.2 भारतीय या विदेशी मुख्य ठेकेदारों के भारतीय उप ठेकेदार द्वारा नामित प्रोजेक्ट/एजेन्सियों को सीधे की गयी आपूर्तियाँ भी मान्य निर्यात के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि करार में मूल रूप में या बाद में उप ठेकेदार का नाम भी दर्शाया गया हो तथा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-22ग के अनुसार उप ठेकेदार के नाम में परियोजना प्राधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

अध्याय - 9

परिभाषाएं

- 9.1 विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे।
- 9.2 “उपांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।
- 9.3 “अधिनियम” का अर्थ है-विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) (एफ टी (डी एण्ड आर) एक्ट)।
- 9.4 “वास्तविक उपयोक्ता” का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है।
- 9.5 “वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी स्वयं की औद्योगिक यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा जाबिंग यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करता है।
- 9.6 “वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो:-
- (1) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, या
 - (2) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अस्पताल, या
 - (3) अन्य सेवा उद्योग।
- 9.7 “ए ई जैड” का अर्थ है प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 8 में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।

- 9.8 “अपील” वह आवेदन है जो कि अधिनियम के भाग 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वह आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में जमा किए जाते हैं।
- 9.9 “आवेदक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल हैं।
- 9.9.1 “प्राधिकार-पत्र” का अर्थ है विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, के भाग 2(छ) में बताया गया है।
- 9.10 “बी-ओ ए” का अर्थ है अनुमोदन बोर्ड जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- 9.11 “बीटीपी” से अभिप्राय उन बायोटेक्नालोजी पार्कों से है जिन्हें बायोटेक्नोलोजी विभाग की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 9.12 “पूँजीगत माल” का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है। पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रारंभिक लाइनिंग हेतु रिफ्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, उर्जा अर्जित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, इनीशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं। पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- 9.13 “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो।

- 9.14 “संघटक” का अर्थ है उप संयोजन या संयोजन का वह तत्व जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए। संघटक में दूसरे संघटक के उपसंगी या उपकरण भी शामिल हैं।
- 9.15 “उपभोज्य” का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जिन मदों का अधिक मात्रा में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा।
- 9.16 “उपभोक्ता माल” का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए उपभोज्य माल और उसके अनुसंगी भी शामिल होंगे।
- 9.17 “प्रतिसंतुलन व्यापार” (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो। प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। निर्यातों और आयातों का संतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है।
- 9.18 “विकासकर्ता” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसा ही अन्य निजी या सरकारी उपक्रम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, वित्तीय सहायता, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है, इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल है।
- 9.19 “विकास आयुक्त” का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त।
- 9.20 “डी एफ आर सी” का अर्थ है शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र (जैसा विदेश व्यापार नीति 2004-09 में दिया गया है)।

- 9.21 “घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र” का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी से बाहर है।
- 9.22 “शुल्क वापसी” का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में, किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। माल में आयातित कलपुर्जे शामिल हैं यदि भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आपूर्ति की गई है।
- 9.23 “ई. एच. टी. पी.” का अर्थ है इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलाजी पार्क।
- 9.24 “ई.ओ.यू.” का अर्थ है निर्यातोन्मुख एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो।
- 9.25 “उत्पाद शुल्क देय माल” का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन हो।
- 9.26 “निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, या निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.27 निर्यात दायित्व का अर्थ है:- प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा में शामिल निर्यात उत्पाद अथवा उत्पादक क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।
- 9.27.1 “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति जो कि अधिनियम के भाग-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है।
- 9.28 “कम्पनी समूह” से अभिप्राय दो या अधिक इन्टरप्राइजेज जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों-
- (i) अन्य इन्टरप्राइजेज में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक भागीदारी होगा; या
- (ii) अन्य इन्टरप्राइजेज में निदेशक मण्डल के सदस्यों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो,

समूह कम्पनियों के लाभ का दावा करने या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा लाभ का दावा करने के लिए उनके निर्यात की गणना हेतु, समूह कम्पनी को विदेश व्यापार नीति की अधिसूचित निर्यात संवर्धन स्कीमों के अधीन आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्ष पूर्व मौजूदा होना चाहिए।

9.29 “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)” का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है और “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -2)” का विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-2) से है।

9.30 “आयातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, या आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

9.31 “बुनियादी सुविधाओं” का अर्थ है औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाएं या कोई अन्य सुविधा जो कि यथाअधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए हो।

9.32 “आई टी सी (एच एस)” का अर्थ निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है। —

9.33 “जाबिंग” का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो।

9.34 “लाइसेंसिंग वर्ष” का अर्थ उस वर्ष से है जो वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।

9.35 “प्रबंधित होटल” से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल ऋंखला द्वारा होटल चलाना/होटल ऋंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार में प्रबंधित होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र आवश्यक रूप को शामिल किया जायेगा।

9.36 “विनिर्माण” का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया,

- गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, रि-कन्डीशनिंग, मरम्मत, रि-मेकिंग, रि-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन रि-इन्जीनिरिंग। विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए विनिर्माण में कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोदपादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।
- 9:37 “विनिर्माता निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।
- 9:38 “एम्. ए. आई.” का अर्थ बाज़ार पहुंच पहल स्कीम है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 9:39 “व्यापारी निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।
- 9:40 “एन-सी” का अर्थ शुल्क मुक्त स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र प्रदान करने की सिफारिश करने तथा डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मूल्य संवर्धित मानदण्ड व निविष्टि उत्पादन मानदण्ड की सिफारिश करने के लिए बनी विदेश व्यापार महानिदेशालय की मानदण्ड (नार्मस) समिति से है।
- 9:41 “एन एफ ई” का अर्थ निवल विदेशी मुद्रा है।
- 9:42 “अधिसूचना” का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए।
- 9:43 “आदेश” का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश।
- 9:44 “पुर्जे” का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो। “पुर्जा” एक संघटक, स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है।
- 9:45 “व्यक्ति” का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कॉर्पोरेशन अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों सहित अन्य कोई वैध व्यक्ति।

- 9.46 “नीति” का अर्थ है समस्त-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 ।
- 9.47 “निर्धारित” का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा विदेश व्यापार नीति अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश के तहत निर्धारित से है ।
- 9.48 “सार्वजनिक सूचना” का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है ।
- 9.49 “कच्ची सामग्री” का अर्थ है:

(1) मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में है, और

(2) किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती है, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो ।

- 9.49.1 “क्षेत्रीय प्राधिकारी” का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत एक प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी ।
- 9.50 “पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र” (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है ।
- 9.51 “नियमों” का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।
- 9.52 “सेवाओं” में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है ।
- 9.53 “सेवा प्रदायक” का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-

(i) भारत से किसी और देश के लिए “सेवा” प्रदान करता है,

(ii) भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई "सेवा" की आपूर्ति करता है, और

(iii) भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से "सेवा" की आपूर्ति करता है।

(iv) भारत में निर्यातों से सम्बन्धित "सेवा" की आपूर्ति जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में या भारतीय मुद्रा में किया गया हो और जिस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया माना हो।

9.54 "एस ई जेड" का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

9.55 "जहाज" का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्र तट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है, इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं।

9.56 "एस आई ओ एन" का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) में अधिसूचित/ अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों से है।

9.57 "स्पेयर्स" का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जें या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। स्पेयर्स में संघटक या सहायक उपकरण शामिल हैं।

9.58 "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।

9.59 "स्तर धारक" का आशय उस निर्यातक से है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक या विकास आयुक्त ने निर्यात सदन/ व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी है।

9.59.1 "भंडार" से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएँ हैं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपकरणों का अन्य सामान है, चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो।

9.60 "एस टी पी" का अर्थ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क से है।

- 9.61 “सहायक विनिर्माता” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद या उसके हिस्सों/उपांगों/संघटकों का विनिर्माण करता है। सहायक विनिर्माता के साथ-साथ निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए।
- 9.62 “तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात” का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक (निर्यातकों) की ओर से किया गया निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख करना होगा। बी आर सी, जी आर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक, तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए।
- 9.63 “सौदा मूल्य” की परिभाषा राजस्व विभाग की सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली में दी गई है।
- 9.64 “वन्य प्राणी” का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में परिभाषित है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

No. 1 (RE 2010)/2009-2014

S.O. 2065(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy, 2009-2014 incorporating the Annual Supplement as updated on 23rd August, 2010 and contained in Annexure to this notification. The policy shall come into force w.e.f. 23rd August, 2010.

This issues in public interest.

[F.No. 01/94/180/Foreign Trade Policy/AM-11/PC-4]

P. K. CHAUDHERY, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

ANNEXURE

Foreign Trade Policy

27th August, 2009 — 31st March, 2014

(w.e.f. 23-08-2010)

GLOSSARY (ACRONYMS)

<u>Acronym</u>	<u>Explanation</u>
ACC	Assistant Commissioner of Customs
ACU	Asian Clearing Union
AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayaat Niryaat Form
ARO	Advance Release Order
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BOA	Board of Approval
BOT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Biotechnology Park
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CIF	Cost, Insurance & Freight
CIS	Commonwealth of Independent States
CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DoBT	Department of Bio Technology
DC	Development Commissioner
DEPB	Duty Entitlement Passbook Scheme
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DFRC	Duty Free Replenishment Certificate
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics
DGFT	Director General of Foreign Trade
DIPP	Department of Industrial Policy & Promotion
DoC	Department of Commerce
DoE	Department of Electronics
DoIT	Department of Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Tourism
DTA	Domestic Tariff Area
EDI	Electronic Data Interchange
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EH	Export House
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council
EO	Export Obligation

EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council
EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Process Outsourcing
FDI	Foreign Direct Investment
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FMS	Focus Market Scheme
FOB	Free On Board
FPS	Focus Product Scheme
FT (D&R) Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)
FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
GATS	General Agreement on Trade in Services
GRC	Grievance Redressal Committee
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Process
HBP v1	Handbook of Procedures (Vol.1)
HBP v2	Handbook of Procedures (Vol.2)
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) Classification for Export & Import Items, 2004-2009
ITPO	India Trade Promotion Organisation
LoC	Line of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Undertaking
MAI	Market Access Initiative
MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NOC	No Objection Certificate
PRC	Policy Relaxation Committee
PTH	Premier Trading House
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
REP	Replenishment
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
RSCQC	Regional Sub-Committee on Quality Complaints
S/B	Shipping Bill
SEH	Star Export House
SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SFIS	Served from India Scheme
SIA	Secretariat for Industrial Assistance

SION	Standard Input Output Norms
SSI	Small Scale Industry
STE	State Trading Enterprise
STH	Star Trading House
STP	Software Technology Park
TEE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TRA	Telegraphic Release Advice
TRQ	Tariff Rate Quota
VA	Value Addition
VKGUY	Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices

CHAPTER 1 A

LEGAL FRAMEWORK

Foreword	1.1	The Foreword spells out the broad framework
Duration	1.2	<p>The Foreign Trade Policy, 2009-2014 (FTP), incorporating provisions relating to export and import of goods and services, shall come into force with effect from 27th August, 2009 and shall remain in force upto 31st March, 2014 unless otherwise specified. All exports and imports upto 26th August 2009 shall be accordingly governed by the FTP 2004-2009.</p> <p>The Foreign Trade Policy, 2009-2014, incorporating the Annual Supplement as updated on 23rd August, 2010 shall come into force with effect from 23rd August, 2010, unless otherwise specified.</p>
Amendment	1.3	Central Government reserves right in public interest to make any amendments by notification to this Policy in exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act.
Transitional Arrangements	1.4	Authorisation issued before commencement of FTP shall continue to be valid for the purpose and duration for which such Authorisation was issued, unless otherwise stipulated.
	1.5	<p>In case an export or import that is permitted freely under FTP is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that shipment of export or import is made within original validity with respect to available balance and time period of an irrevocable commercial letter of credit, established before the date of imposition of such restriction.</p> <p>However for operationalizing such irrevocable commercial letter of credit, the applicant shall have to register the Letter of Credit and contract with the concerned RA within 15 days of the issue of any such restriction or regulation.</p>

CHAPTER 1 B

SPECIAL FOCUS INITIATIVES

Special Focus Initiatives

1B.1 With a view to continuously increasing our percentage share of global trade and expanding employment opportunities, certain special focus initiatives have been identified/continued for Market Diversification, Technological Upgradation, Support to status holders, Agriculture, Handlooms, Handicraft, Gems & Jewellery, Leather, Marine, Electronics and IT Hardware manufacturing Industries, Green products, Exports of products from North-East, Sports Goods and Toys sectors. Government of India shall make concerted efforts to promote exports in these sectors by specific sectoral strategies that shall be notified from time to time.

Further Sectoral Initiatives in other sectors will also be announced from time to time.

(i) Market Diversification

During 2008-09 and 2009-10, weaker demand in developed economies, triggered by falling asset prices and increased economic uncertainty had pulled down the growth of India's exports to developed countries. To insulate Indian exports from the decline in demand from developed countries, in this Policy, focus is on diversification of Indian exports to other markets, specially those located in Latin America, Africa, parts of Asia and Oceania. To achieve diversification of Indian exports, following initiatives have been taken under this Policy.

- (a) 27 new countries have been included within the ambit of Focus Market Scheme.
- (b) The incentives provided under Focus Market Scheme have been increased from 2.5% to 3%.
- (c) There has been a significant increase in the outlay under "Market Linked Focus Product Scheme" by inclusion of more markets and products. This ensures support for exports to all countries in Africa and Latin America, and major Asian markets like China and Japan.

(ii) Technological Upgradation

To usher in the next phase of export growth, India needs to move up in the value chain of export goods. This objective is

sought to be achieved by encouraging technological upgradation of our export sector. A number of initiatives have been taken in this Policy to focus on technological upgradation; such initiatives include:

- (a) EPCG Scheme at zero duty has been introduced for certain engineering products, electronic products, basic chemicals and pharmaceuticals, apparel and textile, plastics, handicrafts, chemicals and allied products and leather and leather products. This scheme is being expanded to cover more export product groups including marine products, sports goods, toys, rubber & rubber products, additional chemicals / allied products and additional engineering products. The scheme is also being extended upto 31.3.2012.
- (b) The existing 3% EPCG Scheme has been considerably simplified, to ease its usage by the exporters.
- (c) The facility of EPCG Scheme for Annual Requirement is being introduced to reduce documentation and transaction time.
- (d) To encourage value added manufacture export, a minimum 15% value addition on imported inputs under Advance Authorisation Scheme has been stipulated.
- (e) A number of products including automobiles and other engineering products have been included for incentives under Focus Product, and Market Linked Focus Product Schemes.
- (f) Steps to encourage Project Exports shall be taken.

(iii) Support to status holders

The Government recognized 'Status Holders' contribute approx. 60% of India's goods exports. To incentivise and encourage the status holders, as well as to encourage Technological upgradation of export production, additional duty credit scrip @ 1% of the FOB value of past export shall be granted for specified product groups including leather, specific sub-sectors in engineering, textiles, plastics, handicrafts and jute. This duty credit scrip can be used for

import of capital goods by these status holders. The imported capital goods shall be subject to actual user condition. The status holder incentive scrip scheme is being expanded to cover more export product groups including marine products, sports goods, toys, specified chemicals and allied products and additional engineering products. The scheme is also being extended upto 31.3.2012.

(iv) Agriculture and Village Industry

- (a) Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana.
- (b) Capital goods imported under EPCG will be permitted to be installed anywhere in AEZ.
- (c) Import of restricted items, such as panels, are allowed under various export promotion schemes.
- (d) Import of inputs such as pesticides are permitted under Advance Authorisation for agro exports.
- (e) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 150 crore shall be notified.
- (f) Additional flexibility for agri-infra scrip by way of limited transferability to other status holders and the units in Food Parks allowed.

(v) Handlooms

- (a) 2% bonus benefits under focus product scheme.
- (b) Specific funds are earmarked under MAI / MDA Schemes for promoting handloom exports.
- (c) Duty free import entitlement of specified trimmings and embellishments is 5% of FOB value of exports during previous financial year. Handloom made-ups have also been included for the entitlement.
- (d) Duty free import entitlement of hand knotted carpet samples is 1% of FOB value of exports during previous financial year.
- (e) Duty free import of old pieces of hand knotted carpets on consignment basis for re-export after repair is permitted.

- (f) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 150 crore shall be notified.
- (g) Machinery and equipment for effluent treatment plants is exempt from customs duty.

(vi) Handicrafts

- (a) Duty free import entitlement of tools, trimmings and embellishments is 5% of FOB value of exports during previous financial year. Entitlement is broad banded, and shall extend also to merchant exporters tied up with supporting manufacturers.
- (b) Handicraft EPC is authorized to import trimmings, embellishments and consumables on behalf of those exporters for whom directly importing may not be viable.
- (c) Specific funds are earmarked under MAI & MDA Schemes for promoting Handicraft exports.
- (d) CVD is exempted on duty free import of trimmings, embellishments and consumables.
- (e) New towns of export excellence with a reduced threshold limit of Rs 150 crore shall be notified.
- (f) Machinery and equipment for effluent treatment plants are exempt from customs duty.
- (g) All handicraft exports would be treated as special Focus products and entitled to higher incentives.
- (h) In addition to above, 2% bonus benefits under Focus Product Scheme for Handicraft exports.

(vii) Gems & Jewellery

- (a) Import of gold of 8k and above is allowed under replenishment scheme, subject to import being accompanied by an Assay Certificate specifying purity, weight and alloy content.
- (b) Duty Free Import Entitlement (based on FOB value of exports during previous financial year) of

Consumables, Tools and additional items allowed for:

1. Jewellery made out of:

- (a) Precious metals
(other than Gold & Platinum) – 2%
- (b) Gold and Platinum – 1%
- (c) Rhodium finished Silver – 3%

2. Cut and Polished Diamonds – 1%

- (c) Duty free import entitlement of commercial samples shall be Rs. 300,000.
- (d) Duty free re-import entitlement for rejected jewellery shall be 2% of FOB value of exports.
- (e) Import of Diamonds on consignment basis for Certification / Grading & re-export by the authorized offices / agencies of Gemological Institute of America (GIA) in India or other approved agencies will be permitted.
- (f) Personal carriage of Gems & Jewellery products in case of holding / participating in overseas exhibitions increased to US\$ 5 million and to US\$ 1 million in case of export promotion tours.
- (g) Extension in number of days for re-import of unsold items in case of participation in an exhibition in USA, increased to 90 days.
- (h) In an endeavour to make India a diamond international trading hub, it is planned to establish "Diamond Bourse(s)".

(viii) Leather and Footwear

- (a) Additional 2% bonus benefits under Focus Product Scheme.
- (b) Finished Leather exports to be incentivized under Focus Product Scheme.
- (c) Duty free import entitlement of specified items is 3% of FOB value of exports of leather garments during preceding financial year.
- (d) Duty free entitlement for import of trimmings, embellishments and footwear components for

footwear (leather as well as synthetic), gloves, travel bags and handbags is 3% of FOB value of exports of previous financial year. Such entitlement shall also cover packing material, such as printed and non-printed shoeboxes, small cartons made of wood, tin or plastic materials for packing footwear.

- (e) Machinery and equipment for Effluent Treatment Plants shall be exempted from basic customs duty.
- (f) Re-export of unsuitable imported materials such as raw hides & skins and wet blue leathers is permitted.
- (g) CVD is exempted on lining and interlining material notified at S.No 168 of Customs Notification No 21/2002 dated 01.03.2002.
- (h) CVD is exempted on raw, tanned and dressed fur skins falling under Chapter 43 of ITC (HS).
- (i) Re-export of unsold hides, skins and semi finished leather shall be allowed from Public Bonded warehouse without payment of export duty.

(ix) Marine Sector

- (a) Imports for technological upgradation under EPCG in fisheries sector (except fishing trawlers, ships, boats and other similar items) exempted from maintaining average export obligation.
- (b) Duty free import of specified specialised inputs / chemicals and flavouring oils is allowed to the extent of 1% of FOB value of preceding financial year's export.
- (c) To allow import of monofilament longline system for tuna fishing at a concessional rate of duty and Bait Fish for tuna fishing at Nil duty.
- (d) A self removal procedure for clearance of seafood waste is applicable subject to prescribed wastage norms.
- (e) Marine products are incentivized at special higher rate under VKGUY scheme.
- (f) Marine sector included for benefits under zero duty EPCG scheme.

(x) Electronics and IT Hardware Manufacturing Industries

- (a) Export of electronic goods to be incentivized under Focus Product Scheme.
- (b) Expeditious clearance of approvals required from DGFT, shall be ensured.
- (c) Exporters /Associations would be entitled to utilize MAI & MDA Schemes for promoting Electronics and IT Hardware Manufacturing industries exports.
- (d) Electronics Sector included for benefits under SHIS scheme.

(xi) Sports Goods and Toys

- (a) Duty free import of specified specialised inputs allowed to the extent of 3% of FOB value of preceding financial year's export.
- (b) Sports goods and toys shall be treated as a Priority sector under MDA / MAI Scheme. Specific funds would be earmarked under MAI / MDA Scheme for promoting exports from this sector.
- (c) Applications relating to Sports Goods and Toys shall be considered for fast track clearance by DGFT.
- (d) Sports Goods and Toys are treated as special focus products and entitled to higher incentives.
- (e) In addition to above, 2% bonus benefits under Focus Product Scheme for Sports Goods & Toys.
- (f) Sports goods & Toys included for benefits under zero duty EPCG and SHIS schemes.

(xii) Green products and technologies

India aims to become a hub for production and export of green products and technologies. To achieve this objective, special initiative will be taken to promote development and manufacture of such products and technologies for exports. To begin with, focus would be on items relating to transportation, solar and wind power generation and other products as may be notified, which will be incentivized under Reward Schemes of Chapter 3 of FTP.

(xiii) Incentives for Exports from the North Eastern Region

In order to give a fillip to exports of products from the north-eastern States, notified products of this region would be incentivized under Reward Schemes of Chapter 3 of FTP.

CHAPTER 1 C

Board of Trade

Board of Trade (BOT)

1C.1 BOT has a clear and dynamic role in advising government on relevant issues connected with Foreign Trade.

Terms of Reference

1C.2 BOT has following terms of reference:

- I To advise Government on Policy measures for preparation and implementation of both short and long term plans for increasing exports in the light of emerging national and international economic scenarios;
- II To review export performance of various sectors; identify constraints and suggest industry specific measures to optimize export earnings;
- III To examine existing institutional framework for imports and exports and suggest practical measures for further streamlining to achieve desired objectives;
- IV To review policy instruments and procedures for imports and exports and suggest steps to rationalize and channelize such schemes for optimum use;
- V To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade, and to strengthen international competitiveness of Indian goods and services; and
- VI To commission studies for furtherance of above objectives.

Composition

1C.3 Commerce & Industry Minister will be the Chairman of the Board of Trade (BOT). Government shall also nominate upto 25 persons, of whom at least 10 will be experts in trade policy. In addition, Chairmen of recognized EPCs and President or Secretary-Generals of National Chambers of Commerce will be ex-officio members. BOT will meet at least once every quarter.

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

*Exports and Imports
free unless regulated*

- 2.1 Exports and Imports shall be free, except where regulated by FTP or any other law in force. The item wise export and import policy shall be, as specified in ITC (HS) notified by DGFT, as amended from time to time.

Import of rough diamond from Cote d'Ivoire shall be prohibited in compliance to Paragraph 6 of UN Security Council Resolution (UNSCR) 1643(2005).

The import/export of rough diamond (HS Code 710210, 710221 or 710231) from / to Venezuela shall be prohibited in view of voluntary separation of Venezuela from the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). No Kimberley Process Certificate shall be accepted / endorsed / issued for import and export of rough diamonds from / to Venezuela.

- 2.1.1 Import / export of arms and related material from / to Iraq shall be prohibited.

- 2.1.2 Direct or indirect export and import of following items, whether or not originating in Democratic People's Republic of Korea (DPRK), to / from, DPRK is prohibited:

All items, materials equipment, goods and technology including as set out in lists in documents S/2006/814, S/2006/815 (including S/2009/205), S/2009/364 and S/2006/853 (United Nations Security Council Documents) INFCIRC/254/Rev.9/Part1a and INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a (IAEA documents) which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.

- 2.1.3 Direct or indirect export and import of all items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water related activities, or to development of nuclear weapon delivery systems, as mentioned below, whether or not originating in Iran, to / from Iran is prohibited:

i) items, listed in INFCIRC/254/Rev8/Part I in document S/2006/814, in Sections B.2 to B.7 as well as A.I and B.I except supply, sale or transfer of equipment covered by B.I when such equipment is for light water reactors and low-enriched uranium covered by A.1.2 when it is incorporated in assembled nuclear fuel elements for such reactors;

ii) items listed in S/2006/815 except sale or transfer of items covered by 19.A.3 of Category II.

Above-mentioned UN Security Council documents are accessible from DGFT web site.

Compliance with Laws 2.2

Every exporter or importer shall comply with the provisions of FT (D&R) Act, the Rules and Orders made thereunder, FTP and terms and conditions of any Authorisation granted to him. All imported goods shall also be subject to domestic Laws, Rules, Orders, Regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods. No import or export of rough diamonds shall be permitted unless accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate as specified by Gem & Jewellery EPC (GJEPC).

Interpretation of Policy 2.3

If any question or doubt arises in respect of interpretation of any provision contained in FTP, or classification of any item in ITC (HS) or HBP v1 or HBP v2, or Schedule of DEPB Rates (including content, scope or issue of an authorization there under) said question or doubt shall be referred to DGFT whose decision thereon shall be final and binding.

Procedure 2.4

DGFT may, specify procedure to be followed for an exporter or importer or by any licensing or any other competent authority for purpose of implementing provisions of FT (D&R) Act, the Rules and the Orders made there under and FTP. Such procedures shall be published by means of a Public Notice, and may, in like manner, be amended from time to time.

Exemption from Policy / Procedure 2.5

DGFT may pass such orders or grant such relaxation or relief, as he may deem fit and proper, on grounds of genuine hardship and adverse impact on trade.

DGFT may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of FTP or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit. Such request may be considered only after consulting committees as under:

Sl.No:	Description	Committee
(i)	Fixation / modification of product norms under all schemes	Norms Committee
(ii)	Nexus with Capital Goods (CG) and benefits under EPCG Schemes	EPCG Committee
(iii)	All other issues	Policy Relaxation Committee (PRC)

Principles of Restriction	2.6	<p>DGFT may, through a notification, adopt and enforce any measure necessary for: -</p> <ol style="list-style-type: none"> Protection of public morals. Protection of human, animal or plant life or health. Protection of patents, trademarks and copyrights and the prevention of deceptive practices. Prevention of use of prison labour. Protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value. Conservation of exhaustible natural resources. Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; and Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war.
Restricted Goods	2.7	Any goods, export or import of which is restricted under ITC(HS) may be exported or imported only in accordance with an Authorisation or in terms of a public notice issued in this regard.
Terms and Conditions of a licence / Certificate / Permission / Authorisation	2.8	<p>Every Authorisation shall be valid for prescribed period of validity and shall contain such terms and conditions as may be specified by RA which may include:</p> <ol style="list-style-type: none"> Quantity, description and value of goods; Actual User condition; Export obligation; Value addition to be achieved; and Minimum export / import price.
Authorisation / Licence / Certificate / Permission not a Right	2.9	No person may claim an Authorization as a right and DGFT or RA shall have power to refuse to grant or renew the same in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules made there under and FTP.
Penalty	2.10	If an Authorisation holder violates any condition of such Authorisation or fails to fulfill export obligation, he shall be liable for action in accordance with FT (D&R) Act, the Rules and Orders made there under, FTP and any other law for time being in force.
State Trading	2.11	Any goods, import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to STE(s), may be imported or exported by STE(s) as per conditions specified in ITC (HS). DGFT may, however, grant an Authorisation to

any other person to import or export any of these goods.

Such STE(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale in a non discriminatory manner and shall afford enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.

**Importer-Exporter
Code (IEC) Number** 2.12

No export or import shall be made by any person without an IEC number unless specifically exempted. An IEC number shall be granted on application by competent authority in accordance with procedure specified in HBP v1.

**Trade with
Neighbouring
Countries** 2.13

DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.

Transit Facility 2.14

Transit of goods through India from / or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with bilateral treaties between India and those countries and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions.

**Trade with Russia
under Debt-Repayment
Agreement** 2.15

In case of trade with Russia under Debt Repayment Agreement, DGFT may issue instructions or frame schemes as may be required, and anything contained in FTP, in, so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.

Actual User Condition 2.16

Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person.

However, if such imports require an Authorisation, actual user alone may import such goods unless actual user condition is specifically dispensed with by RA.

Second Hand Goods 2.17

All second hand goods, except second hand capital goods, shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with provisions of FTP, ITC (HS), HBP v1, Public Notice or an Authorisation issued in this regard.

Import of second hand capital goods, including refurbished / re-conditioned spares shall be allowed freely. However, second hand personal computers / laptops, photocopier machines, air conditioners, diesel generating sets will only be allowed against a licence.

		Import of re-manufactured goods shall be allowed only against a licence.
Scrap/Waste in SEZ	2.17A	Any waste or scrap or remnant including any form of metallic waste & scrap generated during manufacturing or processing activities of an SEZ Unit/ Developer/Co-developer shall be allowed to be disposed in DTA freely subject to payment of applicable Customs Duty.
Import of samples	2.18	Import of samples shall be governed by HBP v1.
Import of Gifts	2.19	Import of gifts shall be permitted where such goods are otherwise freely importable under FTP. In other cases, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required from DGFT.
Passenger Baggage	2.20	Bonafide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per limits, terms and conditions thereof in Baggage Rules notified by Ministry of Finance. Samples of such items that are otherwise freely importable under FTP may also be imported as part of passenger baggage without an Authorisation. Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without an Authorisation.
Import on Export basis	2.21	Freely exportable new or second hand capital goods, equipments, components, parts and accessories, containers meant for packing of goods for exports, jigs, fixtures, dies and moulds may be imported for export without an Authorisation on execution of LUT / BG with Customs Authorities.
Re-import of goods repaired abroad	2.22	Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and reimported without an Authorisation.
Import of goods used in projects abroad	2.23	After completion of projects abroad, project contractors may import, without an Authorisation used goods including capital goods provided they have been used for at least one year.
Sale on High Seas	2.24	Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to FTP or any other law in force.
Import under Lease Financing	2.25	Permission of RA is not required for import of capital goods under lease financing.
Clearance of Goods from Customs	2.26	Goods already imported / shipped / arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against an Authorisation issued subsequently.

Execution of BG / LUT 2.27

Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, importer shall execute prescribed LUT / BG / Bond with Customs Authority before clearance of goods. In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish LUT / BG / Bond to RA concerned before sourcing material from indigenous supplier / nominated agency as prescribed in HBP vI.

Private / Public Bonded Warehouses for Imports 2.28

Private / Public bonded warehouses may be set up in DTA as per terms and conditions of notification issued by DoR.

Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such bonded warehouses.

Such goods may be cleared for home consumption in accordance with provisions of FTP and against Authorisation, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.

If such goods are not cleared for home consumption within a period of one year or such extended period as the custom authorities may permit, importer of such goods shall re-export the goods.

Free Exports

2.29

All goods may be exported without any restriction except to the extent that such exports are regulated by ITC (HS) or any other provision of FTP or any other law for the time being in force.

DGFT may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in ITC (HS), may be exported without an Authorisation.

Export of Samples

2.30

Export of samples and Free of charge goods shall be governed by provisions given in HBP vI.

Export of Passenger Baggage

2.31

Bonafide personal baggage may be exported either along with passenger or, if unaccompanied, within one year before or after passenger's departure from India. However, items mentioned as restricted in ITC (HS) shall require an Authorisation. Government of India officials proceeding abroad on official postings shall, however, be permitted to carry alongwith their personal baggage, food items (free, restricted or prohibited) strictly for their personal consumption.

Export of Gifts

2.32

Goods, including edible items, of value not exceeding Rs.5,00,000 /- in a licensing year, may be exported as a gift.

		However, items mentioned as restricted for exports in ITC (HS) shall not be exported as a gift, without an Authorisation.
Export of Spares	2.33	Warranty spares (whether indigenous or imported) of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods, (except those restricted under ITC (HS)) may be exported along with main equipment or subsequently but within contracted warranty period of such goods subject to approval of RBI.
Third Party Exports	2.34	Third party exports, as defined in Chapter 9 shall be allowed under FTP.
Export of Imported Goods	2.35	Goods imported, in accordance with FTP, may be exported in same or substantially the same form without an Authorisation provided that item to be imported or exported is not restricted for import or export in ITC (HS).
		Exports of such goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted against payment in freely convertible currency.
	2.36	Goods, including those mentioned as restricted for import (except prohibited items) may be imported under Customs Bond for export in freely convertible currency without an Authorisation provided that item is freely exportable without any conditionality / requirement of Licence / permission as may be required under ITC (HS) Schedule II.
	2.36 A	Hides, Skins and semi finished leather may be imported in the Public Bonded warehouse for the purpose of DTA sale and the unsold items thereof can be re-exported from such bonded warehouses at 50% of the applicable export duty. However, this facility shall not be allowed for import under Private Bonded warehouse.
Export of Replacement Goods	2.37	Goods or parts thereof on being exported and found defective / damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by Customs authorities, provided that replacement goods are not mentioned as restricted items for exports in ITC (HS).
Export of Repaired Goods	2.38	Goods or parts, except restricted under ITC (HS) thereof, on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export.
		Such goods shall be allowed clearance without an Authorisation and in accordance with customs notification.

Private Bonded Warehouses for Exports	2.39	<p>Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per terms and conditions of notifications issued by DoR.</p> <p>Such warehouses shall be entitled to procure goods from domestic manufacturers without payment of duty. Supplies made by a domestic supplier to such notified warehouses shall be treated as physical exports provided payments are made in free foreign exchange.</p>
Denomination of Export Contracts	2.40	<p>All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but export proceeds shall be realised in freely convertible currency.</p> <p>However, export proceeds against specific exports may also be realized in rupees, provided it is through a freely convertible Vostro account of a non resident bank situated in any country other than a member country of ACU or Nepal or Bhutan. Additionally, rupee payment through Vostro account must be against payment in free foreign currency by buyer in his non-resident bank account. Free foreign exchange remitted by buyer to his non-resident bank (after deducting the bank service charges) on account of this transaction would be taken as export realization under export promotion schemes of FTP.</p> <p>Contracts [for which payments are received through Asian Clearing Union (ACU)] shall be denominated in ACU Dollar. Central Government may relax provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and Invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank / Government of India line of credit.</p>
Realisation of Export Proceeds	2.41	<p>If an exporter fails to realise export proceeds within time specified by RBI, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law in force, be liable to action in accordance with provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under and FTP.</p>
Free movement of export goods	2.42	<p>Consignments of items meant for exports shall not be withheld/ delayed for any reason by any agency of Central / State Government. In case of any doubt, authorities concerned may ask for an undertaking from exporter.</p>
No seizure of Stock	2.42.1	<p>No seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt manufacturing activity and delivery schedule of exports. In exceptional cases, concerned agency may seize the stock on basis of prima facie evidence. However, such seizure should be lifted within 7 days.</p>
Export Promotion Councils (EPC)	2.43	<p>Basic objective of Export Promotion Councils (EPCs) is to promote and develop Indian exports. Each Council is responsible for promotion of a particular group of products, projects and services as given in HBP-v1.</p>

Registration -cum- Membership Certificate (RCMC)	2.44	Any person, applying for: <ul style="list-style-type: none"> (i) an Authorisation to import / export, [except items listed as restricted items in ITC(HS)] or (ii) any other benefit or concession under FTP <p>shall be required to furnish RCMC granted by competent authority in accordance with procedure specified in HBP-vI unless specifically exempted under FTP.</p> <p>Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) issued by Spices Board shall be treated as Registration-Cum-Membership Certificate (RCMC) for the purposes under this Policy.</p>
Trade Facilitation through EDI Initiatives	2.45	It is endeavor of Government to work towards greater simplification, standardization and harmonization of trade documents using international best practices. As a step in this direction, DGFT, shall move towards an automated environment for electronic filing, retrieval and authentication of documents based on agreed protocols and message exchange with other community partners including Customs and Banks.
DGCI&S Commercial Trade Data	2.45.1	To enable users to make commercial decisions in a more professional manner, DGCI&S trade data shall be made available with a minimum time lag in a query based structured format on a commercial criteria.
Fiscal Incentives to promote EDI Initiatives adoption	2.45.2	With a view to promote use of Information Technology, DGFT will provide fiscal incentives to user community. Deductions in Application Fee would be admissible for applications signed digitally or / and where application fee is paid electronically through EFT (Electronic Fund Transfer). Details are enumerated in HBP vI.
Regularization of EO default and settlement of customs duty and interest through Settlement Commission	2.46	With a view to providing assistance to firms who have defaulted under FTP for reasons beyond their control as also facilitating merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been decided to empower Settlement Commission in Central Board of Excise and Customs to decide such cases also with effect from 01.04.2005.
Easing of Documentation Requirement	2.47	Pending finalisation of Single Common Document (SCD) for international trade, Government Departments dealing with exports and imports will honour Authorisation issued by other Government departments based on verification of export documents like shipping bill, bank realization certificate, packing list, bill of lading etc. and will not insist upon fresh submission of these documents.

Exemption / Remission of Service Tax in DTA	2.48	For all goods and services which are exported from units in DTA and units in EOU / EHTP / STP / BTP exemption / remission of service tax levied and related to exports, shall be allowed, as per prescribed procedure in Chapter 4 of HBP v1.
Exemption from Service Tax in SEZ	2.48.1	Units in SEZ shall be exempted from service tax.
Exemption from Service Tax on Services received abroad	2.48.2	For all goods and services exported from India, services received / rendered abroad, where ever possible, shall be exempted from service tax.

GRIEVANCE REDRESSAL

DGFT as a facilitator of exports / imports	2.49	DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. Focus is on good governance, which depends on clean, transparent and accountable delivery systems.
Citizen's Charter	2.49.1	DGFT has in place a Citizen's Charter, giving time schedules for providing services to clients, and details of grievance committees at different levels.
Grievance Redressal Committee (GRC)	2.49.2	In order to facilitate speedy redressal of grievances of trade and industry, a new grievance redressal mechanism has been put in place in the form of GRC by a Government Resolution. The Government is committed to resolving all outstanding problems and disputes pertaining to past policy periods through GRC set up on 27.10.2004, for condoning delays, regularizing breaches by exporters in bonafide cases, resolving disputes over entitlements, granting extensions for utilization of Authorisations.
Export of perishable agricultural products	2.50	To reduce transaction and handling costs, a single window system to facilitate export of perishable agricultural produce has been introduced. The system will involve creation of multi-functional nodal agencies to be accredited by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi. The detailed procedures have been notified at Appendix 40 to HBP v1.

CHAPTER 3

PROMOTIONAL MEASURES

PROMOTIONAL MEASURES IN DEPARTMENT OF COMMERCE

Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE)

- 3.1 Scheme for Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) is formulated to involve the States in the export effort by providing assistance to the States Governments for creating appropriate infrastructure for the development and growth of exports. The Scheme is administered by Department of Commerce (DoC).

The objective of scheme is to establish a mechanism for involving the State Governments to participate in funding of infrastructure critical for growth of exports by providing export performance linked financial assistance to them.

The activities aimed at development of infrastructure for exports can be funded from the scheme provided such activities have overwhelming export content and their linkage with exports is full established. The specific purposes for which funds allocated under the Scheme can be sanctioned and utilized are as follows:

- Creation of new Export Promotion Industrial Parks/Zones (SEZs/Agri Business Zones) and augmenting facilities in the existing ones.
- Setting up of electronics and other related infrastructure in export conclave.
- Equity participation in infrastructure projects including the setting up of SEZs.
- Meeting requirements of capital outlay of EIPs/EPZs/SEZs.
- Development of complementary infrastructure such as, roads connecting the production centres with the ports, setting up of Inland Container Depots and Container Freight Stations.

- Stabilizing power supply through additional transformers and islanding of export production centre etc.
- Development of minor ports and jetties to serve export purpose.
- Assistance for setting up Common Effluent Treatment facilities and
- Any other activity as may be notified by DoC.

Details of ASIDE Scheme are available at

<http://www.commerce.nic.in> or

<http://www.commerce.gov.in>.

**Market Access
Initiative (MAI)**

3.2

Under MAI scheme, Financial assistance is provided for export promotion activities on focus country, focus product basis. Financial assistance is available for Export Promotion Councils (EPCs), Industry and Trade Associations (ITAs), Agencies of State Government, Indian Commercial Missions (ICMs) abroad and other national level institutions/eligible entities as may be notified.

A whole range of activities can be funded under MAI scheme. These include, amongst others,

- i. Market studies/surveys,
- ii. Setting up of showroom / warehouse,
- iii. Participation in international trade fairs,
- iv. Displays in International departmental stores,
- v. Publicity campaigns,
- vi. Brand promotion,
- vii. Reimbursement of registration charges for pharmaceuticals and expenses for carrying out clinical trials etc., in fulfillment of statutory requirements in the buyer country,
- viii. Testing charges for engineering products abroad.
- ix. Assistance for contesting Anti Dumping litigations etc.

Each of these export promotion activities can receive financial assistance from Government ranging from 25% to 100% of total cost depending upon activity and implementing agency.

Full text of guidelines is available at
<http://commerce.nic.in>.

**Marketing
Development
Assistance (MDA)**

3.3

Under MDA Scheme, financial assistance is provided for a range of export promotion activities implemented by EPCs and Trade Promotion Organizations on the basis of approved annual action plans. The scheme is administered by DOC. Assistance includes, amongst others, participation in:

- i. Trade Fairs and Buyer Seller meets abroad or in India; and
- ii. Export promotions seminars.
- iii. Financial assistance with travel grant is available to exporters traveling to focus areas, viz., Latin America, Africa, CIS region, ASEAN countries, Australia and New Zealand. In other areas, financial assistance without travel grant is available.

MDA assistance is available for exports having an annual export turnover as prescribed in MDA guidelines. Full text of guidelines is available at <http://commerce.nic.in>.

**Meeting expenses for
statutory compliances
in buyer country for
Trade Related Matters**

3.4

DOC provides for reimbursement of charges/expenses for fulfilling statutory requirements in the buyer country, including registration charges for product registration for pharmaceuticals, bio-technology and agro-chemicals products on recommendation of EPCs. Financial assistance is also provided for contesting litigation(s) in the foreign country concerning restrictions/anti dumping duties etc on particular product(s) of Indian origin, as provided under the Market Access Initiative (MAI) Scheme of DOC.

**Towns of Export
Excellence (TEE)**

3.5

A number of towns have emerged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximizing their potential and enabling them to move higher in the value chain and tap new markets.

Selected towns producing goods of Rs. 750 Crore or more will be notified as TEE based on potential for growth in

exports. However for TEE in Handloom, Handicraft, Agriculture and Fisheries sector, threshold limit would be Rs 150 Crores.

- (i) Recognized associations of units will be provided financial assistance under MAI scheme, on priority basis, for export promotion projects for marketing, capacity building and technological services.
- (ii) Common Service Providers in these areas shall be entitled for EPCG scheme.
- (iii) The projects received from TEEs shall be accorded priority by SLEPC for financial assistance under ASIDE.

Notified Towns (TEEs) are listed in Appendix 7 of HBPv1.

Brand Promotion and Quality

IBEF (originally called India Brand Equity Fund and later renamed as India Brand Equity Foundation) was set up by the Ministry of Commerce on 11th July, 1996, with the primary objective to promote and create international awareness of the "Made in India" label in markets overseas. IBEF aims to promote India as a business opportunity by creating positive economic perceptions of India globally as well as effectively present the India business perspective and leverage business partnerships in a globalised market-place.

DOC provides funds for capacity building for up-gradation of quality to national level Institutions and EPCs to organize training programmes for the skill improvement of the exporters for quality up-gradation, reduction in rejection, product improvement etc. as provided under the Market Access Initiative (MAI) Scheme of DOC.

Test Houses

Central Government will assist in modernization and upgradation of test houses and laboratories to bring them at par with international standards.

PROMOTIONAL MEASURES IN DGFT***Quality Complaints /
Disputes*** 3.8

Regional Sub-Committee on Quality Complaints (RSCQC) set up at Regional Offices of this Directorate shall investigate quality complaints received from foreign buyers. Guidelines for settlement of quality complaints, in particular, and such other complaints, in general, are given in Appendix-16 of HBPv1.

***Trade Disputes
affecting Trade
Relations*** 3.9

If it comes to DGFT's notice or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner that:

- (i) is gravely prejudicial to trade relations of India with any other country; and / or
- (ii) is gravely prejudicial to interest of other persons engaged in exports or imports; and / or
- (iii) has brought disrepute to the country;

DGFT may take action against such exporter or importer in accordance with FT(D&R) Act, Rules and Orders made there-under and FTP.

3.10 **EXPORT AND TRADING HOUSES*****Eligibility for Export
and Trading Houses
Status*** 3.10.1

Merchant as well as Manufacturer Exporters, Service Providers, Export Oriented Units (EOUs) and Units located in Special Economic Zones (SEZs), Agri Export Zones (AEZs), Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology Parks (BTPs) shall be eligible for status.

Status Category

3.10.2

Applicant shall be categorized depending on his total FOB (FOR - for deemed exports) export performance during current plus previous three years (taken together) upon exceeding limit below. For Export House (EH) Status, export performance is necessary in at least two out of four years (i.e., current plus previous three years).

Status Category	Export Performance FOB / FOR Value (Rupees in Crores)
Export House (EH)	20
Star Export House (SEH)	100
Trading House (TH)	500
Star Trading House (STH)	2500
Premier Trading House (PTH)	7500

**Double Weightage and
Other Conditions for
Grant of Status**

3.10.3

- (i) Exporters in Small Scale Industry (SSI) / Tiny Sector / Cottage Sector, Units registered with KVICs / KVIBs, Units located in North Eastern States, Sikkim and Jammu & Kashmir, Units exporting handloom / handicrafts / hand knotted or silk carpets, exporters exporting to countries in Latin America / CIS / sub-Saharan Africa as listed in Appendix-9, Units having ISO 9000 (series) / ISO 14000 (series) / WHOGMP / HACCP / SEI CMM level-II and above status granted by agencies listed in Appendix-6 of HBP v1, exports of services and exports of agro products shall be entitled for double weightage on exports made for grant of status. Double Weightage shall be admissible to Merchant as well as Manufacturer Exporters. However, a shipment can get double weightage only once in any one of above categories.
- (ii) Transfer of export performance from one to another is not permitted. Therefore disclaimer system shall not be allowed for counting of export turnover.
- (iii) Exports made on re-export basis shall not be counted for recognition.
- (iv) Exports made by subsidiary of a limited company shall be counted towards export performance of limited company for recognition only if limited company has a majority share holding in subsidiary company.

***Privileges of Export
and Trading House
Status Holders***

3.10.4

A Status Holder shall be eligible for privileges as under:

- (i) Authorization and Customs Clearances for both imports and exports on self-declaration basis;
- (ii) Fixation of Input-Output norms on priority within 60 days;
- (iii) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. Remittance / Receipts, however, would be received through banking channels;
- (iv) 100% retention of foreign exchange in EEFC account;
- (v) Exemption from furnishing of BG in Schemes under FTP;
- (vi) SEHs and above shall be permitted to establish Export Warehouses, as per DoR guidelines.
- (vii) For status holders, a decision on conferring of ACP Status shall be communicated by Customs within 30 days from receipt of application with Customs.
- (viii) As an option, for Premier Trading House (PTH), the average level of exports under EPCG Scheme shall be the arithmetic mean of export performance in last 5 years, instead of 3 years.
- (ix) Status Holders of specified sectors shall be eligible for Status Holder Incentive Scrip under Para 3.16 of FTP.
- (x) Status Holders of Agri. Sector (Chapter 1 to 24) shall be eligible for Agri. Infrastructure Incentive Scrip under VKGUY – Para 3.13.4 of FTP.

3.11 SERVICES EXPORTS

Services Exports

- 3.11.1 Services include all 161 tradable services covered under General Agreement on Trade in Services (GATS) where payment for such services is received in free foreign exchange. A list of services is given in Appendix 10 of HBPv1.

All provisions of this Policy shall apply mutatis mutandis to export of services as they apply to goods.

Registration cum Membership Certificate (RCMC) for Service Providers

- 3.11.2 Software exporters shall register themselves with Electronics and Software EPC. Exporters of 15 specific services listed in Sl. No. 34 of Appendix 2 of HBPv1 are required to register themselves with Services EPC. Other service exporters shall register themselves with Federation of Indian Export Organisations (FIEO).

Common Facility Centres

- 3.11.3 Government shall promote establishment of Common Facility Centres for use by home-based service providers, particularly in areas like Engineering & Architectural Design, Multi-media operations, Software developers etc., in State and District level towns, to draw in a vast multitude of home-based professionals into services export arena.

REWARD / INCENTIVE SCHEMES IN DGFT

3.12 SERVED FROM INDIA SCHEME (SFIS)

Objective

- 3.12.1 Objective is to accelerate growth in export of services so as to create a powerful and unique 'Served From India' brand, instantly recognized and respected world over.

Eligibility

- 3.12.2 All Indian Service Providers, of services listed in Appendix 10 of HBPv1, who have free foreign exchange earning of at least Rs. 10 Lakhs in preceding financial year / current financial year shall qualify for Duty Credit Scrip.

For Individual Indian Service Providers, minimum free foreign exchange earnings would be Rs 5 Lakhs.

Ineligible Services and Service Providers	3.12.3	Services and Service Providers as listed in Para 3.6.1 of HB Pv1 shall not be entitled for benefits under the SFIS scheme.
Entitlement	3.12.4	All Service Providers shall be entitled to Duty Credit Scrip equivalent to 10% of free foreign exchange earned during current financial year.
Eligible Remittances	3.12.5	Free foreign exchange earned through International Credit Cards and other instruments as permitted by RBI for rendering of service shall also be taken into account for computation of Duty Credit Scrip.
Imports Allowed	3.12.6	<p>Duty Credit scrip may be used for import of any capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables; that are otherwise freely importable and / or restricted under ITC (HS). Imports shall relate to any service sector business of applicant.</p> <p>Utilization of Duty Credit scrip earned shall be permitted for payment of duty in case of import of only those vehicles, which are in the nature of professional equipment to the service provider.</p> <p>In case of hotels; clubs having residential facility of minimum 30 rooms, golf resorts and stand-alone restaurants having catering facilities, Duty Credit scrip may also be used for import of consumables including food items and alcoholic beverages.</p>
Non Transferability	3.12.7	Entitlement / goods (imported / procured) shall be non transferable (except within group company and managed hotels) and be subject to Actual User condition.
Procurement from Domestic Sources	3.12.8	Utilization of Duty Credit Scrip shall be permitted for payment of excise duty in terms of DoR notification issued in this behalf for procurement from domestic sources; of items permitted for imports under SFIS Duty Credit Scrip.

3.13 VISHESH KRISHI AND GRAM UDYOG YOJANA (VKGUY) (SPECIAL AGRICULTURE AND VILLAGE INDUSTRY SCHEME)

Objective

3.13.1 Objective of VKGUY is to promote exports of :

- (i) Agricultural Produce and their value added products;
- (ii) Minor Forest Produce and their value added variants;
- (iii) Gram Udyog Products;
- (iv) Forest Based Products; and
- (v) Other Products, as notified from time to time.

Such products shall be listed in Appendix 37A of HBPv1.

Entitlement

3.13.2 Duty Credit Scrip benefits are granted with an aim to compensate high transport costs, and to offset other disadvantages.

Exporters, of products notified in Appendix 37A of HBPv1, shall be entitled for Duty Credit Scrip equivalent to 5% of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards, unless a specific date of export / period is specified by public notice / notification.

However, for exports made w.e.f 27.8.2009, some Flowers, Fruits, Vegetables and other products, as listed in Table 2 of Appendix 37A shall be entitled to an additional duty credit scrip equivalent to 2% of FOB value of exports over and above the 5% or 3% VKGUY reduced rate entitlement available as per Para 3.13.3 below.

Applicability of Reduced Rate

3.13.3 Duty Credit Scrip benefits under VKGUY scheme shall be granted only at a reduced rate of 3% of FOB value of exports in such cases where exporter has also availed benefits of:

- (i) Drawback at rates higher than 1%; and/or
- (ii) Specific DEPB rate (i.e. other than Miscellaneous Category – Sr. Nos. 22D & 22C of Product Group 90); and/or

(iii) Advance Authorization or Duty Free Import Authorization Import of inputs (other than catalysts, consumables and packing materials)

for the exported product for which Duty Credit Scrip under VKGUY is being claimed.

**Agri. Infrastructure
Incentive Scrip**

3.13.4

For exports made during a particular year, all Status Holders (having status recognition for the current year) exporting products covered under ITC HS Chapters 1 to 24, shall be incentivized with duty credit scrip equal to 10% of FOB value of agricultural exports (including VKGUY benefits entitled under Policy Para 3.13.2) provided that the total benefits for all status holders put together does not exceed Rs 100 Cr (i.e. Rs 50 Cr for each half year) and the conditions specified in Para 3.4 of HBPv1 are satisfied.

Zonal Office, CLA, New Delhi shall be the licensing office for grant of the benefit to all status holders.

The following capital goods / equipments shall be permitted for import:

- (i) Cold storage units (including Controlled Atmosphere (CA) and Modified Atmosphere (MA) Stores); Pre-cooling Units and Mother Storage Units for Onions, etc.;
- (ii) Pack Houses (including facilities for handling, grading, sorting and packaging etc.);
- (iii) Reefer Van / Containers; and
- (iv) Other Capital Goods / Equipments as may be notified in Appendix 37F.

Imported capital goods/equipment shall be utilized for storage, packing etc. (as in (ii) above) and transportation of agricultural products (including agro-processed perishable products).

This additional benefit shall be subject to actual user condition and hence non-transferable.

However, for import of Cold Chain Equipment, this Incentive Scrip shall be freely transferable amongst Status Holders as well as to Units (the term 'Units' shall not include Developers) in the Food Parks.

3.14 FOCUS MARKET SCHEME (FMS)

Objective

3.14.1 Objective is to offset high freight cost and other externalities to select international markets with a view to enhance India's export competitiveness in these countries.

Entitlement

3.14.2 Exporters of all products to notified countries (as in Appendix 37C of HBPv1) shall be entitled for Duty Credit Scrip equivalent to 3% of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards, unless a specific date of export / period is specified by public notice / notification.

**Ineligible Exports
Categories / Sectors
for FMS**

3.14.3 The following categories of export products / sectors shall be ineligible for Duty Credit Scrip, under FMS scheme:

- a) Supplies made to SEZ units;
- b) Service Exports;
- c) Diamonds and other precious, semi precious stones;
- d) Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded Jewellery;
- e) Ores and Concentrates, of all types and in all forms;
- f) Cereals, of all types;
- g) Sugar, of all types and in all forms;
- h) Crude / Petroleum Oil & Crude / Petroleum based Products covered under ITC HS codes 2709 to 2715, of all types and in all forms; and
- i) Export of Milk and Milk Products covered under ITC HS Codes 0401 to 0406, 19011001, 19011010, 2105 & 3501.

3.15 **FOCUS PRODUCT SCHEME (FPS)****Objective**

- 3.15.1 Objective is to incentivise export of such products which have high export intensity / employment potential, so as to offset infrastructure inefficiencies and other associated costs involved in marketing of these products.

Entitlement

- 3.15.2 Exports of notified products (as in Appendix 37D of HBPv1) to all countries (including SEZ units) shall be entitled for Duty Credit scrip equivalent to 2% of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards, unless a specific date of export / period is specified by public notice / notification.

However, Special Focus Product(s) /sector(s), covered under Table 2 and Table 5 of Appendix 37D, shall be granted Duty Credit Scrip equivalent to 5% of FOB value of exports (in free foreign exchange) for exports made from 27.8.2009 onwards, unless a specific date of export / period is specified by public notice / notification.

Further, Focus Product(s) / sector(s) that are notified under Table 7 of Appendix 37D shall be granted additional Duty Credit Scrip equivalent to 2% of FOB value of exports (in free foreign exchange) over and above the existing rate for that product / sector from the admissible date of export / period specified in the public notice issued to notify the product / sector.

3.15.3 **Market Linked Focus Products Scrip (MLFPS):**

Export of Products/Sectors of high export intensity / employment potential (which are not covered under present FPS List) would be incentivized at 2% of FOB value of exports (in free foreign exchange) under FPS when exported to the Linked Markets (countries), which are not covered in the present FMS list, as notified in Appendix 37D of HBPv1, for exports made from 27.8.2009 onwards, unless a specific date of export / period is specified by public notice / notification.

3.16 Status Holders Incentive Scrip (SHIS)

- 3.16.1 With an objective to promote investment in upgradation of technology of some specified sectors as listed in Para 3.16.4 below, Status Holders shall be entitled to incentive scrip @1% of FOB value of exports made during 2009-10, 2010-11 and during 2011-12, of these specified sectors, in the form of duty credit.

The Status Holders of the additional sectors listed in the Para 3.10.8 of HBPv1 2009-14 (RE-2010) shall be eligible for this Status Holders Incentive Scrip on exports made during 2010-11 and 2011-12.

This shall be over and above any duty credit scrip claimed/availed under this chapter.

- 3.16.2 Status Holders availing Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) benefits (under Ministry of Textiles) during a particular year shall not be eligible for Status Holders Incentive Scrip for exports of that year.

- 3.16.3 The Status Holders Incentive Scrip shall be with Actual User Condition and shall be used for imports of capital goods (as defined in FTP) relating to the sectors specified in Para 3.16.4 below.

- 3.16.4 The Status Holders of the following Sectors shall be eligible for this Status Holders Incentive Scrip:

1. Leather Sector (excluding finished leather);
2. Textiles and Jute Sector;
3. Handicrafts;
4. Engineering Sector (excluding Iron & Steel, Non-ferrous Metals in primary or intermediate forms, Automobiles & two wheelers; nuclear reactors & parts and Ships, Boats and Floating Structures);
5. Plastics; and
6. Basic Chemicals (excluding Pharma Products).

The Status Holders of the additional sectors listed in the Para 3.10.8 of HBPv1 2009-14 (RE-2010) shall be eligible for this Status Holders Incentive Scrip on exports made during 2010-11 and 2011-12.

Special Provisions	3.17	Common Provisions of Duty Credit Scrips, except where specifically provided for.
	3.17.1	Government reserves the right in public interest, to specify export products or services or exports to such countries, which shall not be eligible for computation of entitlement.
		Further Government reserves the right to impose / change the rate / ceiling on Duty Credit Scrip under this chapter.
		Similarly, Government may also notify goods (in Appendix 37B of HBPv1), which shall not be allowed for import under Duty Credit Scrips.
Ineligible Exports Categories / Sectors	3.17.2	For VKGUY, FMS, FPS (including MLFPS) and Status Holders Incentive Scrip, the following exports categories / sectors shall be ineligible for Duty Credit Scrip entitlement: <ul style="list-style-type: none"> (i) EOUs / EHTPs / BTPs who are availing direct tax benefits / exemption; (ii) Export of imported goods covered under Para 2.35 of FTP; (iii) Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transshipped through India; (iv) Deemed Exports; (v) Exports made by SEZ units or SEZ products exported through DTA units; and (vi) Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS).
Counting of Commission in FOB value of Exports (in free foreign exchange)	3.17.3	For computation of Duty Credit Scrip Benefits, FOB Value of Exports (in free foreign exchange) shall include up to 12.5% Foreign Agency Commission.
Free Transferability	3.17.4	Duty Credit Scrip and items imported against it would be freely transferable.

However, Duty Credit Scrip under SFIS (Para 3.12) and under Status Holders Incentive Scrip (Para 3.16) shall not be freely transferable.

Imports Allowed

3.17.5

Duty Credit Scrip may be used for import of inputs or goods including capital goods, provided same is freely importable and / or restricted under ITC (HS). However, import of items listed in Appendix 37B of HBPv1 shall not be permitted to be debited.

Duty Credit Scripts under Chapter 3 of FTP can also be utilized for payment of duty against imports under EPCG scheme provided the item is importable against the scrip.

CENVAT / Drawback

3.17.6

Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Duty Credit scrip shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per DoR rules, except under SFIS.

TRA Facility

3.17.7

Utilization of Duty Credit Scrip for imports from a port other than port of registration shall be allowed under Telegraphic Release Advice (TRA) facility as per DoR notification.

Exclusivity of Entitlement

3.17.8

For a shipment, Duty Credit Scrip benefit under any one of the schemes covered in this Chapter can alone be claimed, at exporter's option.

Import under Lease financing

3.17.9

Utilization of Duty Credit Scrip shall be permitted for payment of duty in case of import of capital goods under lease financing in terms of provision in Para 2.25 of FTP.

Transfer of Export Performance

3.17.10

Transfer of export performance from one to another shall not be permitted. Thus, a shipment bill containing name of applicant shall be counted in export performance / turnover of applicant only if export proceeds from overseas are realized in applicant's bank account and this shall be evidenced from BRC / FIRC.

However, for VKGUY, FMS and FPS (including MLFPS), benefits can be claimed either by the supporting manufacturer (along with disclaimer from the company / firm who has realized the foreign exchange directly from overseas) or by the company / firm who has realized the foreign exchange directly from overseas.

Facility of Payment of Customs Duties in case of E.O. defaults	3.17.11	Duty Credit Scrips can also be used / debited towards payment of Customs Duties in case of EO defaults under Authorizations issued under Chapters 4 and 5 of the Policy. However, penalty / interest shall be required to be paid in cash.
---	---------	--

CHAPTER 4

DUTY EXEMPTION & REMISSION SCHEMES

Duty Exemption and Remission Schemes	4.1	Duty exemption schemes enable duty free import of inputs required for export production. Duty Exemption Schemes consist of (a) Advance Authorisation scheme and (b) Duty Free Import Authorisation (DFIA) scheme. A Duty Remission Scheme enables post export replenishment / remission of duty on inputs used in export product. Duty remission schemes consist of (a) Duty Entitlement Passbook (DEPB) Scheme and (b) Duty Drawback (DBK) Scheme.
---	-----	---

Re-import of exported goods under Duty Exemption / Remission Scheme	4.1.1	Goods exported under Advance Authorisation / DFIA / DEPB may be re-imported in same or substantially same form subject to DoR specified conditions.
--	-------	---

Value Addition	4.1.2	Value addition (VA) for the purpose of this Chapter (Except for Gems and Jewellery Sector) shall be:-
-----------------------	-------	---

$$VA = \frac{A - B}{B} \times 100, \text{ where}$$

A = FOB value of export realised / FOR value of supply received.

B = CIF value of inputs covered by authorisation, plus any other imported materials used on which benefit of DBK is claimed.

ADVANCE AUTHORISATION SCHEME

Advance Authorisation	4.1.3	An Advance Authorisation is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts which are consumed / utilised to obtain export product, may also be allowed. DGFT, by means of Public Notice, may exclude any product(s) from purview of Advance Authorisation.
------------------------------	-------	--

Duty free import of mandatory spares upto 10% of CIF value of Authorisation which are required to be exported / supplied with

resultant product are allowed under Advance Authorisation. Advance Authorisations are issued for inputs and export items given under SION. These can also be issued on the basis of Adhoc norms or self declared norms as per para 4.7 of HBP v1.

Advance Authorisation can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s) for:

- i) Physical exports (including exports to SEZ); and/ or
- ii) Intermediate supplies; and /or
- iii) Supply of goods to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j) of FTP ;
- iv) Supply of 'stores' on board of foreign going vessel / aircraft subject to condition that there is specific SION in respect of item(s) supplied.

In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of FTP, an Advance Authorisation can also be availed by sub-contractor to such project provided name of sub contractor(s) appears in main contract.

Such Authorisation can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and which are paid for in free foreign exchange.

However, Advance Authorization for import of raw sugar, can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s). Exports can also be made by procurement of white sugar from any other factory(ies). This provision shall be applicable for exports from 17.2.2009.

- 4.1.4 Advance Authorisations are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any. However, imports for supplies covered under paragraph 8.2 (h) & (i) will not be exempted from payment of applicable anti-dumping and safeguard duty, if any.

- 4.1.5 Advance Authorisation and / or materials imported thereunder will be with actual user condition. It will not be transferable even after completion of export obligation. However, Authorisation holder will have option to dispose off product manufactured out of duty free inputs once export obligation is completed. In case where CENVAT credit facility on inputs have been availed for the exported goods, even after completion of export obligation, the goods imported against Advance Authorisation shall be utilized only in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer), for which the authorisation holder shall produce a certificate from either the jurisdictional Central Excise Supdt. or Chartered Accountant, at the option of the exporter, at the time of filing application for EODC to RA concerned. However, the actual user condition shall not be applicable in case of raw sugar to be imported from 17.2.2009, till 30.09.2009 under Advance Authorization Scheme.

Further the manufacturing wastes / scrap, as allowed, can be disposed off with the payment of applicable duty even before fulfilment of export obligation.

- 4.1.6 Advance Authorisation necessitates exports with a minimum value addition of 15%, except for items specified in Appendix 11B of HBP v1 and for items in Gems & Jewellery sector, for which value addition would be as per paragraph 4A.2.1 of HBP v.1. Exports to SEZ Units / supplies to Developers / Co-developers, irrespective of currency of realization, would also be covered.

For physical exports for which payments are not received in freely convertible currency, same shall be subject to value addition as specified in Appendix-11 of HBP v1.

In case of Authorisation for import of Tea, minimum value addition under Advance Authorisation shall be 50%.

Similarly, in case of spices {covered by Chapter 9 of ITC(HS)}, duty free import of spices shall be permitted only for value addition purposes like crushing / grinding / sterilization or for manufacture of oils and oleoresins and not for simple cleaning, grading, re-packing etc.

- 4.1.7 Advance Authorisation shall be issued in accordance with Policy and procedure in force on Authorisation issue date.

Validity period of Advance Authorisation for import shall be as prescribed in HBP v1.

**Free of Cost
Supply by Foreign
Buyer**

4.1.8

Facility of Advance Authorisation shall also be available where some or all inputs are supplied free of cost to exporter by foreign buyer.

In such cases, for calculation of value addition, notional value of free of cost inputs along with value of other duty-free inputs shall be taken into consideration. However, if all inputs are supplied free of cost, exporter shall also have option to follow provision prescribed by DoR.

Export Obligation

4.1.9

Period for fulfillment of export obligation under Advance Authorisation shall be as prescribed in HBP v1.

**Provision for
BIFR units**

4.1.9 A

Any firm / company registered with BIFR or any firm / company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed Export Obligation Period (EOP) extension as per rehabilitation package prepared subject to approval of BIFR or 5 years if not specified, without payment of composition fee.

Above provisions apply also to SSI units as per rehabilitation scheme of concerned State government.

**Advance
Authorisation
for Annual
Requirement**

4.1.10

Advance authorisation can also be issued for annual requirement. Imports are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any.

Status Certificate holder and all other categories of exporters having past export performance (in preceding two years) shall be entitled for Advance Authorisation for Annual Requirement.

Entitlement in terms of CIF value of imports shall be upto 300% of the FOB value of physical export and / or FOR value of deemed export in preceding licensing year or Rs 1 crore, whichever is higher.

**Advance Release
Order (ARO) and
Invalidation Letter**

4.1.11

Holder of Advance Authorisation, Advance Authorisation for Annual Requirement and Duty Free Import Authorisation intending to source inputs from indigenous sources / State Trading Enterprises in-lieu of direct import, has option to source them either against Advance Release Order (ARO) or Invalidation letter denominated in free foreign exchange / Indian rupees. However, supplies may be obtained against Authorisation from EOU / EHTP / BTP / STP / SEZ units, without conversion into ARO or Invalidation letter.

Transferee of DFIA shall also be eligible for ARO / Invalidation letter facility.

Validity period of ARO shall be as prescribed in HBP v1.

***Back-to-Back
Inland Letter of
Credit***

4.1.12 Holder of Advance Authorisation, Advance Authorisation for Annual Requirement and DFIA may, instead of applying for an ARO or Invalidation letter, avail of the facility of Back-to-Back Inland Letter of Credit in accordance with procedure specified in HBP v1.

Prohibited Items

4.1.13 Prohibited items of imports mentioned in ITC(HS) shall not be imported under Advance Authorisation / DFIA. Further items reserved for imports by STEs cannot be imported against Advance Authorisation / DFIA. However those items can be procured from STEs against ARO or Invalidation letter.

STEs are also allowed to sell goods on High Sea Sale basis to holders of Advance Authorisation / DFIA holder.

In addition, STEs are permitted to issue "No Objection Certificate (NOC)" for import by advance Authorisation / DFIA holder. Authorisation Holder would be required to file Quarterly Returns of imports effected against such NOC to concerned STE and STE would submit half-yearly import figures of such imports to concerned administrative Department for monitoring with a copy endorsed to DGFT.

Similarly prohibited items of exports mentioned in ITC(HS) shall not be exported under Advance Authorisation / DFIA scheme. Export of restricted items shall be subject to all conditionalities or requirements of Export Authorisation or permission, as may be required, under Schedule II of ITC (HS).

***Admissibility of
Drawback***

4.1.14 In case of an Advance Authorisation, drawback shall be available for any duty paid material, whether imported or indigenous, used in goods exported, as per drawback rate fixed by DoR, Ministry of Finance (Directorate of Drawback). Drawback allowed shall be mentioned in Authorisation.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION (DFIA) SCHEME

Scheme	4.2.1	DFIA is issued to allow duty free import of inputs, fuel, oil, energy sources, catalyst which are required for production of export product. DGFT, by means of Public Notice, may exclude any product(s) from purview of DFIA. This scheme is in force from 1 st May, 2006.
Entitlement	4.2.2	<p>Provisions of paragraph 4.1.3 shall be applicable in case of DFIA. However, these Authorisations shall be issued only for products for which Standard Input and Output Norms (SION) have been notified.</p> <p>In case of post export DFIA, a merchant exporter shall be required to mention only name (s) and address(s) of manufacturer(s) of the export product(s). Applicant is required to file application to concerned RA before effecting exports under DFIA.</p> <p>Pre-export Authorisation shall be issued with actual user condition and shall be exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty / Excise duty, education cess, anti-dumping duty and safeguard duty, if any.</p> <p>In case of actual user DFIA and where CENVAT credit facility on inputs have been availed for the exported goods, even after completion of export obligation, the goods imported against such DFIA shall be utilized in the manufacture of dutiable goods whether within the same factory or outside (by a supporting manufacturer)</p>
Import items	4.2.3	Provisions of paragraphs 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 and 4.1.14 of FTP shall be applicable for DFIA holder.
Value Addition	4.2.4	A minimum 20% value addition shall be required for issuance of such authorisation except for items in gems and jewellery sector for which value addition would be as per paragraph 4A.2.1 of HBP v1. Items for which higher value addition is prescribed under Advance Authorisation Scheme shall be applicable.
Export Obligation	4.2.5	Procedure and time period related to fulfillment of Export Obligation have been laid down in Chapter 4 of HBP v1.
Transferability	4.2.6	Once export obligation has been fulfilled, request for transferability of Authorisation or inputs imported against it may be made before concerned RA. Once, transferability is

endorsed, Authorisation holder may transfer DFIA or duty free inputs, except fuel and any other item(s) notified by DGFT. However, for fuel, import entitlement may be transferred only to companies which have been granted authorisation to market fuel by Ministry of Petroleum and Natural Gas.

Once transferability is endorsed, imports / domestic procurement against authorisation or transfer of imported inputs / domestically procured inputs shall be subject to payment of applicable additional customs duty / excise duty. While endorsing transferability, authorisation would bear a note as to liability of such additional customs duty / excise duty. However, in case where CENVAT facility has not been availed, exemption from additional customs duty / excise duty would be available even after endorsement of transferability on DFIA.

Wherever SIONs prescribe actual user condition and in case of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine, DFIA shall be issued with actual user condition for these inputs and no transferability shall be allowed for these inputs even after fulfillment of export obligation.

However, for authorizations issued prior to 1.4.2007, exemption from Additional Customs Duty/ Excise Duty shall continue to be available even after endorsement of transferability as provided in FTP (RE-2006).

CENVAT Facility 4.2.7

CENVAT credit facility shall be available for inputs either imported or procured indigenously.

DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK (DEPB) SCHEME

Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)

4.3 Objective of DEPB is to neutralise incidence of customs duty on import content of export product. Component of customs duty on fuel (appearing as consumable in the SION) shall also be factored in the DEPB rate. Component of Special Additional Duty shall also be allowed under DEPB(as brand rate) in case of non-availment of CENVAT credit. Neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against export product.

4.3.1 An exporter may apply for credit, at specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency. In case of supply by a DTA unit to a SEZ unit / SEZ Developer/Co-Developer, an exporter may apply for credit for exports made in freely convertible currency or payment made

from foreign currency account of SEZ Unit/SEZ Developer/Co-Developer. In addition, the exporter shall also be entitled for DEPB benefit in case payment is made in Indian Rupees by SEZ Developer/Co-Developer for supplies received w.e.f 10.2.2006.

Credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by DGFT by way of public notice. Credit may be utilized for payment of Customs Duty on freely importable items and/or restricted items. DEPB Scrips can also be utilized for payment of duty against imports under EPCG Scheme. Further, DEPB Scrips can also be used / debited towards payment of customs Duty in case of E.O. defaults for authorizations issued under chapters 4 And 5 of this policy. However, penalty / interest shall be required to be paid in cash.

Prohibited items of exports mentioned in ITC(HS) Book (as amended from time to time) shall not be entitled for DEPB credit except for the exports effected under transitional facility, wherever allowed, in terms of paragraph 1.5 of FTP.

4.3.2 DEPB holder shall have option to pay additional customs duty in cash as well.

Validity 4.3.3 Validity period of DEPB for import shall be as prescribed in HBP v.l.

Transferability 4.3.4 DEPB and / or items imported against it are freely transferable. Transfer of DEPB shall however be for import at specified port, which shall be the port from where exports have been made.

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per terms and conditions of DOR notification.

Applicability of Drawback 4.3.5 Additional customs duty / Excise Duty and Special Additional Duty paid in cash or through debit under DEPB may also be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per DoR

GEMS AND JEWELLERY

<i>Scheme for Gems and Jewellery</i>	4A	Exporters of Gems and Jewellery can import / procure duty free inputs for manufacturing.
<i>Replenishment Authorisation</i>	4A.1	Exporters may obtain Replenishment (REP) Authorisations from RA in accordance with procedure specified in HBP v1.
	4A.1.1	Replenishment authorisation may also be issued for consumables as per paragraph 4A.28 of HBP v1.
<i>Import of Diamonds for Certification / Grading & re-export</i>	4A.2	The authorized offices/agencies in India of Gemological Institute of America (GIA) or any other agency approved in this regard shall be permitted to import diamonds to their laboratories for the purpose of certification/grading reports by them with a condition that the same should be re-exported with the certification/grading reports issued by them without any import duty as per the procedure laid down in HBP v.1
<i>Schemes for Gold/ Silver/ Platinum Jewellery</i>	4A.3	Exporters of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.
<i>Nominated Agencies</i>	4A.4	Nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), the Project and Equipment Corporation of India Ltd (PEC), STCL Ltd, MSTC Ltd, Diamond India Limited (DIL), Gems & Jewellery Export Promotion Council (G&J EPC)), Star Trading House (only for Gems & Jewellery sector) and Premier Trading House under Paragraph 3.10.2 of FTP and any other agency authorised by RBI. Exporters (except EOUs and units in SEZ) may obtain gold / silver / platinum from nominated agency(s).

Procedure for import of precious metal by these agencies (other than those authorized by RBI and the Gems & Jewellery units operating under EOU and SEZ schemes) and the monitoring mechanism thereof shall be as per the provisions laid down in HBP v1 in this regard.

A bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import standard gold bars as per RBI guidelines.

Items of Export

4A.5 Following items, if exported, would be eligible for facilities:

- (a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above;
- (b) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;
- (c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and articles including medallions and coins (excluding legal tender coins and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

Value Addition

4A.6 Value Addition (VA) for gems and jewellery sector shall be as per paragraph 4A.2.1 of HBP v1. It would be calculated as under:

$$VA = \frac{A - B}{B} \times 100, \text{ where}$$

A = FOB value of the export realised / FOR value of supply received.

B = Value of inputs (including domestically procured) such as gold / silver / platinum content in export product plus admissible wastage along with value of other items such as gemstone etc. Wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplier.

Wastage Norms

4A.7 Wastage or manufacturing loss for gold / silver / platinum jewellery shall be admissible as per paragraph 4A.2 of HBP v1.

Export against Supply by Foreign Buyer

4A.8 Where export orders are placed on nominated agencies / status holder / exporters of three years standing having an annual average turnover of Rs. Five Crores during preceding three licensing years, foreign buyer may supply in advance and free of charge, gold / silver / platinum, alloys, findings and mountings of gold / silver / platinum for manufacture and export.

Such supplies can also be in advance and may involve semi-finished jewellery including findings / mountings / components

for repairs / re-make and export subject to minimum value addition of 10%. However, if so imported semi finished gold / silver / platinum jewellery is exported as studded jewellery, value addition of 15% shall be achieved. In such cases of export, wastage of 2% may be permitted.

Exports may be made by nominated agencies directly or through their associates or by status holder / exporter. Import and Export of findings shall be on net to net basis.

**Export Against
Supply by
Nominated
Agencies**

4A.9 Exporter may obtain gold / silver / platinum as an input for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with specified procedure.

**Export Against
Advance
Authorisation**

4A.10 An Advance Authorisation may be granted for duty free import of :

- (a) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;
- (b) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;
- (c) Platinum of fineness not less than 0.900 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

4A.11 Such authorisations shall carry an export obligation to be fulfilled as per procedure specified in paragraph 4A of HBP v1. Value addition shall be as per paragraph 4A.2.1 of HBP v.1.

Advance Authorisation holder may obtain gold / silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct import.

**Gem
Replenishment
Authorisation**

4A.12 Gem Replenishment (Gem & Jewellery REP) Authorisation may be issued as given in paragraph 4A.8, 4A.9 and 4A.10 above.

In case of plain or studded gold / silver / platinum jewellery and articles, value of such Authorisations shall be determined with reference to realisation in excess of prescribed minimum VA.

Such Gem REP Authorisations shall be freely transferable.

**Gem REP Rate
and Item**

4A.13 Replenishment Rate and item of import will be as prescribed in Appendix 12B of HBP v1.

**Export Promotion
Tours/ Export of**

4A.14 Nominated agencies and their associates, with approval of Department of Commerce, and others, with approval of Gem &

Branded Jewellery

Jewellery EPC (GJEPC), may export gold / silver / platinum jewellery and articles thereof for exhibitions abroad.

Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted, subject to conditions as in HBP v1.

**Personal Carriage
of Export / Import
Parcels**

4A.15

Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and import parcels by an Indian importer/foreign national may be permitted as in HBP v1.

Export by Post

4A.16

In case of exports through Foreign Post Office (including via Speed Post), value of jewellery parcels shall not exceed US\$ 75000 and 20 kg. by weight.

**Diamond &
Jewellery Dollar
Accounts**

4A.17

Firms and companies dealing in purchase/ sale of rough or cut and polished diamonds/precious metal jewellery plain, minakari and / or studded with / without diamond and/or other stones, with a track record of at least two years in import or export of diamonds / coloured gemstones/ diamond and coloured gemstones studded jewellery / plain gold jewellery, and having an average annual turnover of Rs. 3 crores or above during preceding three licensing years, may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts (DDA).

Dollars in such accounts available from bank finance and / or export proceeds shall be used only for:

- (i) Import / purchase of rough diamonds from overseas / local sources;
- (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources;
- (iii) Import / purchase of gold from overseas / nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and
- (iv) Transfer to Rupee Account of exporter. Details of this DDA Scheme are given in HBP v1.

A non-DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert same into Rupees within 7 days. Cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non-DDA holder will also be counted towards discharge of his export obligation and / or entitle him to replenishment Authorisation.

<i>Export of cut & Polished precious and semi-precious stones for treatment and re-import</i>	4A.18	Gems and Jewellery exporters shall be allowed to export cut and polished precious and semi-precious stones for the treatment and re-import as per customs rules and regulations. In case of re-export, the exporter shall be entitled for duty drawback as per rules.
<i>Re-import of rejected jewellery</i>	4A.19	Gems & Jewellery exporters shall be allowed to re-import rejected precious metal jewellery as per para 4A.32 of HBP v1.
<i>Export on consignment basis</i>	4A.20	Gems & Jewellery exporters shall be allowed to export diamond, gemstones & jewellery on consignment basis as per HBP v1 and Customs rules and regulations.

CHAPTER 5**EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS (EPCG) SCHEME****Zero duty
EPCG
Scheme**

- 5.1 Zero duty EPCG scheme allows import of capital goods for pre-production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at zero Customs duty, subject to an export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme, to be fulfilled in 6 years reckoned from Authorization issue-date.

The scheme will be available for exporters of engineering & electronic products, basic chemicals & pharmaceuticals, apparels & textiles, plastics, handicrafts, chemicals & allied products, leather & leather products, paper & paperboard and articles thereof, ceramic products, refractories, glass & glassware, rubber & articles thereof, plywood and allied products, marine products, sports goods and toys subject to exclusions as provided in HBP Vol. I.

Validity period for import of capital goods and provision for extension in export obligation period will be as separately provided in the HBP Vol. I. All other provisions pertaining to concessional 3% duty EPCG scheme under this Chapter, to the extent they are not inconsistent with the above provisions of zero duty EPCG scheme, shall be applicable to the zero duty EPCG scheme also. The zero duty EPCG scheme will be in operation till 31.3.2012.

**Concessional
3% Duty
EPCG
Scheme**

- 5.2 Concessional 3% duty EPCG scheme allows import of capital goods for pre-production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at 3% Customs duty, subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme, to be fulfilled in 8 years reckoned from Authorization issue-date.

In case of agro units, and units in cottage or tiny sector, import of capital goods at 3% Customs duty shall be allowed subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods imported, in 12 years from Authorization issue-date.

For SSI units, import of capital goods at 3% Customs duty shall be allowed, subject to fulfillment of export obligation equivalent to 6 times of duty saved on capital goods, in 8 years from Authorization issue-date, provided the landed cif value of such imported capital goods under the scheme does not exceed Rs. 50 lakhs and total investment in plant and machinery after such imports does not exceed SSI limit.

However, in respect of EPCG Authorization with a duty saved amount of Rs. 100 crores or more, export obligation shall be fulfilled in 12 years.

In case CVD is paid in cash on imports under EPCG, incidence of CVD would not be taken for computation of net duty saved, provided the same is not CENVATED.

Capital goods shall include spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, jigs, fixtures, dies and moulds.

Second hand capital goods, without any restriction on age, may also be imported under EPCG scheme.

However, import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owning/operating golf resorts, subject to the condition that:

- (i) total foreign exchange earning from hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in current and preceding three licensing years is Rs. 1.5 crores or more.
- (ii) 'duty saved' amount on all EPCG Authorizations issued in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles/ all purpose vehicles shall not exceed 50% of average foreign exchange earnings from hotel, travel & tourism and golf tourism sectors in preceding three licensing years.
- (iii) vehicles imported shall be so registered that the vehicle is used for tourist purpose only. A copy of the Registration certificate should be submitted to concerned RA as a confirmation of import of vehicle. However, parts of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles such as chassis etc. cannot be imported under the EPCG Scheme.

Import of Restricted items of imports mentioned under ITC(HS) shall only be allowed under EPCG Scheme after approval from EFC at Headquarters.

- 5.2A Spares (including refurbished/reconditioned spares), moulds, dies, jigs, fixtures, tools, refractory for initial lining and catalyst for initial charge; for existing plant and machinery (imported earlier, under EPCG or otherwise), shall be allowed to be imported under the EPCG scheme subject to an export obligation equivalent to 50% of the normal export obligation prescribed in para 5.1 and 5.2 above (for import of capital goods), to be fulfilled in 8 years (6 years for zero duty EPCG scheme), reckoned from Authorization issue date. This would however be subject to the condition that the c.i.f. value of import of the above spares etc. will be limited to 10% of the value of plant and machinery imported under the EPCG scheme. In case of plant and machinery not imported

under the EPCG scheme, c.i.f. value of import of the spares etc. will be limited to 10% of the book value of the plant and machinery.

**EPCG for
Projects**

- 5.2B - An EPCG Authorization can also be issued for import of capital goods under Scheme for Project Imports notified by the Central Board of Excise and Customs under S. No. 441 of Customs Exemption Notification No. 21/2002 dated 01.03.2002.

Export obligation for such EPCG Authorizations would be eight times (6 times for zero duty EPCG scheme) of duty saved. Duty saved would be difference between the effective duty under aforesaid Customs Notification and concessional duty under the EPCG Scheme.

**EPCG for
Retail Sector**

- 5.2C To create modern infrastructure in retail sector, concessional duty benefits under EPCG scheme shall be extended for import of capital goods required by retailers having minimum area of 1000 sq. meters. Such retailer shall fulfill export obligation i.e. 8 times of duty saved, in 8 years.

**EPCG
Authorization
for Annual
Requirement**

- 5.2D EPCG Authorization can also be issued for annual requirement to Status Certificate Holders and all other categories of exporters having past export performance (in preceding two years), both under zero duty and 3% duty Schemes. The annual entitlement in terms of duty saved amount shall be upto 50% of FOB value of Physical Export and / or FOR value of Deemed Export, in preceding licensing year.

Eligibility

- 5.3 EPCG scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s)/ vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers.

Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme also covers a service provider who is designated / certified as a Common Service Provider (CSP) by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export Excellence subject to provisions of Foreign Trade Policy/Handbook of Procedures with the following conditions:-

- (i) EPCG licence to be given to the CSP should have a clear endorsement giving the details of the users and the quantum of Export Obligation (EO) which each user would fulfill;
- (ii) Such exports will not count towards fulfillment of other specific export obligations; and
- (iii) Each one of the users of the CSP apart from the CSP should furnish 100% Bank Guarantee (BG) equivalent to their portion of duty foregone apportioned in terms of quantum of EO to be discharged by them and the B.G. will be enforced in the event of the obligation not being fulfilled.

Conditions for import of Capital Goods	5.4	Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till export obligation is completed.
---	-----	--

Export obligation	5.5	Following conditions shall apply to the fulfillment of the export obligation:-
------------------------------	-----	--

- (i) Export Obligation shall be fulfilled by export of goods manufactured/services rendered by the applicant.

Export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including extended period, if any; except for categories mentioned in paragraph 5.7.6 of HBP Vol. I. Such average would be the arithmetic mean of export performance in the last three years for the same and similar products provided that Premier Trading House (PTH) shall have option of fixing average level of exports based on arithmetic mean of export performance in the last five years instead of three years.

Upto 50% Export Obligation may also be fulfilled by exports of other good(s) manufactured or service(s) provided by the same firm / company, or group company / managed hotel, which has the EPCG authorization. However, EPCG authorizations issued prior to 1.4.2008 will be governed by earlier policy provisions.

However, in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above average exports achieved by the unit / company / group company / managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) / service(s), despite exemptions in Para 5.7.6 of HBP Vol. I.

- (ii) Shipments under Advance Authorization, DFRC, DFIA, DEPB or Drawback scheme, or incentive schemes under Chapter 3 of FTP; would also count for fulfillment of EPCG export obligation.
- (iii) Export obligation can also be fulfilled by the supply of ITA-I items to DTA, provided realization is in free foreign exchange.
- (iv) Exports shall be physical exports. However, deemed exports as specified in paragraph 8.2 (a), (b), (d), (f), (g) & (j) of FTP shall also be counted towards fulfillment of export obligation, alongwith usual benefits available under paragraph 8.3 of FTP.

Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R&D services shall also be counted for discharge under EPCG. Payment received in rupee terms for port handling services, in terms of Chapter 9 of FTP shall also be counted for export obligation discharge.

**Provision for
BIFR units**

5.5.1 Any firm/ company registered with BIFR or any firm/ company acquiring a unit, which is under BIFR, may be allowed EO extension, as per rehabilitation package prepared by operating agency and approved by BIFR/Rehabilitation Department of State Government, upto 12 years if not specified.

Above provisions apply also to SSI units as per rehabilitation scheme of concerned State government.

**EPCG for
agro units**

5.5.2 LUT/Bond or 15% BG (as applicable) may be given for EPCG Authorization granted to units in Agri Export Zones provided EPCG Authorization is taken for export of primary agricultural product(s) notified in Appendix 8 or their value added variants.

**Indigenous
Sourcing of
Capital Goods
and benefits
to Domestic
Supplier**

5.6 A person holding an EPCG Authorization may source capital goods from a domestic manufacturer. Such domestic manufacturer shall be eligible for deemed export benefit under paragraph 8.3 of FTP. Such domestic sourcing shall also be permitted from EOUs and these supplies shall be counted for purpose of fulfillment of positive NFE by said EOU as provided in Para 6.9 (a) of FTP.

**Fixation of
Export
Obligation**

5.7 In case of direct imports, export obligation shall be reckoned with reference to actual duty saved amount. In case of domestic sourcing, export obligation shall be reckoned with reference to notional Customs duties saved on FOR value.

**Technological
Upgradation
of existing
EPCG
machinery**

5.8 EPCG Authorization holders can opt for Technological Upgradation of existing capital good imported under EPCG Authorization.

Conditions governing Technological Up-gradation of existing capital goods are as under:

- (i) Minimum time period for applying for Technological Up-gradation of existing capital goods imported under EPCG is 5 years from Authorization issue-date.
- (ii) Minimum exports made under old capital goods must be 40% of total export obligation imposed on first EPCG Authorization.
- (iii) Export obligation would be re-fixed such that total export obligation mandated for both capital goods would be sum total of 6 times of duty saved on both the capital goods, to be fulfilled in 8 years from new authorization issue-date.

- (iv) Facility for technological up-gradation shall be available only once and the minimum imports to be made shall be at least 10% of the existing investment in plant and machinery by applicant.
- (v) Capital Goods to be imported must be new and technologically superior to earlier CG.

***Incentives for
Fast Track
Companies***

5.9 To incentivize fast track companies with a view to accelerate exports, in cases where Authorization holder has fulfilled 75% or more of specific export obligation and 100% of Average Export Obligation till date, if any, in half or less than half the original export obligation period specified, remaining export obligation shall be condoned and the Authorization redeemed by RA concerned. However no benefits under Para 5.12 of HBP Vol. I shall be available in such cases.

CHAPTER 6**EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs).*****Eligibility***

6.1

Units undertaking to export their entire production of goods and services (except permissible sales in DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronics Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park (STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) Scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, re-engineering and rendering of services. Trading units are not covered under these schemes.

Export and Import of Goods

6.2

- (a) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in ITC(HS).

Procurement and supply of export promotion material like brochure / literature, pamphlets, hoardings, catalogues, posters etc. upto a maximum value limit of 1.5% of FOB value of previous years exports shall also be allowed.

- (b) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may import and /or procure, from DTA or bonded warehouses in DTA / international exhibition held in India, without payment of duty, all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS). Any permission required for import under any other law shall be applicable. Units shall also be permitted to import goods including capital goods required for approved activity, free of cost or on loan / lease from clients. Import of capital goods will be on a self certification basis. Goods imported by a unit shall be with actual user condition and shall be utilized for export production.
- (c) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units. However, in respect of Chrome Ore / Chrome concentrate, State Trading Regime as stipulated in export policy of these items, will be applicable to EOUs.

- (d) EOU / EHTP / STP / BTP units may import / procure from DTA, without payment of duty, certain specified goods for creating a central facility. Software EOU / DTA units may use such facility for export of software.
- (e) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use outside bonded area.
- (f) Gems and jewellery EOUs may source gold / silver / platinum through nominated agencies on loan / outright purchase basis. Units obtaining gold / silver / platinum from nominated agencies, either on loan basis or outright purchase basis shall export gold / silver / platinum within 90 days from date of release.
- (g) EOU / EHTP / STP / BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit / Escrow Rupee Account of buyer subject to RBI clearance, if any.
- (h) Procurement and export of spares / components, upto 5% of FOB value of exports, may be allowed to same consignee / buyer of the export article, subject to the condition that it shall not count for NFE and direct tax benefits.
- (i) BoA may allow, on a case to case basis, requests of EOU / EHTP / STP / BTP units in sectors other than Gems & Jewellery, for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with manufactured article. Such goods may be allowed to be imported / procured from DTA by EOU without payment of duty, to the extent of 5% FOB value of such manufactured articles exported by the unit in preceding financial year. Details of procured / imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents. In such cases, value of procured / imported goods will not be taken into account for calculation of NFE, DTA sale entitlement & profits accruing out of such procured / imported goods will not be eligible for income tax benefits. Such procured / imported goods shall not be allowed to be sold in DTA. BoA may also specify any other conditions.

Second Hand Capital Goods

6.3

Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported duty free.

Leasing of Capital Goods

6.4

a) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may, on the basis of a firm contract between parties, source capital goods from a domestic / foreign leasing company without payment of customs / excise duty. In such a case, EOU / EHTP / STP / BTP unit and domestic / foreign leasing company shall jointly file documents to enable import / procurement of capital goods without payment of duty.

b) An EOU / EHTP / BTP / STP unit may sell capital goods and lease back the same from a Non Banking Financial Company (NBFC), subject to the following conditions:

i) The unit should obtain permission from the jurisdictional Deputy / Assistant Commissioner of Customs or Central Excise, for entering into transaction of 'Sale and Lease Back of Assets', and submit full details of the goods to be sold and leased back and the details of NBFC;

ii) The goods sold and leased back shall not be removed from the unit's premises;

iii) The unit should be NFE positive at the time when it enters into sale and lease back transaction with NBFC;

iv) A joint undertaking by the unit and NBFC should be given to pay duty on goods in case of violation or contravention of any provision of the notification under which these goods were imported or procured, read with Customs Act, 1962 or Central Excise Act, 1944, and that the lien on the goods shall remain with the Customs / Central Excise Department, which will have first charge over the said goods for recovery of sum due from the unit to Government under provision of Section 142(b) of the Customs Act, 1962 read with the Customs (Attachment of Property of Defaulters for Recovery of Govt. Dues) Rules, 1995.

Net Foreign Exchange Earnings

6.5

EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner except for sector specific provision of Appendix 14-I-C of HBP v. 1, where a higher value addition shall be required. NFE Earnings shall be calculated

cumulatively in blocks of five years, starting from commencement of production. Whenever a unit is unable to export due to prohibition / restriction imposed on export of any product mentioned in LoP, the five year block period for calculation of NFE earnings may be suitably extended by BoA. BoA may also consider extension of block period by another one year, for calculation of NFE, on case to case basis, for those units which complete 5 years' block period in between 30.09.2008 and 30.09.2009, keeping in view the decline in exports in that particular unit, due to economic slow down only.

**Letter of Permission /
Letter of Intent and
Legal Undertaking**

6.6

- (a) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by DC / designated officer to EOU / EHTP / STP / BTP unit. LoP / LoI shall have an initial validity of 3 years, by which time unit should have commenced production. Its validity may be extended further up to 3 years by competent authority. However, proposals for extension beyond six years shall be considered in exceptional circumstances, on a case-to-case basis by BoA. Once unit commences production, LoP / LoI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by DC for a period of 5 years at a time.
- (b) LoP / LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority, subject to compliance of provision in para 6.2 above, would be construed as an Authorisation for all purposes.
- (c) Unit shall execute an LUT with DC concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of LoP / LoI / IL / LUT shall render the unit liable to penal action under provisions of the FT (D&R) Act and Rules and Orders made thereunder, without prejudice to action under any other law / rules and cancellation or revocation of LoP / LoI / IL.
- (d) Only projects having a minimum investment of Rs. 1 Crore in plant & machinery shall be considered for establishment as EOUs. However, this shall not apply to existing units and units in EHTP / STP / BTP, Handicrafts / Agriculture / Floriculture / Aquaculture / Animal Husbandry / Information Technology, Services, Brass Hardware and Handmade jewellery sectors. BoA may also allow establishment of EOUs with a lower investment criteria.

Investment Criteria

**Application &
Approvals**

- 6.7 (a) Applications for setting up of units under EOU scheme, other than proposals for setting up of units in services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by BoA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per criteria indicated in HBP v1.
- (b) In other cases, approval may be granted by BoA set up for this purpose as indicated in HBP v 1.
- (c) Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by DC after clearance of proposal by BoA and DIPP within 45 days.
- (d) Applications for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit from existing DTA units, having an investment of Rs. 50 crores and above in plant and machinery or exporting Rs. 50 crores and above annually, shall be placed before BoA for a decision.

**DTA Sale of Finished
Products / Rejects /
Waste / Scrap /
Remnants and By-
products**

6.8

Entire production of EOU / EHTP / STP / BTP units shall be exported subject to following:

- (a) Units, other than gems and jewellery units, may sell goods upto 50% of FOB value of exports, subject to fulfilment of positive NFE, on payment of concessional duties. Within entitlement of DTA sale, unit may sell in DTA, its products similar to goods which are exported or expected to be exported from units. However, units which are manufacturing and exporting more than one product can sell any of these products into DTA, upto 90% of FOB value of export of the specific products, subject to the condition that total DTA sale does not exceed the overall entitlement of 50% of FOB value of exports for the unit, as stipulated above. No DTA sale at concessional duty shall be permissible in respect of motor cars, alcoholic liquors, books, tea (except instant tea), pepper & pepper products, marble and such other items as may be notified from time to time. Such DTA sale shall also not be permissible to units engaged in activities of packaging / labeling / segregation / refrigeration / compacting / micronisation / pulverization / granulation / conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa. Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from Foreign Exchange Account of SEZ unit. Sale to DTA would also be subject

to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs). An amount equal to Anti Dumping duty under section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 leviable at the time of import, shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into DTA from the unit.

- (b) For services, including software units, sale in DTA in any mode, including on line data communication, shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA, subject to fulfillment of positive NFE. In respect of sale of plain jewellery, recipient shall pay concessional rate of duty as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable as applicable.
- (d) Unless specifically prohibited in LoP, rejects within an overall limit of 50% may be sold in DTA on payment of duties as applicable to sale under sub-para 6.8(a) on prior intimation to Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap / waste / remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in DTA, as per SION notified under Duty Exemption Scheme, on payment of concessional duties as applicable, within overall ceiling of 50% of FOB value of exports. Such sales of scrap / waste / remnants shall not be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by norms, DC may fix ad-hoc norms for a period of six months and within this period, norms should be fixed by Norms Committee. Ad-hoc norms will continue till such time norms are fixed by Norms Committee. Sale of waste / scrap / remnants by units not entitled to DTA sale, or sales beyond DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties. Scrap / waste / remnants may also be exported.
- (f) There shall be no duties / taxes on scrap / waste / remnants, in case same are destroyed with permission of Customs authorities.

- (g) By-products included in LoP may also be sold in DTA, subject to achievement of positive NFE, on payment of applicable duties, within the overall entitlement of sub-para 6.8(a). Sale of by-products by units not entitled to DTA sales, or beyond entitlements of sub-para 6.8 (a), shall also be permissible on payment of full duties.
- (h) EOU / EHTP / STP / BTP units may sell finished products, except pepper and pepper products and marble, which are freely importable under FTP in DTA, under intimation to DC, against payment of full duties, provided they have achieved positive NFE. An amount equal to Anti Dumping duty under section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 leviable at the time of import, shall be payable on the goods used for the purpose of manufacture or processing of the goods cleared into DTA from the unit.
- (i) In case of units manufacturing electronics hardware and software, NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.
- (j) In case of DTA sale of goods manufactured by EOU / EHTP / STP / BTP, where basic duty and CVD is nil, such goods may be considered as non-excisable for payment of duty.
- (k) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for first year, except pharmaceutical units where this will be based on its estimated exports for first two years.
- (l) Units in Textile and Granite sectors shall have an option to sell goods into DTA in terms of sub- paras 6.8 (a), (d), (e), (g) and (k) above, on payment of an amount equal to aggregate of duties of excise leviable under section 3 of the Central Excise Act, 1944 or under any other law for the time being in force, on like goods produced or manufactured in India other than in an EOU, subject to the condition that they have not used duty paid imported inputs in excess of 3% of the FOB value of exports of the preceding year and they have achieved positive NFE. Once this option is exercised, the unit will not be allowed to import any duty free inputs for any purpose.

Other Supplies in DTA 6.9

Following supplies effected from EOU / EHTP / STP / BTP units to DTA will be counted for fulfillment of positive NFE:

- (a) Supplies effected in DTA to holders of Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA under duty exemption / remission scheme / EPCG scheme. However, printing sector EOU (or any other sector that may be notified in HBP v 1), can not supply goods, where basic customs duty and CVD is nil or exempted otherwise, to holders of Advance Authorisation / Advance Authorization for annual requirement.
- (b) Supplies effected in DTA against foreign exchange remittance received from overseas.
- (c) Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units, provided that such goods are permissible for procurement in terms of para 6.2 of FTP.
- (d) Supplies made to bonded warehouses set up under FTP and / or under section 65 of Customs Act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange.
- (e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by MoF, as may be provided in HBP v 1.
- (f) Supplies of Information Technology Agreement (ITA -1) items and notified zero duty telecom / electronics items.
- (g) Supplies of items like tags, labels, printed bags, stickers, belts, buttons or hangers to DTA unit for export.
- (h) Supply of LPG produced in an EOU refinery to Public Sector domestic oil companies for being supplied to household domestic consumers at subsidized prices under the Public Distribution System (PDS) Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002, as notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide notification No. E-20029/18/2001-PP dated 28.01.2003 (hereinafter referred to as PDS Scheme) subject to the following conditions:-
 - (a) Only supply of such quantity of LPG would be eligible for which Ministry of Petroleum and Natural Gas declines permission for export and requires the LPG to be cleared in DTA; and

- (b) The Ministry of Finance by a notification has permitted duty free imports of LPG for supply under the aforesaid PDS Scheme.

Export through others

6.10

An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export goods manufactured / software developed by it through another exporter or any other EOU / EHTP / STP / SEZ unit subject to conditions mentioned in para 6.18 of HBP v1.

Entitlement for supplies from the DTA

6.11

- (a) Supplies from DTA to EOU / EHTP / STP / BTP units will be regarded as "deemed exports" and DTA supplier shall be eligible for relevant entitlements under chapter 8 of FTP, besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. Notwithstanding the above, EOU / EHTP / STP / BTP units shall, on production of a suitable disclaimer from DTA supplier, be eligible for obtaining entitlements specified in chapter 8 of FTP. For claiming deemed export duty drawback, they shall get brand rates fixed by DC wherever All Industry Rates of Drawback are not available.

- (b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of Replenishment Authorisations at rates and for items mentioned in HBP v1.

- (c) In addition, EOU / EHTP / STP / BTP units shall be entitled to following:-

- i) Reimbursement of Central Sales Tax (CST) on goods manufactured in India.

Simple interest @ 6% per annum will be payable on delay in refund of CST, if the case is not settled within 30 days of receipt of complete application (as in paragraph 9.10.1 of HBP v1).

- ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on goods procured from DTA on goods manufactured in India.

- iii) Reimbursement of duty paid on fuel procured from domestic oil companies / Depots of domestic oil Public Sector Undertakings as per drawback rate notified by DGFT from time to time. Reimbursement of additional duty of excise levied on fuel under the Finance Acts would also be admissible.

iv) CENVAT Credit on service tax paid:

Other Entitlements

6.12

Other entitlements of EOU / EHTP / STP / BTP units are as under:

- (a) Exemption from Income Tax as per Section 10A and 10B of Income Tax Act.
- (b) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for SSI sector.
- (c) Export proceeds will be realized within 12 months.
- (d) Units will be allowed to retain 100% of its export earning in the EEFC account.
- (e) Unit will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where unit has
 - (i) a turnover of Rs. 5 crores or above;
 - (ii) unit is in existence for at least three years; and
 - (iii) The unit :
 - (a) has achieved positive NFE / export obligation wherever applicable;
 - (b) has not been issued a show cause notice or a confirmed demand, during the preceding 3 years, on grounds other than procedural violations, under the penal provision of the Customs Act, the Central Excise Act, the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, the Foreign Exchange Management Act, the Finance Act, 1994 covering Service Tax or any allied Acts or the rules made thereunder, on account of fraud / collusion / willful mis-statement / suppression of facts or contravention of any of the provisions thereof;
- (f) 100% FDI investment permitted through automatic route similar to SEZ units.

- (g) Units shall pay duty on the goods produced or manufactured and cleared into DTA on monthly basis in the manner prescribed in the Central Excise Rules.

Inter Unit Transfer

- 6.13 (a) Transfer of manufactured goods from one EOU / EHTP / STP / BTP unit to another EOU / EHTP / STP / BTP unit is allowed with prior intimation to concerned DC and Customs authorities, following procedure of in-bond movement of goods. Transfer of manufactured goods shall also be allowed from EOU / EHTP / STP / BTP unit to a SEZ developer or unit following procedure prescribed in SEZ Rules, 2006.
- (b) Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units, with prior intimation to concerned DC and Customs authorities.
- (c) Goods supplied by one unit of EOU / EHTP / STP / BTP to another unit shall be treated as imported goods for second unit for payment of duty, on DTA sale by second unit.

Sub-Contracting

- 6.14 (a) (i) EOU / EHTP / STP / BTP units, including gems and jewellery units, may on the basis of annual permission from Customs authorities, subcontract production processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in DTA.
- (ii) These units may subcontract upto 50% of overall production of previous year in value terms in DTA with permission of Customs authorities.
- (b) (i) EOU may, with annual permission from Customs authorities, undertake job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in name of DTA / EOU. For such exports, DTA units will be entitled for refund of duty paid on inputs by way of brand rate of duty drawback.
- (ii) Duty free import of goods for execution of export order placed on EOU by foreign supplier on jobwork basis, would be allowed subject to condition that no DTA clearance shall be allowed.

- (iii) Subcontracting of both production and production processes may also be undertaken without any limit through other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units, on the basis of records maintained in unit.
- (iv) EOU / EHTP / STP / BTP units may subcontract part of production process abroad and send intermediate products abroad as mentioned in LoP. No permission would be required when goods are sought to be exported from subcontractor premises abroad. When goods are sought to be brought back, prior intimation to concerned DC and Customs authorities shall be given.
- (c) Scrap / waste / remnants generated through job work may either be cleared from job worker's premises on payment of applicable duty on transaction value or destroyed in presence of Customs / Central Excise authorities or returned to unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.
- (d) Sub-contracting / exchange by gems and jewellery EOUs through other EOUs or SEZ units or units in DTA, shall be as per procedure indicated in HBP VI.
- 6.15 (a) In case an EOU / EHTP / STP / BTP unit is unable to utilize goods and services, imported or procured from DTA, it may be
 - (i) transferred to another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit; or
 - (ii) disposed off in DTA with approval of Customs authorities on payment of applicable duties and submission of import authorization; or
 - (iii) exported. Such transfer from EOU / EHTP / STP / BTP unit to another such unit would be treated as import for receiving unit.
- (b) Capital goods and spares that have become obsolete / surplus, may either be exported, transferred to another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit or disposed off in DTA on payment of applicable duties. Benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA only when the unit has achieved positive NFE taking into consideration the depreciation allowed.

Sale of Unutilized Material

No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap / waste / remnants / rejects are destroyed within unit after intimation to Customs authorities or destroyed outside unit with permission of Customs authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

- (c) In case of textile sector, disposal of left over material / fabrics upto 2% of cif value or quantity of import, whichever is lower, on payment of duty on transaction value, may be allowed, subject to certification of Central Excise / Customs officers that these are leftover items.
- (d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

**Reconditioning / Repair
and Re-engineering** 6.16

EOU / EHTP / STP / BTP units may be set up with approval of BoA to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, up-gradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. Provisions of paragraphs 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 of FTP and para 6.28 of HBP v1 shall not, however, apply to such activities.

**Replacement / Repair
of imported /
Indigenous Goods** 6.17

- (a) General provisions of FTP relating to export / import of replacement / repair of goods would also apply equally to EOU / EHTP / STP / BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by DC.
- (b) Goods sold in DTA and not accepted for any reasons, may be brought back for repair / replacement, under intimation to concerned jurisdictional Customs / Central Excise authorities.
- (c) Goods or parts thereof, on being imported / indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently, may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, goods may be brought back from foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. The unit can take free of cost replacement (duty paid) from the authorized agents in India of foreign suppliers, provided the defective part is re-exported or destroyed. However destruction shall not apply to precious and semi precious stones and precious metals.

Exit from EOU Scheme

6.18

- (a) With approval of DC, an EOU may opt out of scheme. Such exit shall be subject to payment of Excise and Customs duties and industrial policy in force.
- (b) If unit has not achieved obligations, it shall also be liable to penalty at the time of exit.
- (c) In the event of a gems and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gems and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by DoC, at price to be determined by that agency.
- (d) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by DC to exit from the scheme at any time on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme for DTA Units. This will be subject to fulfillment of positive NFE criteria under EOU scheme, eligibility criteria under EPCG scheme and standard conditions indicated in HBP v 1.
- (e) Unit proposing to exit out of EOU scheme shall intimate DC and Customs and Central Excise authorities in writing. Unit shall assess duty liability arising out of debonding and submit details of such assessment to Customs and Central Excise authorities. Customs and Central Excise authorities shall confirm duty liabilities on priority basis, subject to the condition that the unit has achieved positive NFE, taking into consideration the depreciation allowed. After payment of duty and clearance of all dues, unit shall obtain "No Dues Certificate" from Customs and Central Excise authorities. On the basis of "No Dues Certificate" so issued by the Customs and Central Excise authorities, unit shall apply to DC for final debonding.

In case there is no proceeding pending under FT(D&R) Act, DC shall issue final debonding order within a period of 7 working days. Between "No Dues Certificate" issued by Customs and Central Excise authorities and final debonding order by DC, unit shall not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or inputs. However, unit can claim Advance Authorisation / DEPB / Duty Drawback. Since the duty calculations and dues are disputed and take a long time, a BG / Bond / Installment processes backed by BG shall be provided for expediting the exit process.

- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machines procured from abroad after payment of applicable import duty, or from domestic market after payment of excise duty, and unit is subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after debonding would be without payment of duty. Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under EPCG Scheme and after completely fulfilling export obligation gets converted into EOU, unit would not be charged customs duty on capital goods at the time of removal of such capital goods in DTA when debonding.
- (g) An EOU / EHTP / STP / BTP unit may also be permitted by DC to exit under Advance Authorization as a one time option. This will be subject to fulfillment of positive NFE criteria.
- Conversion** 6.19 (a) Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit, and Income Tax benefits under Section 10A and 10B will be available for plant, machinery and equipment already installed.
- (b) Existing EHTP / STP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will remain in bond and avail exemptions in duties and taxes as applicable.
- Monitoring of NFE** 6.20 Performance of EOU / EHTP / STP / BTP units shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines in HBP v1.
- Export through Exhibitions / Export Promotion Tours / showrooms abroad / Duty Free Shops** 6.21 EOU / EHTP / STP / BTP are permitted to:
- (i) Export goods for holding / participating in exhibitions abroad with permission of DC.
- (ii) Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.
- (iii) Export goods for display / sale in permitted shops set up abroad.
- (iv) Display / sell in permitted shops set up abroad, or in showrooms of their distributors / agents.
- (v) Set up showrooms / retail outlets at International Airports.
- Personal Carriage of Import / Export Parcels including through** 6.22 Import / export through personal carriage of gems and jewellery items may be undertaken as per Customs procedure. However, export proceeds shall be realized

Foreign bound Passengers		through normal banking channel. Import / export through personal carriage by units, other than gems and jewellery units, shall be allowed provided goods are not in commercial quantity. An authorized person of Gems & Jewellery EOU may also import gold in primary form, upto 10 Kgs in a financial year through personal carriage, as per guidelines prescribed by RBI and DoR.
Export / Import by Post / Courier	6.23	Goods including free samples, may be exported / imported by airfreight or through foreign post office or through courier, as per Customs procedure.
Administration of EOUs / Powers of DC	6.24	Details of administration of EOUs and powers of DC are given in HBP v1.
Revival of Sick Units	6.25	Subject to a unit being declared sick by appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by BoA .
Approval of EHTP / STP	6.26	In case of units under EHTP / STP schemes, necessary approval / permission under relevant paragraphs of this Chapter shall be granted by officer designated by Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology, instead of DC, and by Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BoA.
Approval of BTP	6.27	Bio-Technology Parks (BTP) would be notified by DGFT on recommendations of Department of Biotechnology. In case of units in BTP, necessary approval / permission under relevant provisions of this chapter will be granted by designated officer of Department of Biotechnology.

CHAPTER 7

SPECIAL ECONOMIC ZONES

The policy relating to Special Economic Zones is governed by SEZ Act 2005, and the Rules framed thereunder.

CHAPTER 7 A

FREE TRADE & WAREHOUSING ZONES

The policy relating to Free Trade and Warehousing Zones is governed by SEZ Act 2005, and the Rules framed thereunder.

CHAPTER 8**DEEMED EXPORTS*****Deemed Exports***

- 8.1 “Deemed Exports” refer to those transactions in which goods supplied do not leave country, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange.

Categories of Supply

- 8.2 Following categories of supply of goods by main / sub-contractors shall be regarded as “Deemed Exports” under FTP, provided goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA;
- (b) Supply of goods to EOU / STP / EHTP / BTP;
- (c) Supply of capital goods to EPCG Authorisation holders;
- (d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral Agencies / Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MoF under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those Agencies / Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;

Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral Agencies / Funds as notified by DEA, MoF under ICB, in accordance with procedures of those Agencies / Funds, which bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;
- (e) Supply of capital goods, including in unassembled / disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till stage of commercial production, and spares to extent of 10% of FOR value to fertilizer plants;
- (f) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the MoF, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty;
- (g) Supply of goods to power projects and refineries not covered in (f) above;

- (h) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers-manufacturers) provided said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by customs;
- (i) Supply to projects funded by UN Agencies; and
- (j) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB.

Benefits of deemed exports shall be available under paragraphs (d), (e), (f) and (g) only if the supply is made under procedure of ICB.

However, in regard to mega power projects, the requirement of ICB would not be mandatory, if the requisite quantum of power has been tied up through tariff based competitive bidding or if the project has been awarded through tariff based competitive bidding.

**Benefits for
Deemed Exports**

8.3 Deemed exports shall be eligible for any / all of following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports subject to terms and conditions as in HBP v1:-

- (a) Advance Authorisation / Advance Authorisation for annual requirement / DFIA.
- (b) Deemed Export Drawback.
- (c) Exemption from terminal excise duty where supplies are made against ICB. In other cases, refund of terminal excise duty will be given. Exemption from TED shall also be available for supplies made by an Advance Authorisation holder to a manufacturer holding another Advance Authorization if such manufacturer, in turn, supplies the product(s) to an ultimate exporter.

**Benefits to the
Supplier**

- 8.4.1 (i) In respect of supplies made against Advance Authorisation / DFIA in terms of paragraph 8.2(a) of FTP, supplier shall be entitled to Advance Authorisation / DFIA for intermediate supplies.
- (ii) If supplies are made against Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit issued against Advance Authorisation / DFIA in terms of paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of FTP, suppliers shall be entitled to benefits listed in paragraphs 8.3(b) and (c) of FTP, whichever is applicable.

- 8.4.2 In respect of supply of goods to EOU / EHTP / STP / BTP in terms of paragraph 8.2(b) of FTP, supplier shall be entitled to benefits listed in paragraphs 8.3(a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable.
- 8.4.3 In respect of supplies made under paragraph 8.2(c) of FTP, supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3(a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.
- 8.4.4 (i) In respect of supplies made under paragraphs 8.2(d), (f) and (g) of FTP, supplier shall be entitled to benefits listed in paragraphs 8.3(a), (b) and (c), whichever is applicable.
- (ii) In respect of supplies mentioned in paragraph 8.2(d), supplies to projects funded by such Agencies alone, as may be notified by DEA, MoF, shall be eligible for deemed export benefits. A list of such Agencies / Funds is given in Appendix 13 of HBP.v1.
- (iii) Benefits of deemed exports under para 8.2(f) of FTP shall be applicable in respect of items, import of which is allowed by DoR at zero customs duty, subject to fulfillment of conditions specified under Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time.
- (iv) Supply of Capital goods and spares upto 10% of FOR value of capital goods to power projects in terms of paragraph 8.2(g), shall be entitled for deemed export benefits provided the ICB procedures have been followed at Independent Power Producer (IPP) / Engineering and Procurement Contract (EPC) stage. However, in regard to mega power projects, the requirement of ICB would not be mandatory, if the requisite quantum of power has been tied up through tariff based competitive bidding or if the project has been awarded through tariff based competitive bidding. Benefit of deemed exports shall also be available for renovation / modernization of power plants. Supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable. However, supply of goods required for setting up of any mega power project as specified in S.No. 400 of DoR Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended, shall be

eligible for deemed export benefits as mentioned in paragraph 8.3(a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable; if such mega power project complies with the threshold generation capacity specified therein, in Customs Notification.

Further, supply of goods required for the expansion of existing mega power project as specified in Sl. no 400A of DoR Notification 21/2002- Customs dated 1.3.2002, as amended shall also be eligible for deemed export benefits as mentioned in paragraph 8.3 (a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable.

- (v) Supplies under paragraph 8.2(g) of FTP to new refineries being set up during Ninth Plan period and spilled over to Tenth Plan period, shall be entitled for deemed export benefits in respect of goods mentioned in list 17 specified in S.No. 228 of Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time. Supplier shall be eligible for benefits listed in paragraphs 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable.

8.4.5 In respect of supplies made under paragraph 8.2(e) of FTP, supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable. Benefit of deemed exports shall be available in respect of supplies of capital goods and spares to Fertilizer Plants, which are set up or expanded / revamped / retrofitted / modernized during Ninth Plan period. Benefit of deemed exports shall also be available on supplies made to Fertilizers Plants, which have started in the 8th / 9th Plan periods and spilled over to 10th Plan period.

8.4.6 Supplies of goods to projects funded by UN Agencies covered under para 8.2(i) of FTP are eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of FTP, whichever is applicable.

8.4.7 In respect of supplies made to Nuclear Power Projects under para 8.2(j) of FTP, the supplier would be eligible for benefits given in para 8.3(a), (b) and (c) of FTP, whichever is applicable. Supply of only those goods required for setting up any Nuclear Power Project specified in list 43 at S.No. 401 of Notification No. 21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time, having a capacity of 440MW or more as certified by an officer not below rank of Joint Secretary to Government of India in Department of Atomic Energy, shall be entitled for deemed export benefits in cases where procedure of competitive bidding (and not ICB) has been followed.

***Eligibility for
refund of
terminal excise
duty / drawback***

8.5 Supply of goods will be eligible for refund of terminal excise duty in terms of para 8.3(c) of FTP, provided recipient of goods does not avail CENVAT credit / rebate on such goods. Similarly, supplies will be eligible for deemed export drawback in terms of para 8.3(b) of FTP on Central Excise paid on inputs / components, provided CENVAT credit facility / rebate has not been availed by applicant. Such supplies will however be eligible for deemed export drawback on customs duty paid on inputs / components.

8.5.1 Simple interest @ 6% per annum will be payable on delay in refund of duty drawback and terminal excise duty under deemed export scheme if the case is not settled within 30 days of receipt of complete application (as in paragraph 9.10.1 of HBP v1).

***Supplies to be
made by the
main / sub-
contractor***

8.6.1 In all cases of deemed exports, supplies shall be made directly to designated Projects / Agencies / Units / Advance Authorisation / EPCG Authorisation holders. Sub-contractor may, however, make supplies to main contractor instead of supplying directly to designated projects / Agencies. Such Supplies shall be eligible for deemed export benefits as per procedure laid down in paragraph 8.4 of HBP v1.

8.6.2 Supplies made by an Indian sub-contractor of an Indian or foreign main contractor directly to the designated projects / Agencies, shall also be eligible for deemed export benefits provided sub-contractor is indicated either originally or subsequently in the contract, and payment certificate is issued by project authority in the name of sub-contractor as in Appendix 22C of HBP v1.

CHAPTER 9

DEFINITIONS

- 9.1 For purpose of FTP, unless context otherwise requires, following words and expressions shall have the following meanings attached to them.
- 9.2 "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.
- 9.3 "Act" means Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) [FT(D&R) Act].
- 9.4 "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.
- 9.5 "Actual User (Industrial)" means a person who utilises imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.
- 9.6 "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in
- (i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or
 - (ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or
 - (iii) any service industry.
- 9.7 "AEZ" means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 8 of HBP v1.
- 9.8 "Appeal" is an application filed under section 15 of the Act and includes such applications preferred by DGFT officials in government interest against decision by designated adjudicating / appellate authorities.
- 9.9 "Applicant" means person on whose behalf an application is made and shall, wherever context so requires, includes person signing the application.
- 9.9.1 "Authorisation" means a permission as included in Section 2 (g) of FT(D&R) Act to import or export as per provisions of FTP.
- 9.10 "BoA" means the Board of Approval as notified by DoC.
- 9.11 "BTP" means Biotechnology Park as notified by DGFT on recommendation of Department of Biotechnology.

- 9.12 "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. It also includes packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in services sector.
- 9.13 "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under FTP.
- 9.14 "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to another component.
- 9.15 "Consumables" means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process, will be deemed to be consumables.
- 9.16 "Consumer Goods" means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.
- 9.17 "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from/to India are balanced either by direct imports/exports from importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. Balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.
- 9.18 "Developer" means a person or body of persons, company, firm and such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintains or manages a part or whole of infrastructure and other facilities in SEZ as approved by Central Government and also includes a co-developer.
- 9.19 "Development - Commissioner" means Development Commissioner of SEZ.

- 9.20 "DFRC" means Duty Free Replenishment Certificate (as given in FTP 2004-09).
- 9.21 "Domestic Tariff Area (DTA)" means area within India which is outside SEZs and EOU/ EHTP/ STP/BTP.
- 9.22 "Drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported, means rebate of duty chargeable on any imported material or excisable material used in manufacture of such goods in India. Goods include imported spares, if supplied with capital goods manufactured in India.
- 9.23 "EHTP" means Electronic Hardware Technology Park.
- 9.24 "EOU" means Export Oriented Unit for which an LOP has been issued by Development Commissioner.
- 9.25 "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under Central Excise and Salt Act 1944 (1 of 1944).
- 9.26 "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an IEC number, unless otherwise specifically exempted.
- 9.27 "Export Obligation" means obligation to export product or products covered by Authorisation or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by Regional or competent authority.
- 9.27.1 "FTP" means the Foreign Trade Policy which specifies policy for exports and imports under section 5 of the Act.
- 9.28 "Group Company" means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to —
- (i) exercise twenty-six per cent, or more of voting rights in other enterprise; or
- (ii) appoint more than fifty percent, of members of board of directors in the other enterprise.
- For group companies to claim benefits or have their exports counted for benefits to be claimed by another member of group, the group company should have been in existence at least 2 years prior to date of application under any of export promotion schemes notified in FTP.
- 9.29 "HBP v1" means the Handbook of Procedures (Vol.1) and "HBP v2" means Handbook of Procedures (Vol.2) published under provisions of paragraph 2.4 of FTP.
- 9.30 "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an IEC number, unless otherwise specifically exempted.

- 9.31 "Infrastructure facilities" means industrial, commercial and social infrastructure or any other facility for development of SEZ as notified.
- 9.32 "ITC(HS)" means ITC(HS) Classifications of Export and Import Items Book.
- 9.33 "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to job worker, so as to complete a part of process resulting in manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for aforesaid process.
- 9.34 "Licensing Year" means period beginning on the 1st April of a year and ending on 31st March of following year.
- 9.35 "Managed Hotel" means hotels managed by a three star or above hotel/ hotel chain under an operating management contract for a duration of at least three years between operating hotel/ hotel chain and hotel being managed. Management contract must necessarily cover the entire gamut of operations/ management of managed hotel.
- 9.36 "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling, Re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering. Manufacture, for the purpose of FTP, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.
- 9.37 "Manufacturer Exporter" means a person who exports goods manufactured by him or intends to export such goods.
- 9.38 "MAI" means Market Access Initiative Scheme notified by Department of Commerce.
- 9.39 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.
- 9.40 "NC" means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade, for recommending grant of Authorisations under Duty Exemption Scheme and for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by DGFT.
- 9.41 "NFE" means Net Foreign Exchange.
- 9.42 "Notification" means a notification published in Official Gazette.
- 9.43 "Order" means an Order made by Central Government under the Act.
- 9.44 "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself, and not amenable to further

- disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory.
- 9.45 "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person including the DGFT officials.
- 9.46 "Policy" means FTP 2009-2014 as amended from time to time.
- 9.47 "Prescribed" means prescribed under the Act or the Rules or Orders made thereunder or under FTP.
- 9.48 "Public Notice" means a notice published under provisions of paragraph 2.4 of FTP.
- 9.49 "Raw material" means:
- (i) basic materials which are needed for manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and
 - (ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.
- 9.49.1 "Regional Authority" means authority competent to grant an Authorisation under the Act / Order.
- 9.50 "Registration-Cum-Membership Certificate" (RCMC) means certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council/Commodity Board/Development Authority or other competent authority as prescribed in FTP or HBP v1.
- 9.51 "Rules" means Rules made by Central Government under Section 19 of the Act.
- 9.52 "Services" include all tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.
- 9.53 "Service Provider" means a person providing
- (i) Supply of a 'service' from India to any other country;
 - (ii) Supply of a 'service' from India to service consumer of any other country in India; and
 - (iii) Supply of a 'service' from India through commercial or physical presence in territory of any other country.
 - (iv) Supply of a 'service' in India relating to exports paid in free foreign exchange or in Indian Rupees which are otherwise considered as having being paid for in free foreign exchange by RBI.
- 9.54 "SEZ" means Special Economic Zone notified by Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce.

- 9.55 "Ships" mean all types of vessels used for sea borne trade or coastal trade, and shall include second hand vessels.
- 9.56 "SION" means Standard Input Output Norms notified by DGFT in HBP v2 / approved by Board of Approval.
- 9.57 "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.
- 9.58 "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy through Notification / Public Notice.
- 9.59 "Status holder" means an exporter recognized as Export House/Trading House etc. by DGFT/Development Commissioner.
- 9.59.1 "Stores" means goods for use in a vessel or aircraft and includes fuel and spares and other articles of equipment, whether or not for immediate fitting.
- 9.60 "STP" means Software Technology Park
- 9.61 "Supporting Manufacturer" means any person who manufactures any product or part/accessories/components of that product. Name of supporting manufacturer as well as the exporter must be endorsed on export documents.
- 9.62 "Third-party exports" means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, export documents such as shipping bills shall indicate name of both manufacturing exporter/manufacturer and third party exporter(s). BRC, GR declaration, export order and invoice should be in the name of third party exporter.
- 9.63 "Transaction Value" is as defined in Customs Valuation Rules of Department of Revenue.
- 9.64 "Wild Animal" means any wild animal as defined in Section 2(36) of Wildlife (Protection) Act, 1972.